सुविचार

अंत का इंतजार ही नहीं करना चाहिए, उसका इंतजाम भी करना चाहिए।

-कृष्ण बलदेव वैद

Daily
THE PHOTON NEWS
सच के हक में...

द फोटोन न्यूज Published from Ranchi

Ranchi ● Sunday, 02 November 2025 ● Year : 03 ● Issue : 284 ● Ranchi Edition ● Page : 12 ● Price : ₹3 ● www.thephotonnews.com | E-Paper : epaper.thephotonnews.com

12
Yami Gautam Confirms Haq...

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 VS

जंगल राज में हुए कई नरसंहार, हम बंद चीनी मिलों को करेंगे चालू : अमित शाह

गोपालगंज में चुनावी सभा को केंद्रीय गृह मंत्री ने वर्चुअली किया संबोधित

- यह विधानसभा का चुनाव विधायकों का नहीं, बिहार का तय करेगा भविष्य
- खराब मौसम के कारण पटना से अमित शाह का हेलीकॉप्टर नहीं भर सका उड़ान

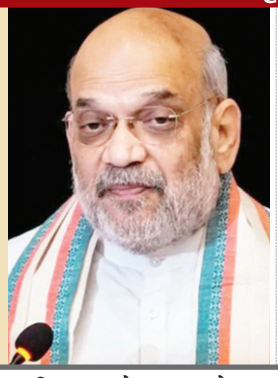

AGENCY GOPALGANJ : शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोपालगंज में वर्चुअली चुनावी जनसभा को संबोधित किया। खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर पटना से उड़ान नहीं भर सका, इसलिए जनता को उन्हें वर्चुअली संबोधित करना पड़ा। अपने संबोधन में शाह ने जंगलराज की याद दिलाई और कहा कि इस दौरान कई नरसंहार हुए। हम बंद पड़े चीनी मिलों को चालू करेंगे। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा खराब मौसम की वजह से रद्द हो गई। गोपालगंज में करीब 5 मिनट के अपने भाषण में शाह ने कहा, पीएम ने बंद पड़ी रीगा चीनी मिल को चालू करने का काम किया है। बिहार की बाकी बंद पड़ी चीनी मिल को अगले 5 सालों में चालू किया जाएगा। विधानसभा का यह चुनाव विधायकों का नहीं, बल्कि विभाग का भविष्य तय करेगा।

थावे जंक्शन का किया जा रहा जीर्णोद्धार

शाह ने कहा, एनडीए सरकार ने गोपालगंज जिले में डुमरिया घाट से पटना तक 2200 करोड़ रुपये की लागत से एक एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया है। हथुआ में 340 करोड़ रुपये की लागत से एक आधुनिक एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का निर्माण किया गया है। गोपालगंज के सबेया हवाई अड्डे पर जल्द ही उड़ान सेवाएं शुरू होंगी। हमने 131 करोड़ रुपएये की लागत से मीरगंज बाईपास सड़क के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। छपरा-गोपालगंज खंड को चार लेन तक विस्तारित करने के लिए काम चल रहा है, और थावे जंक्शन का जीर्णोद्धार किया जा रहा है।

बिहार में चरम पर क्राइम, प्रचार के दौरान हो जा रहा मर्डर, महिलाएं भी असुरक्षित

बेगूसराय में कांग्रेस की महासचिव ने चुनावी सभा को किया संबोधित

- 20 साल से चल रही एनडीए की सरकार ने अब तक नहीं दिए जनता के अधिकार
- एसआईआर के नाम पर मतदाताओं को मौलिक अधिकार से किया जा रहा वंचित

AGENCY BEGUSARAY : शनिवार को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने बेगूसराय के बछवाड़ा में चुनावी सभा की। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। कहा कि बिहार में क्राइम चरम पर है। उद्योगपतियों की भी हत्या हो रही है। चुनाव प्रचार में मर्डर हो रहा है। महिलाएं असुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि 20 सालों से बिहार में एनडीए की सरकार है। आपको आपके अधिकार नहीं दिए गए। सिर्फ बांटने की राजनीति कर देशभर में झूठा राष्ट्रवाद फैलाया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हाल में इन लोगों ने एसआईआर करवाकर 65 लाख वोट काट दिए। इसके कटने का मतलब क्या है। आपके मौलिक अधिकार कट रहे हैं। आपको कमजोर किया जा रहा है। इससे आपको सरकारी फायदे नहीं मिलेंगे। इन लोगों ने हर चीज पर टैक्स लगा रखा है।

नीतीश सरकार के हाथ में अब कुछ नहीं बचा

प्रियंका ने कहा, बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। बच्चों की चिंता है, बेटियों की चिंता है। डर ऐसा है कि कमाने जाना भी चाहें तो नहीं जा सकती हैं। बिहार में नीतीश कुमार के हाथ में कुछ नहीं बचा है। यहां की सरकार दिल्ली से चल रही है। वो लोग जो कहते हैं, नीतीश कुमार वही करते हैं। आप दूसरे शहरों में नौकरी के लिए जाते हैं। घबराहट लेकर आप वहां नौकरी करते हैं। मेरे परिवार का क्या होगा। मेरा परिवार कैसा होगा। उस वक्त आपको बचाने कोई नहीं आता। आपको बिहार की स्थिति बदलनी है तो खुद आगे आना होगा।

सूचना

अपरिहार्य कारणों से आज हमारा साप्ताहिक कॉलम 'नौकरशाही' नहीं जा सका। अगले सप्ताह से नियमित रहेगा।

SARAFA

सोना	:	11,425
चांदी	:	166.00

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

हमने कभी नमाज के वक्त हमला नहीं किया : द्विवेदी

SATNA : शनिवार को भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सतना में थे। वे 53 साल बाद अपने बचपन के स्कूल सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे। आर्मी चीफ ने कहा- ऑपरेशन सिंदूर एक धर्म युद्ध था, यह आगे भी जारी रहेगा। हमने किसी भी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाया, न ही नमाज या किसी भी धार्मिक प्रार्थना के समय हमला किया। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि 1971-72 में चौथी क्लास में इस स्कूल में पढ़े हैं। इतने सालों बाद अपने स्कूल लौटकर वह भावुक हो गए। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा। सिद्धांत और तकनीक के संयोजन से मिशन सफल हुआ। पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि हम धर्म युद्ध के अनुयायी हैं और आगे भी यही नीति अपनाएंगे। स्कूल के दिनों में सीखी निर्णय क्षमता ने उन्हें सेना में कई सफलताएं दिलाईं। चौथी कक्षा में यहीं से निर्णय लेने की क्षमता मिली, इसी ने ऑपरेशन सिंदूर में निर्णायक सफलता दिलाई।

दर्दनाक : एकादशी पर अधिक भीड़ के कारण अचानक टूट गई रेलिंग

आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़, 10 लोगों की मौत

मरने वालों में 8 महिलाएं और 2 बच्चे, 25 से अधिक घायल लोगों का चल रहा है इलाज

SRIKAKULAM @ PTI : शनिवार को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम स्थित काशीबुग्गा वेंकटेश्वर मंदिर में एकादशी के दौरान भगदड़ ने 10 लोगों की जान ले ली। इनमें 8 महिलाएं और 2 बच्चे हैं। 25 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर में आने-जाने का रास्ता एक ही है। भारी भीड़ के दौरान रास्ता जाम हो गया। लोगों की धक्का-मुक्की की वजह से रेलिंग टूट गई। इससे भगदड़ मच गई। घटना के बाद चीख पुकार मच गई। परिजन रोते बिलखते दिखे और अस्पतालों में भारी भीड़ लग गई। एंबुलेंस और बचाव दल मौके पर पहुंचे। शवों और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया। सरकार ने हादसे की जांच का आदेश दे दिया है। श्रीकाकुलम के एसपी केवी महेश्वर रेड्डी ने बताया कि मंदिर के प्रशासक हरिमुकुंद पांडा पर गैर-इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज किया गया है। भगदड़ के कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें मंदिर की सीढ़ियों पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। इनमें महिलाएं, बच्चें और कई बुजुर्ग भी थे। इसी दौरान रेलिंग गिर गई और लोग भीड़ से दबने लगे। महिलाएं और बच्चे बाहर निकलने के लिए चीखते-चिल्लाते दिखे।

- चिल्लाती रहीं महिलाएं और बच्चे, रौंदते हुए आगे बढ़ गए लोग
- मंदिर में आने और जाने के लिए एक ही है रास्ता
- मंदिर के प्रशासक हरिमुकुंद पांडा पर गैर-इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज
- सरकार ने दिया जांच का आदेश

लोगों के ऊपर चढ़कर निकलते दिखे लोग

कई तो अपनी जान बचाने के लिए लोगों के ऊपर चढ़कर निकलते दिखे। वीडियो में लोग भीड़ में दबी महिलाओं और बच्चों को बाहर निकालते दिखे। महिलाएं भगदड़ वाली जगह पर इधर-उधर बेसुध पड़ी दिखाई दीं। लोगों ने भीड़ में से महिलाओं को उनके हाथ-पैर पकड़कर खींचते दिखाई दिए।

मंदिर तक पहुंचाने के लिए 25 सीढ़ियां

आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री अनीता ने बताया कि मंदिर में हर हफ्ते करीब 1500 से 2000 श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। एकादशी होने की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक थी। उन्होंने बताया कि मंदिर पहली मंजिल पर स्थित है और यहां जाने के लिए 20 सीढ़ियां हैं। इसी दौरान धक्का-मुक्की हुई और भगदड़ मच गई। उधर, स्वास्थ मंत्री सत्य प्रकाश ने दावा किया कि 25 हजार से ज्यादा लोग दर्शन के लिए पहुंच गए थे, जबकि मंदिर की क्षमता इतनी नहीं है। जांच में सामने आया है कि एंट्री और एक्जिट एक ही रास्ता था, किसी भी तरह की परमिशन नहीं ली गई थी।

सभी राज्यों की प्रगति में निहित है देश का चहुंमुखी विकास : पीएम मोदी

- विकसित राष्ट्र बनने के अभियान में तेजी से आगे बढ़ रहा भारत
- प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित ब्रह्माकुमारी संस्थान का भव्य शांति शिखर रिट्रीट सेंटर एकेडमी फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड का किया उद्घाटन
- कहा- राष्ट्र को विकसित करने की यात्रा में ब्रह्मकुमारी जैसी संस्थाओं की भी अहम भूमिका

RAIPUR @ PTI : शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्र को विकसित करने की यात्रा में ब्रह्मकुमारी जैसी संस्थाओं की भूमिका अहम है। प्रधानमंत्री ब्रह्मकुमारी के नवा रायपुर के सेक्टर-20 में नवनिर्मित ब्रह्माकुमारी संस्थान के भव्य शांति शिखर रिट्रीट सेंटर एकेडमी फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड के उद्घाटन और रजत महोत्सव समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज का दिन विशेष है, क्योंकि तीनों राज्य अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सभी राज्यों की प्रगति में ही देश का चहुंमुखी मुखी विकास निहित है। इसी मंत्र पर चलते हुए हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के अभियान में जुटे हैं। इस रास्ते पर देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ब्रह्मकुमारी संस्थान से अपने संबंधों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सेवा ही ब्रह्मकुमारी संस्था की पहचान है। इस दौरान राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रह्माकुमारी संस्था के शांति शिखर कार्यक्रम में शामिल होकर छत्तीसगढ़ सहित झारखंड और उत्तराखंड राज्यों के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं।

यहां शब्द कम, सेवा की भावना ज्यादा

प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली आने के बाद भी उन्हें कई अवसरों पर ब्रह्मकुमारी संस्था से जुड़ने का मौका मिला-चाहे वह आजादी के अमृत महोत्सव का अभियान हो या स्वच्छता अभियान। जब भी मैं आपके बीच आया हूं, मैंने आपके प्रयासों को गहराई से महसूस किया है। मोदी ने कहा-यहां शब्द कम, सेवा ज्यादा की भावना है। उन्होंने संस्था से अपने व्यक्तिगत लगाव का भी उल्लेख किया और कहा, इस संस्थान से मेरा अपनापन हमेशा रहा है। जानकी दीदी का स्नेह और राजयोगिनी दादी योगिनी जी का मार्गदर्शन मेरे जीवन की विशेष स्मृतियों में शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने भावनात्मक रूप से कहा, मैं यहां अतिथि नहीं, आपका ही एक सदस्य हूं। मोदी ने देश-विदेश में जुड़े सभी ब्रह्माकुमारी परिवार के सदस्यों को शुभकामनाएं दीं।

रांची में जारी रही धूप और छांव की लुकाछिपी

कमजोर पड़ा चक्रवात 'मोंथा' आज से पूरा साफ होगा मौसम

PHOTON NEWS RANCHI : बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान 'मोंथा' कमजोर पड़ गया है। इससे झारखंड के विभिन्न जिलों में हो रही बारिश रुक गई है। शनिवार को मौसम कुछ साफ हुआ। लेकिन बादल छाए रहे। रविवार से मौसम पूरी तरह साफ होने की संभावना है। यह जानकारी मौसम विभाग में शनिवार को दी। वहीं रांची और आसपास के इलाकों में शनिवार को धूप-छांव की लुकाछिपी जारी रही। पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में सबसे अधिक बारिश धनबाद में 119.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा राज्य के विभिन्न इलाकों में भी बारिश रिकार्ड की गई जिसमें पुटकी में 90.8 मिलीमीटर, बरकट्ठा 86, पालगंज 50, कोनर डीवीसी 48.2, पपकुनी 48.2, पांकी 41 मिमी, तोपचांची 39.8, गढ़वा 38.6, नामकुम 34 मिमी, नंदादीह 33.4, बड़कागांव 33, डुमरी 32.4, मरकच्चो 30 और डाल्टनगंज में 27 .8 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गई।

राजधानी के मिसिरगोंदा स्थित लोहरा कोचा की घटना, कई दिनों से चल रहा था विवाद

अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी को मार डाला

PHOTON NEWS RANCHI : रांची के गोंदा थाना क्षेत्र में पति ने शक की वजह से अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना मिसिरगोंदा स्थित लोहरा कोचा की है। मृतका की पहचान राहिल कच्छप के रूप में की गई है, जबकि आरोपी का नाम शिबू कच्छप है। दोनों के बीच बीते कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि शिबू को अपनी पत्नी राहिल पर शक था कि उसका किसी अन्य व्यक्ति से संबंध है। शुक्रवार की देर रात भी इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर शिबू ने गला दबाकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी।

पड़ोसियों को घटना की जानकारी मिली तो इलाके में मच गई अफरा-तफरी

- तत्काल कार्रवाई करते हुए गोंदा थाना पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
- आपसी संबंधों को लेकर बीते कुछ दिनों से दोनों के बीच चल रहा था विवाद

बस्ती में छिपा रहा आरोपी

हत्या के बाद आरोपी शिबू रातभर बस्ती में ही छिपा रहा। शनिवार सुबह जब पड़ोसियों को घटना की जानकारी मिली तो इलाके में अफरातफरी मच गई। लोगों ने घटना की जानकारी तुरंत गोंदा थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सदर डीएसपी संजीव कुमार बेसरा और थाना प्रभारी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की। कुछ देर बाद आरोपी शिबू को उसी बस्ती से गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि शिबू और राहिल की शादी वर्ष 2011 में हुई थी और पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच लगातार झगड़े होते रहते थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है।

उपलब्धि हाल ही में जारी सीआरईए की रिपोर्ट में किया गया है दावा

तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा भारत का स्वच्छ ऊर्जा मिशन

PHOTON NEWS @ RESEARCH DESK : स्वच्छ ऊर्जा मिशन का मतलब है- एक व्यापक और लक्षित प्रयास, जो प्रदूषणकारी उत्सर्जन को कम करते हुए स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों (जैसे सौर, पवन, और हरित हाइड्रोजन) को बढ़ावा देने, उनका उपयोग बढ़ाने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को कम करना, ऊर्जा की आत्मनिर्भरता बढ़ाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। विशेषज्ञों के अनुसार, ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कम करना जरूरी है। इस दृष्टि से भारत का स्वच्छ ऊर्जा मिशन सही रास्ते पर आगे बढ़ते हुए तेज गति से अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर है। हाल ही में जारी ऊर्जा व स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र (सीआरईए) की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। इससे भविष्य में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। समय से पहले उद्देश्य को हासिल करने के लिए भारत सौर, पवन व हरित हाइड्रोजन के उत्पादन की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रहा है। ऊर्जा की आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास को सही दिशा में बढ़ावा मिल रहा है।

भविष्य में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मिलेगी बड़ी मदद

सौर, पवन व हरित हाइड्रोजन के उत्पादन पर दिया जा रहा विशेष जोर

- ऊर्जा की आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास को सही दिशा में मिला बढ़ावा
- दुनिया में चीन, भारत और इंडोनेशिया कोयला आधारित ऊर्जा उत्पदान के सबसे बड़े बाजार

पेरिस समझौते के बाद कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के प्रमुख चालक भी हैं तीन देश

- 2030 से पहले अपने पावर सेक्टर उत्पादन के शिखर पर पहुंच सकता है भारत
- समय-सीमा से बहुत पहले ही देश ने पार कर लिया है 50 प्रतिशत का आंकड़ा

500 गीगावाट की गैर-जीवाश्म ऊर्जा

इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि चीन, भारत और इंडोनेशिया कोयला आधारित ऊर्जा उत्पदान के सबसे बड़े बाजार हैं। पेरिस समझौते के बाद से वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के प्रमुख चालक भी बने हुए हैं। इन तीनों देशों का स्वच्छ ऊर्जा मिशन के लक्ष्य को हासिल करना पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। नई परिस्थितियों का का विश्लेषण करते हुए रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अगर भारत, चीन और इंडोनेशिया अपनी स्वच्छ ऊर्जा प्रगति बरकरार रखें, तो 2030 से पहले अपने पावर सेक्टर उत्पादन के शिखर पर पहुंच सकते हैं। भारत अगर अपनी 500 गीगावाट की गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य समय पर पूरा कर लेता है, तो देश कोयला बिलजी उत्सर्जन के शिखर पर पहुंच सकता है।

हेमंत सरकार ने विद्यार्थियों के लिए दी सौगात, शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने पर जोर

यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये किए गए मंजूर

PHOTON NEWS RANCHI : हेमंत सरकार उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने पर जोर दे रही है। इसी के मद्देनजर सरकार ने विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत कॉलेजों के विकास तथा नए डिग्री कॉलेजों की स्थापना के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने अलग-अलग योजनाओं के तहत इस राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इनमें कुछ योजनाएं पीएम-उषा कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित हैं। सरकार ने गढ़वा के मेराल में डिग्री कॉलेज के भवन निर्माण के लिए 15 करोड़, जामताड़ा के नाला में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 15.76 करोड़, पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 9.99 करोड़ की राशि स्वीकृत की है।

अलग-अलग योजनाओं के तहत दी गई है राशि की प्रशासनिक स्वीकृति

- स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए नए डिग्री कॉलेजों की स्थापना पर भी सरकार का जोर

सिल्ली में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए मिले 25 करोड़

रांची के सिल्ली में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 25 करोड़, गोड्डा के ठाकुरगंगटी में डिग्री कॉलेज के लिए 39.21 करोड़ तथा गिरिडीह के बगोदर में डिग्री कॉलेज के भवन निर्माण के लिए 1.04 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति प्रदान की है। खूंटी में नए डिग्री महिला कॉलेज के निर्माण के लिए 58 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है। इसी तरह, चतरा स्थित महिला कॉलेज में छात्रावास के निर्माण के लिए 9.98 करोड़ तथा सीबी कॉलेज, बेड़ो के जीर्णाद्धार के लिए 4.10 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। रांची के जेएन कॉलेज, धुर्वा तथा पलामू के जीएल कॉलेज में विद्युतीकरण के लिए क्रमशः 74 लाख एवं 38 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है।

आंखें नम कर गए ख्यातिलब्ध साहित्यकार पद्मश्री प्रो. रामदरश मिश्र, दिल्ली में हुआ अंतिम संस्कार

हिंदी एवं भोजपुरी साहित्य जगत ने सबसे ख्यातिलब्ध साहित्यकारों में से एक पद्मश्री से सम्मानित 101 वर्षीय प्रो. रामदरश मिश्र को शुक्रवार देर रात खो दिया। पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे गोरखपुर के डुमरी गांव के रहनिहार और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेवानिवृत आचार्य ने नई दिल्ली के द्वारिका सेक्टर-7 स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार शनिवार को दिल्ली के मंगलापुरी श्मशान घाट पर किया गया। जहां बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई देने के लिए उमड़े। 15 अगस्त 1924 को गोरखपुर के डुमरी गांव में जन्मे प्रो. रामदरश मिश्र के भाई रामनवल मिश्र भी भोजपुरी के नामी कवि थे। प्रो. मिश्र अपने पीछे पुत्र शशांक और विवेक, पुत्रवधु रीता, सागरिका और माया, पुत्री स्मिता और अंजलि सहित भरापूरा परिवार छोड़ गए हैं।

सीएम ने जताया शोक : प्रो. रामदरश मिश्र के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति बताया। देशभर के साहित्यकारों ने उनके उनके निधन को कभी पूरा नहीं हो सकने वाली क्षति बताया है।

कई सम्मानों से नवाजे गए थे प्रो. मिश्र : प्रो. रामदरश मिश्र साहित्य जगत में अतुलनीय योगदान के लिए साहित्यकार सम्मान (1984), साहित्य भूषण सम्मान (1996), नागरी प्रचारिणी सभा सम्मान (1996), दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान (1998), शलाका सम्मान (2001), महापंडित राहुल सांकृत्यायन सम्मान (2004), भारत भारती सम्मान (2005), साहित्य अकादमी सम्मान (2015) और पद्म श्री (2025) सहित अनगिनत सम्मान से अलंकृत हुए थे।

गोरखपुर से अनुराग की विशेष रिपोर्ट।

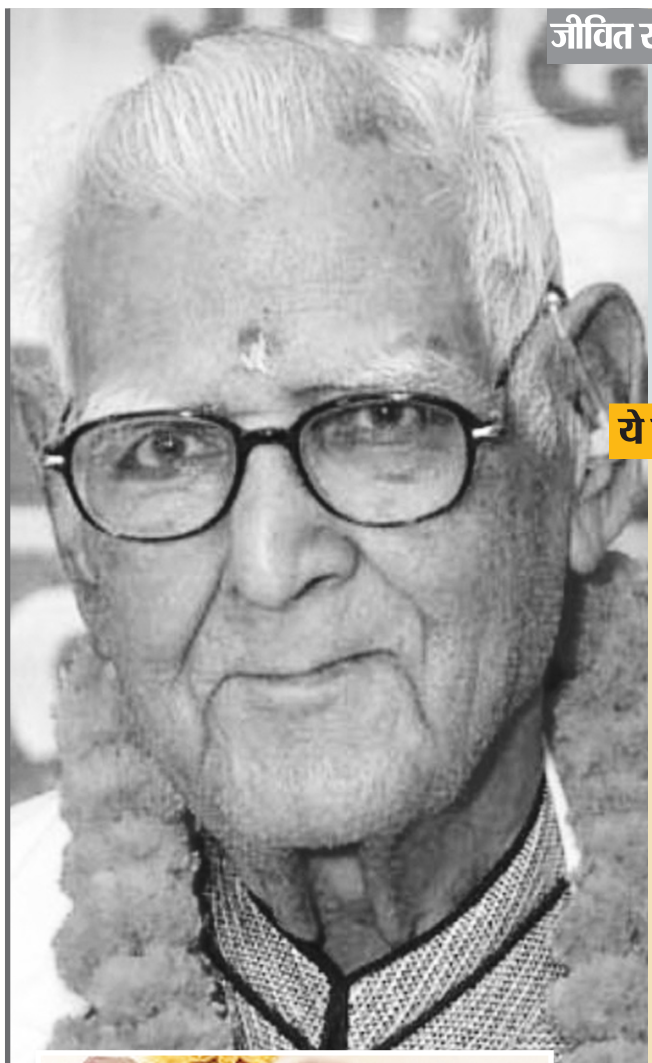

जीवित रहते रचनावली हुई थी प्रकाशित

हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर प्रो. रामदरश मिश्र कविता और गद्य की लगभग सभी विधाओं में समान पकड़ के साथ अपनी कृतियों से अमिट छाप छोड़ने में सफल रहे। उनकी रचनाओं में पूर्वांचल और गोरखपुर की सांस्कृतिक झलक उभरकर सामने आती थी। वे साहित्य जगत के उन चुनिंदा साहित्यकारों में थे, जिनकी रचनावली जीवित रहते हुए प्रकाशित हुई। प्रगतिशील विचारों के साहित्यकार प्रो. रामदरश मिश्र की किताबें 'छायावाद का रचनालोक' और 'हिंदी उपन्यास एक अंतरयात्रा' विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती है।

ये हैं प्रो. मिश्र की प्रमुख कृतियां

प्रो. मिश्र ने लगभग हर विधा में रचना की। उनके प्रमुख उपन्यासों में 'पानी के प्राचीर', 'जल टूटता हुआ', 'सूखता हुआ तालाब', 'अपने लोग', 'रात का सफर', 'आकाश की छत', 'आदिम राग', 'बिना दरवाजे का मकान', 'दूसरा घर', 'थकी हुई सुबह', 'बीस बरस', 'परिवार', 'बचपन भास्कर का', 'एक बचपन यह भी', 'एक था कलाकार' जैसी कृतियां हैं। कहानी संग्रहों में 'खाली घर', 'एक वह', 'दिनचर्या', 'सर्पदंश', 'बसन्त का एक दिन', 'इकसठ कहानियां', 'मेरी प्रिय कहानियां', 'अपने लिए', 'अतीत का विष', 'चर्चित कहानियां', 'श्रेष्ठ आंचलिक कहानियां', 'आज का दिन भी', 'एक कहानी लगातार', 'फिर कब आएंगे?', 'अकेला मकान', 'विदूषक', 'दिन के साथ', 'मेरी कथा यात्रा', 'विरासत', 'इस बार होली में', 'चुनी हुई कहानियां', 'नेता की चादर', 'स्वप्नभंग', 'आखिरी चिट्ठी', 'कुछ यादें बचपन की' (बाल साहित्य) आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा ललित निबंध शैली में 'कितने बजे हैं', 'बबूल और कैक्टस', 'घर-परिवेश', 'छोटे-छोटे सुख', 'नया चौराहा' और आत्मकथा 'सहचर है समय', यात्रावृत में 'घर से घर तक', 'देश-यात्रा' के अलावा डायरी विधा में 'आते-जाते दिन', 'आस-पास', 'बाहर-भीतर', 'विश्वास ज़िन्दा' आदि चर्चित हैं।

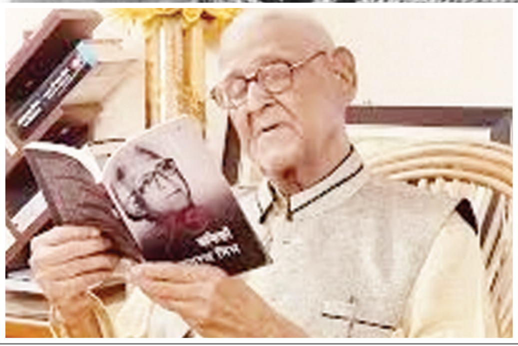

इन रचनाओं को मिली खासी लोकप्रियता

प्रो. रामदरश मिश्र की 'हिंदी आलोचना का इतिहास,' 'ऐतिहासिक उपन्यासकार वृन्दावन लाल वर्मा', 'साहित्य: संदर्भ और मूल्य', 'हिंदी उपन्यास एक अंतर्यात्रा', 'आज का हिंदी साहित्य: संवेदना और दृष्टि', हिंदी कहानी 'अंतरंग पहचान', हिंदी कविता 'आधुनिक आयाम' (छायावादोत्तर हिंदी कविता), 'छायावाद का रचनालोक', 'आधुनिक कविता: सर्जनात्मक संदर्भ', 'हिंदी गद्यसाहित्य: उपलब्धि की दिशाएं' और 'आलोचना का आधुनिक बोध' बेहद लोकप्रिय किताबों में शामिल हैं।

केके बिरला फाउंडेशन का सरस्वती सम्मान प्राप्त करते प्रो. रामदरश मिश्र व साथ में है पद्मश्री प्रो. विश्वनाथ तिवारी।

विभिन्न संगठनों के लिए किया काम

प्रो. मिश्र ने अध्यापन एवं लेखन के साथ-साथ विभिन्न साहित्यिक संगठनों को आगे बढ़ाने का जिम्मा भी बखूबी निभाया और उन्हें मजबूती प्रदान की। वे 1952 से 1955 तक साहित्यिक संघ, वाराणसी के प्रधान सचिव रहे। 1960 से 1964 तक वे गुजरात हिन्दी प्राध्यापक परिषद के अध्यक्ष रहे। 1984 से 1990 तक वे भारतीय लेखक संगठन के अध्यक्ष पद पर रहे। उन्होंने मीमांसा, नई दिल्ली के अध्यक्ष की जिम्मेदारी का भी निर्वहन किया। इसके अलावा वे लंबे समय तक कई मंत्रालयों में हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में कार्य करते रहे।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान करने के बाद स्याही दिखाते प्रो. रामदरश मिश्र जी।

कविता

पद्मश्री प्रो. रामदरश मिश्र
साहित्यकार

हाथ

इस हाथ से मैंने
आगजनी पर कविता लिखी
दंगे पर कहानी
आरक्षण पर लेख लिखा
अयोध्या मसले पर टिप्पणी
आतंकवाद के विरुद्ध हस्ताक्षर-अभियान चलाया
और कनाट-प्लेस में मानव-श्रृंखला बनाई
सम्प्रदायवाद के विरोध में
लेकिन तुम कहाँ छिपे रहे भगोड़े
इस जलते समय में ?
वह चुप रहा
और शायद मेरी चिकनी हथेलियाँ देखता रहा
फिर धीरे-धीरे अपने दोनों हाथ फैला दिए
वे झुलसे हुए थे
वह बोला -
"मैंने एक जलते हुए मकान में से
एक बच्चे को बचाया था
फिर अस्पताल में पड़ा रहा"

इस प्रिय कविता के रचनाकार रामदरश मिश्र को श्रद्धांजलि।

1. हमें अपना फीडबैक, सुझाव या टिप्पणियां देने के लिए दिए गए बार कोड को स्कैन करें या मेल करें।
2. आप हमें अपनी रचनाएं, कविता या आलेख भी भेज सकते हैं। जिसे हम अपने आने वाले अंक पर प्रकाशित करेंगे।

SCAN ME

Email- thephotonnewsjharkhand@gmail.com

स्मृतिशेष

रामदरश मिश्र : लोकचेतना के समर्थ कवि

डॉ. देवेन्द्र नाथ तिवारी

बात इसी फरवरी की है। विश्व पुस्तक मेले की। ठसाठस भीड़। आंखों में झिलमिल करता वह चेहरा। सफेद बालों के बीच से झांकती बालसुलभ मुस्कान। चमकता हुआ ललाट। एक आत्मीयता से भरा हुआ चेहरा। जैसे अपने ही घर-आंगन में खड़ा कोई पुरनिया। कोई ऐसा व्यक्ति जो पहली बार नहीं, सदियों से हमारे बीच रहा हो। कल केशव मोहन पांडेय जी के फेसबुक पोस्ट से पता चला। 'आज सुगना पयान कर गया...।' पर, वह 'सुगना' कौन था? वह थे, पद्मश्री रामदरश मिश्र।

वे नहीं रहे। 31 अक्तूबर, 2025 की दुपहरी को उन्होंने अपने भौतिक शरीर को विदा कहा। महाप्रस्थान किया। पर इससे कहीं बड़ा यह तथ्य है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को, उसके भीतर पलते लोकमन को, अजर कर दिया। वे अपने समय के अंतिम बड़े साक्षी थे। साखी थे। उस समय के जब कविता लोक संवेदना की माटी से उपजती थी, जब शब्द खेत के हल की तरह अनुभूति धरती को चीर कर अंकुरित होते थे।

रामदरश जी का व्यक्तित्व किसी विद्यापीठ के वातानुकूलित कक्ष में नहीं, बल्कि 'कछार' में आकार पाया था। सधे, सुलभ और सहज। उनकी उपस्थिति हमेशा एक करुण-प्रसन्नता का आभास देती थी। वे एक ऐसे लेखक थे, जो अपने शताब्दी पार के जीवन में भी विनम्र रहे। सरल रहे। और सबसे बढ़कर मनुष्य बने रहे। उन्होंने जीकर दिखाया कि साहित्य, केवल शब्दों की जुगाली नहीं, एक जीवंत नैतिक उत्तरदायित्व है।

कछार की माटी लोगों की जीवटता, आत्मीयता और सजलता के लिए जानी जाती है। मैंने स्वयं अपने पितृपक्ष से वहां की माटी की निकटता जानी है। इसलिए कह सकता हूं कि रामदरश जी के व्यक्तित्व में जो अपनापन था, वह कछार की माटी का ही विस्तार था। वे सहज ही लोक की बात करते थे। जैसे बतिया नहीं रहे हों, जीवन का आख्यान सुना रहे हों। उनकी कविताओं में राप्ती-गोर्रा की लहराती लय थी। जो अभी 'प्रदूषित' नहीं हुई हैं। बटोहियों की बोली, बेटियों के गीत, खेतों की सांस, और जीवन की करुण मुस्कान। वे शब्दों में नहीं, हृदय में रहते थे। रामदरश जी की कविताएं केवल पढ़ी नहीं जातीं, अनुभव की जाती हैं। एक पंक्ति में वह पूरा लोक बोल उठता है, जो शहरों की भागदौड़ में विस्मृत हो गया है। वे हमें याद दिलाते थे कि 'भारतीयता' कोई विचार नहीं, एक संवेदना है, जिसका स्रोत लोक है।

उनका कथा-संसार, चाहे 'जलती झाड़ी' हो या 'नयी कहानी' की परंपरा में आया उनका आत्मानुभव, हमेशा उस आम आदमी की आवाज था, जिसे इतिहास अक्सर ओझल कर देता है। वे लेखक होकर भी जन के थे। उन्हें देखकर हमेशा लगता था कि यह व्यक्ति 'साहित्य का महामानव' कम और 'मानवता का गाँव' अधिक है। रामदरश जी ने कभी शिकायती स्वर नहीं उठाया। उनके जीवन का संतुलन ही उनकी प्रतिक्रिया थी। वे चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाते थे। वे अपनी पीढ़ी के अंतिम कवि थे। बिना किसी 'वाद' के, सरोकार के कवि। भोजपुरी में उन्होंने लोक का जो रूपांतरण किया, वह कबीर की परंपरा की नई व्याख्या है। अगर जीवन को एक नदी माना जाए, तो रामदरश मिश्र उसकी अंतधार्रा थे। वह निरंतर बहती रही, शांत, शीतल, और आलोकमय। उनके जाने से हिंदी साहित्य का

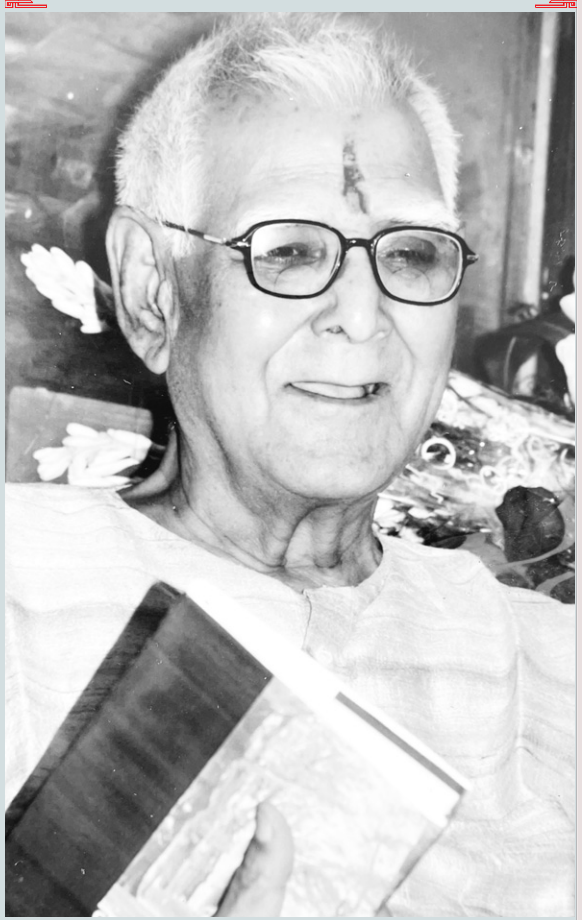

वितान खाली हो गया है। उनका जाना भोजपुरी के वटवृक्ष का गिरना भी है। रामदरश जी हमें छोड़ गए हैं। पर वे जितने दूर हुए, उतने ही हमारे भीतर उतर आए हैं। जब भी पुरुआ बयार चलेगी, जब भी कोई किसान अपनी थकान के बीच मुस्कुराएगा, जब भी कोई छात्र शब्दों के अर्थ में मनुष्य को खोजेगा–वहां, कहीं न कहीं, रामदरश मिश्र मौजूद होंगे। वह इस काल के नहीं, लोकचेतना के समर्थ कवि थे। और लोकचेतना, कभी मरती नहीं। श्रद्धेय मिश्र जी की स्मृतियों प्रणाम।

(लेखक लोक संस्कृति, संचार के अध्येता हैं।)

कविता

पद्मश्री प्रो. रामदरश मिश्र

अच्छा लगा

आज धरती पर झुका आकाश तो अच्छा लगा
सिर किये ऊँचा खड़ी है घास तो अच्छा लगा

आज फिर लौटा सलामत राम कोई अवध में
हो गया पूरा कड़ा बनवास तो अच्छा लगा

था पढ़ाया मांज कर बरतन घरों में रात-दिन
हो गया बुधिया का बेटा पास तो अच्छा लगा

लोग यों तो रोज ही आते रहे, आते रहे
आज लेकिन आप आये पास तो अच्छा लगा

कत्ल, चोरी, रहजनी व्यभिचार से दिन थे मुखर
चुप रहा कुछ आज का दिन खास तो अच्छा लगा

खून से लथपथ हवाएँ खौफ-सी उड़ती रहीं
आँसुओं से नम मिली वातास तो अच्छा लगा

है नहीं कुछ और बस इंसान तो इंसान है
है जगा यह आपमें अहसास तो अच्छा लगा

हँसी हँसते हाट की इन मरमरी महलों के बीच
हँस रहा घर-सा कोई आवास तो अच्छा लगा

रात कितनी भी घनी हो सुबह आयेगी जरूर
लौट आया आपका विश्वास तो अच्छा लगा

आ गया हूँ बाद मुद्दत के शहर से गाँव में
आज देखा चाँदनी का हास तो अच्छा लगा

दोस्तों की दाद तो मिलती ही रहती है सदा
आज दुश्मन ने कहा-शाबाश तो अच्छा लगा।।

BRIEF NEWS

यूथ कनेक्ट उपसमिति की बैठक में युवाओं को चैंबर से जोड़ने पर चर्चा

RANCHI : झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की यूथ कनेक्ट उप समिति की पहली बैठक शनिवार को चैंबर भवन में आयोजित हुई। बैठक में समिति के गठन और पूरे प्रदेश के युवाओं को चैंबर से जोड़ने की दिशा में विस्तृत चर्चा की गई। उप समिति चेयरमैन अमित अग्रवाल ने कहा कि सभी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और संबंधित संगठनों के माध्यम से प्रदेश स्तर पर युवाओं को संगठन से जोड़ा जाएगा ताकि युवा विंग को सशक्त बनाया जा सके और राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। चर्चा के क्रम में यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य में प्रभावशाली युवाओं, कंटेंट क्रिएटर्स और स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित करने की दिशा में विशेष पहल की जाएगी। साथ ही नेशनल स्किल फ्रेमवर्क और स्टार्टअप इंडिया जैसी राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत ठोस कार्य किए जाएंगे ताकि राज्य के युवाओं को स्व-रोजगार के अवसर प्राप्त हों और वे स्थापित हो सके।

आदिवासी नेत्री ने की चेन बेचकर इलाजरत लोगों की मदद

RANCHI : आदिवासी युवा नेत्री ज्योत्सना केरकेट्टा ने संवेदनशीलता का परिचय दिखाया है। वे शनिवार को रिम्स में बीते दिनों बुंडू क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में घायल इलाजरत मरीजों से मुलाकात की और उनके परिजनों को पांच-पांच हजार रुपए की राशि सौंपी। इस अवसर पर ज्योत्सना केरकेट्टा ने कहा कि जिस दिन से घटना घटी है। समाज की दुर्दशा देखकर काफी चिंता हो रही थी। कुछ करने की चाहत में जब पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो उन्होंने अपने पास रखे एक सोने की चेन को बेच दिया और उससे मिले पैसे से रिम्स में इलाजरत लोगों को देकर, उन्हें छोटी सी आर्थिक मदद करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजन और घायलों की हर कोई अपने स्तर से मदद कर रहा है।

श्री रामलला पूजा समिति के डोनेशन कूपन का ड्रॉ आज

RANCHI : श्री राम लला पूजा समिति रांची के सानिध्य में रविवार को की शाम छह बजे डोनेशन कूपन ड्रॉ के माध्यम से उपहार निकाला जाएगा। उल्लेखनीय है कि दशहरा के उपलक्ष्य में श्री रामलला पूजा समिति ने मां दुर्गा के भक्तों के लिए 50 रुपये का सहयोग राशि देकर उपहार योजना डोनेशन कूपन लिया था। समिति के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने बताया कि समिति की ओर से निकाली जाने वाली लॉटरी के नंबर सार्वजनिक किये जायेंगे। साथ ही अखबार के माध्यम से पुरस्कारों के नंबर को भी प्रकाशित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी सहयोग के रुप में 50 रुपया देकर कूपन प्राप्त किया है।

अचानक रिम्स पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, प्रबंधन को दी चेतावनी

किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी लापरवाही

PHOTON NEWS RANCHI : शनिवार को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी अचानक रिम्स पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बुंडू में हुए सड़क हादसे के घायलों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने रिम्स का निरीक्षण भी किया। मरीजों से बात करने के बाद उन्होंने हॉस्पिटल प्रबंधन को चेतावनी दी कि लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना और बेहतर उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की, साथ ही घायलों को व्यक्तिगत स्तर पर मदद भी प्रदान की। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में मारे गए परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी। हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के दौरान व ब्लड बैंक, वार्ड और दवा वितरण केंद्र भी पहुंचे। उन्होंने मरीजों से सीधा संवाद किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रिम्स निदेशक और सुपरिंटेंडेंट को फटकार लगाई। साथ ही कहा कि आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए परिणाम भी बड़े चाहिए। मैं संसाधन उपलब्ध करा रहा हूं। स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि हॉस्पिटल में स्वच्छता, दवा आपूर्ति और मरीजों की शिकायतों के निपटारे में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा अस्पताल जनता की सेवा के लिए हैं, अधिकारियों का आरामगाह नहीं। इसलिए वार्डों में अधिकारी घूमते रहें और मरीजों को देखें कि उन्हें क्या परेशानी हो रही है।

अस्पताल का किया निरीक्षण, बुंडू में हुए सड़क हादसे में घायलों से की मुलाकात

रिम्स का निरीक्षण करते स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी व अन्य

- मृतकों के परिजनों को एक लाख रुपये की दी जाएगी आर्थिक सहायता
- ब्लड बैंक, वार्ड और दवा वितरण केंद्र का मुआयना करने के बाद मरीजों से किया संवाद
- डॉक्टरों को सस्ती दवाएं लिखने का दिया निर्देश

मंत्री ने यह भी कहा

- रिम्स में डायरेक्टर से परमिशन लिए बिना मीडिया कर्मियों को नहीं मिलेगी इंट्री।
- डायरेक्टर को इमरजेंसी व वार्डों से जानकारी लेने का निर्देश, बाहरी दवाएं लिखने वालों को करें चिह्नित।
- ट्रॉमा सेंटर में 120 बेड की कैपेसिटी से ज्यादा मरीजों का हो रहा इलाज।

प्राइवेट हॉस्पिटलों पर होगी कार्रवाई

स्वास्थ्य मंत्री ने प्राइवेट हॉस्पिटलों की मनमानी पर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि कई प्राइवेट हॉस्पिटल 4-5 लाख रुपये वसूलने के बाद मरीज को रिम्स भेज देते हैं, जो गंभीर अपराध है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे हॉस्पिटलों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाएगा, ताकि कोई भी गरीब मरीज पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे।

मेडिकल कालेजों में हाईटेक इक्विपमेंट्स

डॉ. इरफान अंसारी ने यह भी घोषणा की कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में हाईटेक इक्विपमेंट्स की खरीद प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इससे जांच और इलाज की गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को आधुनिक और विश्वसनीय बनाना मेरा संकल्प है। वहीं चाईबासा की घटना पर बोलते हुए उन्होंने राजनीतिक साजिश की आशंका जताई और कहा कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय है। उन्होंने इनडोर में इलाज करा रहे मरीजों से फीडबैक भी लिया।

राज्य के सभी किसानों को मिलेगा मोंथा से हुए नुकसान का लाभ : शिल्पी नेहा तिर्की

फसलों के नुकसान का जायजा लेतीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की व अन्य • फोटोन न्यूज

PHOTON NEWS RANCHI : कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि झारखंड में चक्रवाती तूफान मोंथा से हुए नुकसान का लाभ राज्य के सभी किसानों को दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने फसल बीमा नहीं कराया है उन्हें भी लाभ दिया जाएगा और मुआवजा मिलेगी। मंत्री ने बताया कि इसके लिए आपदा प्रबंधन के तहत प्रति एकड़ तीन हजार रुपये भुगतान का प्रावधान है। भुक्तभोगी किसान अपने अंचल कार्यालय में एक आवेदन देकर योजना का लाभ ले सकते हैं। किसान अपने फसल नुकसान होने संबंधित जानकारी टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल करके भी आसानी से दे सकते हैं। मंत्री शनिवार को चक्रवात से धान की फसल की नुकसान की सूचना पर देवघर जिला के सारवां प्रखंड के जियाखारा पंचायत स्थित रामपुर गांव में बोल रही थीं। इस दौरान उन्होंने प्रभावित किसानों से बातकर फसलों को हुई नुकसान की विस्तार से जानकारी ली। कृषि मंत्री किसानों के खेत भी पहुंची जहां उन्होंने खेतों में फसलों की वास्तविक नुकसान का जायजा लिया। मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में करीब 13 लाख किसानों का बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत निबंधन हुआ है। ये सभी किसान फसल बीमा के दायरे में आएंगे। उनके फसल नुकसान का आकलन बीमा कंपनी करेगी। उन्होंने कहा कि देवघर में इसबार करीब ढाई लाख किसानों ने फसल बीमा में अपना निबंधन कराया है। मौके पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इसके लिए टास्क फोर्स बनाकर अगले तीन से चार दिनों में प्रभावित किसानों का आंकड़ा तैयार करने का निर्देश दिया।

स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर निगम के अपर प्रशासक ने दिए सख्त निर्देश

टीम भावना, स्मार्ट वर्क व कारगर मॉनिटरिंग पर जोर

PHOTON NEWS RANCHI : स्वच्छता सर्वेक्षण-2025 में बेहतर रैंक हासिल करने के लक्ष्य के साथ रांची नगर निगम पूरी तैयारी में जुट गया है। इसी क्रम में अपर प्रशासक संजय कुमार की अध्यक्षता में निगम कार्यालय सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें सभी विभागीय अधिकारी, सफाई निरीक्षक और संबंधित शाखाओं के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और वेस्ट सेग्रिगेशन को और प्रभावी ढंग से लागू करने पर चर्चा हुई। अपर प्रशासक ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए टूलकिट के अनुरूप काम करते हुए हर कंपोनेंट पर फोकस करना होगा। उन्होंने टीम भावना, स्मार्ट वर्क और सख्त मॉनिटरिंग पर जोर दिया। सभी पदाधिकारियों को मल्टी-टास्किंग ढंग से काम करने के निर्देश दिए गए ताकि मिशन स्वच्छ रांची के हर पहलू में प्रगति हो सके। साथ ही बताया गया कि डोर-टू-डोर कलेक्शन, कचरा पृथक्करण, जन-जागरूकता, शौचालयों की स्वच्छता और फीडबैक के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं। अपर प्रशासक ने निर्देश दिया कि गीला और सूखा कचरा स्रोत पर ही पृथक किया जाए।

कचरा फेंकने वालों पर होगा एक्शन

नगर निगम के अपर प्रशासक ने साफ तौर पर कहा कि जो भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान सड़कों या नालियों में कूड़ा फेंकते पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 और झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

तीन होटलों पर लगा जुर्माना

इसी क्रम में अपर प्रशासक ने स्टेशन रोड क्षेत्र का निरीक्षण किया। जांच में कई प्रतिष्ठानों द्वारा सफाई नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिस पर तुरंत कार्रवाई की गई। ऐसे में द एलिमेंट होटल पर 5000, खालसा रेस्टोरेंट पर 2000 और होटल देवरी पर 2000 का जुर्माना लगाया गया। अपर प्रशासक ने शहरवासियों से अपील की कि वे गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। दो डस्टबिन का उपयोग करें और सड़कों पर कचरा न फेंकें। उन्होंने कहा कि स्वच्छ रांची, सुंदर रांची का सपना तभी साकार होगा जब हर नागरिक इसमें सक्रिय भागीदारी निभाएगा।

राजधानी में कोल इंडिया लिमिटेड और सीसीएल का मनाया गया स्थापना दिवस

PHOTON NEWS RANCHI : रांची स्थित सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) मुख्यालय में शनिवार को कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और सीसीएल के 51वां स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें झंडोत्तोलन के बाद कोल इंडिया गीत प्रस्तुत किया गया तथा रंग-बिरंगे गुब्बारे छोड़कर ऊर्जा और एकता के प्रतीक का संदेश भी दिया गया।

कार्यक्रम की शुरूआत मुख्य अतिथि निदेशक (वित्त) पवन कुमार मिश्रा, निदेशक (तकनीकी/संचालन) चंद्र शेखर तिवारी की ओर से शहीद स्मारक पर वीर शहीद कोल श्रमिकों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देने से की गई। इसके बाद पवन कुमार मिश्रा ने कोल इंडिया के तथा चंद्र शेखर तिवारी ने सीसीएल का ध्वज का झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर सीसीएल के सभी क्षेत्रों के ध्वजाओं का झंडोत्तोलन भी किया गया।

पवन कुमार मिश्रा ने इस अवसर पर सभी को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया के कर्मी अपने मूल्यों और परंपराओं को याद करते हुए भविष्य की दिशा तय करते हैं। कोयला, न्यूक्लियर और पेट्रोलियम देश की ऊर्जा के तीन प्रमुख स्रोत हैं, जिनमें से लगभग 80 प्रतिशत योगदान कोयला और कोल इंडिया का है।

एआई फर्जी पोस्ट पर एफआईआर झामुमो की साजिश बेनकाब : भाजपा

PHOTON NEWS RANCHI : घाटशिला विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के खिलाफ सोशल मीडिया पर वायरल किए गए एआई-जनित फर्जी पोस्ट के मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया है। घाटशिला थाने में कांड संख्या 75/2025 के तहत विभिन्न गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया गया है कि इन पोस्ट्स के जरिए बाबूलाल सोरेन की छवि धूमिल करने और मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश की गई। स्वयं सोरेन ने इसे एक 'सोची-समझी साजिश' बताया, जिसका उद्देश्य जनता में बढ़ते उनके समर्थन को रोकना है। इस मामले पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता अजय साह ने शनिवार को कहा कि घाटशिला में अपनी हार को भांपकर झामुमो अब फजीर्वाड़े का सहारा ले रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) आईटी सेल और उससे जुड़े फर्जी हैंडल्स के माध्यम से निरंतर दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। अजय साह ने कहा कि झामुमो सरकार का छह साल का खराब प्रदर्शन जनता देख चुकी है, इसलिए अब वे एआई जनरेटेड झूठ का सहारा लेकर चुनावी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि फर्जी कंटेंट बनाने और प्रसारित करने वालों की शीघ्र पहचान कर कठोर कार्रवाई की जाए और सभी भ्रामक पोस्ट्स को तुरंत हटाया जाए।

श्रद्धापूर्वक मनी देवउठनी एकादशी व तुलसी विवाह

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड की राजधानी रांची सहित विभिन्नस जिलों में शनिवार को तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस दौरान सुहागिन महिलाओं ने दिनभर उपवास रखकर शाम में चुनरी सहित विभिन्न प्रकार के श्रृंगार प्रसाधनों से विधिपूर्वक माता तुलसी की पूजा-अर्चना की और अखंड सौभाग्य की प्रार्थना की। वहीं रांची के कांके रोड स्थित तिरुपति अपार्टमेंट में झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन के संयुक्त महामंत्री संजय सर्राफ के आवास पर देवउठनी एकादशी एवं तुलसी विवाह का आयोजन श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर सर्राफ परिवार के सदस्य सहित अपार्टमेंट के कई श्रद्धालु उपस्थित रहे।

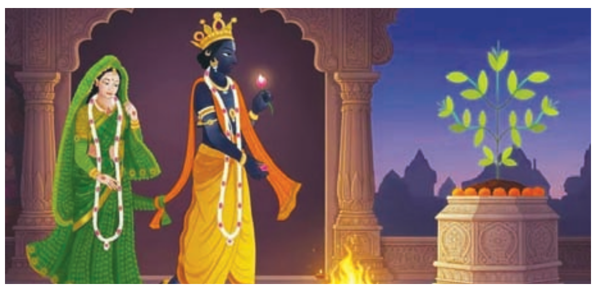

इस पावन अवसर पर अनुराधा सर्राफ ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ एकादशी का व्रत रखा। दिनभर व्रत उपवास कर उन्होंने संध्या के समय पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना, आरती और भोग अर्पित किया। तुलसी माता के पौधे को चुनरी, नारियल, फूल-माला, दीपक और रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया। वातावरण में भक्ति और उत्साह का अद्भुत समावेश देखने को मिला। पूजन के बाद श्री विष्णु भगवान की आरती की गई और तुलसी विवाह का शुभ आयोजन सम्पन्न हुआ। तुलसी माता का विवाह शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु से वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कराया गया। पूजा के दौरान शंख, घंटी और जय जय तुलसी माता और ओम नमो भगवते वासुदेवाय की गूंज से सम्पूर्ण वातावरण आध्यात्मिक बना रहा। उल्लेखनीय है कि देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु चार माह की योगनिद्रा से जागते हैं।

केरल बना देश का पहला अत्यंत गरीबी से मुक्त राज्य : माकपा

PHOTON NEWS RANCHI : माकपा की राज्य इकाई कहा है कि केरल की वाम-जनवादी मोर्चा की सरकार ने केरल से अत्यधिक गरीबी समाप्त कर देश में ही नहीं पूरे दक्षिण एशिया में इतिहास रचने का काम किया है। पार्टी का कहना है कि केरल मॉडल ने पूरे देश को रास्ता दिखाया है। उल्लेखनीय है कि केंद्र की मोदी सरकार ने योजना आयोग को खत्म कर नीति आयोग का गठन किया है। नीति आयोग की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार केरल में 0.7 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। वर्ष 2021 में सत्ता में आयी, माकपा के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में इसे चैलेंज के रुप में लेते हुए यह निर्णय लिया था कि केरल को, अत्यंत गरीबी से मुक्त कराया जाएगा। इसे तय अवधि में पूरा कर लिया गया। इस संबंध में एक वैज्ञानिक और सर्वसमावेशी सर्वे कर राज्य के कुल 64 हजार छह अति गरीब परिवारों को चिन्हित किया गया। मोटे तौर पर ऐसे परिवारों को अत्यंत गरीब माना गया जिनके लिए भोजन, स्वास्थ्य, आजीविका और आवास के पहलुओं से, गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। इसके लिए एक माइक्रो प्लान बनाया गया और सरकारी तंत्र सहित वालंटियर और आम जनता को गोलबंद कर सामाजिक ऑडिट के जरिए इस लक्ष्य को हासिल किया गया। पार्टी की ओर से शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया है कि इसे लेकर केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में समाज के विभिन्न हिस्सों की उपस्थिति में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने उपलब्धि की घोषणा की।

विधि-व्यवस्था

कल सुबह 8 से रात 12 बजे तक भारी मालवाहक वाहनों का शहर में नहीं होगा प्रवेश

गुरु नानक जयंती को लेकर राजधानी के ट्रैफिक रूट में किया गया बदलाव

PHOTON NEWS RANCHI : पांच नवंबर को गुरुनानक जयंती मनाई जाएगी। इस अवसर पर 3 नवंबर को गुरुनानक सत्संग शोभायात्रा निकाली जाएगी। शोभायात्रा को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए रांची जिला प्रशासन और यातायात पुलिस ने शहर में विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। इसके तहत ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। वहीं गाड़ियों की पार्किंग के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए है। 3 नवंबर को सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक भारी मालवाहक वाहनों का शहर में प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। इन वाहनों को केवल रिंग रोड होकर अपने गंतव्य तक जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा नो-इंट्री का पूर्ववत समय भी लागू रहेगा। गुरुनानक सत्संग शोभायात्रा के समय दोपहर 2 बजे से शोभायात्रा की समाप्ति तक रंची वासियों से अपील है कि शोभायात्रा रूट बिड़ला मैदान, मेट्रो गली, दुर्गा मंदिर रोड, न्यू मार्केट चौक, किशोरी यादव चौक, महावीर चौक, शहीद चौक, फिरायालाल चौक, सर्जना चौक, काली मंदिर चौक, वूल हाउस कट, उदू लाईब्रेरी कट, रतन पीपी चौक और सुजाता चौक रूट में आवागमन हेतु कम से कम उपयोग करें। गुरुनानक सत्संग शोभायात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं से अपील की जाती है कि अपने-अपने वाहनों को रामविलास पेट्रोल पंप के बगल सुरजीत मोटर (पंजाबी) गैरेज और रामविलास पेट्रोल पम्प के सामने शारदा नंद बाल मंदिर स्कूल में पार्किंग कर सकते है।

- गाड़ियों की पार्किंग के लिए भी किए गए हैं विशेष इंतजाम
- भारी वाहनों को केवल रिंग रोड होकर अपने गंतव्य तक जाने की होगी अनुमति
- कल निकलेगी सत्संग शोभायात्रा, 5 नवंबर को मनाई जाएगी जयंती

इस प्रकार रहेगा रूट प्लान

- दोपहर 3 बजे से रात 12:00 बजे तक सभी छोटे मालवाहक वाहनों का प्रवेश भी प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में रेडियम चौक से शहीद चौक, फिरायालाल चौक, सर्जना चौक, रतन सिनेमा पी.पी. होते हुए सुजाता चौक तक सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।
- दोपहर 3 बजे से रात्रि 12 बजे तक रेडियम चौक से शहीद चौक, फिरायालाल चौक तक, सर्जना चौक, रतन पीपी होते हुए सुजाता चौक तक सभी प्रभार के वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा। आवश्यकतानुसार अन्य मार्गों को अल्प समय के लिए डायवर्ट और स्टॉप किया जा सकता है।
- दोपहर 2 बजे गुरुनानक सत्संग शोभायात्रा की समाप्ति तक पिस्का मोड से मेट्रो गली, दुर्गा मंदिर, न्यू मार्केट चौक, किशोरी बाबू चौक, महावीर चौक, शहीद चौक तक सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा।
- सुबह 10 बजे से शाम 17 बजे तक मेट्रो गली से बिड़ला मैदान तक सभी प्रकार के वाहनों का (केवल गुरुनानक सतसंग शोभायात्रा में शामिल वाहनों को छोड़कर) परिचालन वर्जित रहेगा।
- शाम 5 बजे तक सुजाता चौक से गुरुनानक पब्लिक स्कूल पीपी कंपाउंड तक गुरुनानक सतसंग शोभायात्रा की समाप्ति तक सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा।
- गुरुनानक सतसंग शोभायात्रा के मद्देनजर सुजाता चौक से मेन रोड की ओर जाने वाले वाहन चालक रतन पीपी से दाएं मुड़कर कर्बला चौक होते हुए अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे।

रेलवे सुरक्षा बल मूरी ने यात्री के छूटे हुए सामान को सही-सलामत लौटाया

PHOTON NEWS RANCHI : कमांडेंट पवन कुमार के निर्देश पर रेलवे सुरक्षा बल के जवान पूरी तत्परता से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और यात्रियों की सहायता भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं यात्रियों को छूटे हुए सामान भी उन्हें सही सलामत लौटाया जा रहा है। 29 अक्टूबर को रेल मदद के माध्यम से रेलवे को सूचना मिली कि ट्रेन संख्या 06056 बरौनी-पोडनूर स्पेशल के कोच संख्या एस-3 में एक यात्री का आईफोन एयरपॉड प्रो छूट गया है। इसका अनुमानित मूल्य 20,000 रुपये है। सूचना प्राप्त होते ही आरपीएफ पोस्ट मूरी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित कोच का निरीक्षण किया। एयरपॉड को बरामद कर सुरक्षित रख लिया। सत्यापन के बाद 31 अक्टूबर को नवी मुंबई के रहने वाले सूर्यकांत यादव को उनकी अमानत एयरपॉड उनके सुपुर्द कर दिया गया। सूर्यकांत ने इसके लिए आरपीएफ मूरी के एएसआई एल सवैयान, कर्मचारी दीपेन तिर्की की सराहना की और धन्यवाद दिया।

तमाड़ में बालिकाओं को दिया गया विधिक जागरूकता का संदेश

RANCHI : शनिवार को तमाड़ के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय सलगाडीह में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) रांची की ओर से लीगल लिट्रेसी क्लास आयोजित की गई। डिप्टी एलएडीसी राजेश कुमार सिन्हा ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और विचार व्यक्त करने के अधिकारों की जानकारी दी। पीएलवी अनीमा मल्लिक ने बाल विवाह को अपराध बताते हुए बालिकाओं से अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने का आह्वान किया। इसी क्रम में जारगो पंचायत भवन में भी विधिक जागरूकता शिविर हुआ, जहां नालसा की योजनाओं साथी, आशा, डॉन, संवाद और जागृति की जानकारी दी। उन्होंने नशा, पोक्सो एक्ट, डायन व दहेज प्रथा पर भी चर्चा की।

BRIEF NEWS

हैदरनगर में दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली

PALAMU : शनिवार की सुबह हैदरनगर हाई स्कूल मैदान में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब दो बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक का नाम नीरज चंद्रवंशी उर्फ मंटू (22 वर्ष) है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नीरज का मकान हाई स्कूल मैदान के ठीक सामने है। घटना सुबह करीब आठ बजे की है। गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की सहायता से जख्मी युवक को फौरन हैदरनगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया गया। यहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डाक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद रेफर कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही हैदरनगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी अभियान चला रही है।

सीसीएल कर्मी ने रेल लाइन पर ट्रेन से कट कर की आत्महत्या

BERMO : बोकारो थर्मल थाना अंतर्गत बरवाबेड़ा तीन पुलवा के पास बरकाकाना गोमोह रेलखंड में जारंगडीह बोकारो थर्मल के बीच पोल संख्या 39/32 रेलवे लाइन में ट्रेन से कट कर सीसीएल कर्मी 32 वर्षीय राकेश कुमार चौहान की मौत हो गई है। राकेश कुमार स्वांग गोविंदपुर फेज टू खुली खदान परियोजना कार्यालय में कार्यरत थे। लोगों ने इसकी सूचना बोकारो थर्मल थाना सहित गोमिया आरपीएफ को दी। सूचना मिलने पर पर बोकारो थर्मल थाना के दरोगा कृष्णा उरांव, सअनि बैजून मरांडी व आरपीएफ गोमिया के विकास कुमार सिंह घटना स्थल पहुंचे। शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम हेतु तेनुघाट भेज दिया गया। सूत्रों के अनुसार मृतक राकेश कुमार चौहान व उसकी पत्नी किरण देवी में शुक्रवार की रात विवाद हुआ था। इसकी शिकायत कथारा ओपी पुलिस को दी गई थी।

सी विजल एप पर करें आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत

JAMSHEDPUR : घाटशिला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप चुनाव में 11 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव कार्य को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए जिला कन्ट्रोल रूम की स्थापना साकची थाना परिसर में की गई है। अगर कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो लोग दूरभाष संख्या 0657-2440111, 0657-2221717, 0657-2221718 पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। यह कंट्रोल रूम प्रतिदिन रात-दिन कार्यरत है। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित वोटर हेल्प लाइन ऐप, सी विजिल ऐप https://voters.eci.gov.in, वोटर हेल्पलाइन टोल फ्री नम्बर 1950 भी शिकायत कर सकते हैं।

प्रिंस खान का नेटवर्क तोड़ने को जमशेदपुर में पुलिस का 'ऑपरेशन लंगड़ा'

लौहनगरी में लगातार बढ़ रहा प्रिंस व सुजीत का नेटवर्क पुलिस के लिए बना चुनौती

MUJTABA RIZVI JSR : यूपी पुलिस ने लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन लंगड़ा शुरू किया था। इस ऑपरेशन की धमक अब जमशेदपुर में भी सुनी जा रही है। सिदगोड़ा इलाके में झारखंड के कुख्यात बदमाश प्रिंस सिंह के शूटर साथ मुठभेड़ में पुलिस ने उसके पैर में गोली मार कर उसे दबोच लिया था। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की थी। इस घटना के बाद जमशेदपुर के बदमाशों में खौफ तारी हो गया है। बदमाश ऑपरेशन लंगड़ा से डरे हुए हैं। माना जा रहा है कि इधर बीच जमशेदपुर में बदमाश एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे कर पुलिस के सामने चुनौती पेश कर रहे थे। मगर, अब जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई शुरू की है तो आपराधिक घटनाओं में कमी आ सकती है। गौरतलब है कि जमशेदपुर में इन दिनों अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। झारखंड के कुख्यात बदमाश प्रिंस सिंह का जमशेदपुर में दखल शुरू हो गया है। भुइयांडीह के रहने वाले कारोबारी हरराम सिंह से दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगे जाने की बड़ी घटना सामने आने के बाद कारोबारियों में दहशत है। इसके अलावा, शहर में कई फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं। जुगसलाई और गोलमुरी में क्षेत्रीय बदमाश सिर उठा रहे हैं। जुगसलाई में शुक्रवार की रात गोलमुरी के दुकानदार जाफर अली पर फायरिंग हुई थी। पुलिस ने इस मामले के तीन आरोपियों शाकिब, हयात और एक अन्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शुक्रवार को ही गोलमुरी में भी गोली चली थी। यहां सागर नामक युवक को गोली लगी थी। इस मामले में पुलिस ने रिंकू नामक अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अब पुलिस ने इन बदमाशों से मुकाबला करने के लिए कमर कस ली है। पुलिस ने आपरेशन लंगड़ा शुरू किया है। जमशेदपुर के कुख्यात बदमाश रवि महानंद को लंगड़ा कर इसकी शुरुआत कर दी गई है।

प्रतीकात्मक फोटो

साल 2021 में शुरू हुआ था ऑपरेशन

सूत्र बताते हैं कि यूपी पुलिस ने वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ऑपरेशन लंगड़ा शुरू किया था। इस ऑपरेशन में यूपी पुलिस की बदमाशों से लगातार मुठभेड़ चल रही है। बताया जा रहा है कि इस आपरेशन की बदौलत यूपी में तस्वीर बदली है। अब वहां भी आपराधिक घटनाओं में कमी आई है।

कदमा का बदमाश भानू माझी प्रिंस खान का है शूटर

लौहनगरी जमशेदपुर में इधर बीच कुख्यात प्रिंस खान का नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है। पहले इस बात का खुलासा हुआ था कि कदमा का बदमाश भानू माझी प्रिंस खान का शूटर है। पुलिस ने धनबाद में इस गिरोह के शूटर भानू माझी को एक पुलिस मुठभेड़ में दबोचा था। उसके पहले जमशेदपुर पुलिस भी भानू माझी के दो शूटरों को कदमा से दबोच चुकी थी। अब प्रिंस सिंह का एक और शूटर सिदगोड़ा से पकड़ा गया है। पता चला है कि इस इलाके में भी प्रिंस सिंह के कई गुर्गे तैयार हुए हैं। यह सब पुलिस के लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैं।

सोशल मीडिया पर चल रहा था बाबूलाल सोरेन का एआई जनित पोस्ट

भाजपा प्रत्याशी का एआई जेनरेटेड पोस्ट वायरल, एफआईआर दर्ज

PHOTON NEWS JSR : घाटशिला उप चुनाव में भाजपा उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनित पोस्ट फेसबुक पर वायरल किया गया है। यह भ्रामक पोस्ट बड़े पैमाने पर फेसबुक पर वायरल है। इस मामले में जिला प्रशासन से शिकायत की गई है। जांच में पाया गया कि किसी ने जानबूझकर प्रत्याशी की छवि बिगाड़ने और उपचुनाव में अपने उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनाने के लिए यह एआई जनरेटेड पोस्ट वायरल किया है। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ घाटशिला थाने में प्राथमिक की दर्ज हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस मामले की शिकायत होने पर घाटशिला उपचुनाव में फ्लाइंग स्क्वायड टीम नंबर एक की मजिस्ट्रेट गालूडीह सिंचाई प्रमंडल की कनीय अभियंता किरण सोरेन ने घाटशिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन की धारा 66 सी, भारतीय दंड संहिता की धारा 300, 223, 356 (2) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में आरोपी का पता लगाया जा रहा है। यह पता लगाया जा रहा है की सबसे पहले फेसबुक पर किसने पोस्ट डाली है। जिसने भी फेसबुक पर पोस्ट डाली है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को पत्र जारी कर कहा था कि उपचुनाव में चुनाव प्रचार को लेकर अगर कोई आई जेनरेटेड भ्रामक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग का निर्देश आने के बाद ही इस मामले में यह पहली शिकायत हुई और प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि मामले में भाजपा के नेताओं की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है।भाजपा नेताओं का आरोप है कि भ्रामक एआई जनित पोस्ट आईटी सेल ने तैयार कराया है।

फाइल फोटो

निगम चुनाव में पालिटेक्निक कॉलेज परिसर में बनेगा ईवीएम स्ट्रांग रूम

DHANBAD : नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। पालिटेक्निक परिसर को चुनावी दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल के रूप में चयनित किया गया है। यहां से ईवीएम मशीनों का डिस्पैच, रिसीविंग एवं मतगणना कार्य संपन्न किया जाएगा। शनिवार को डीसी आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने संयुक्त रूप से धनबाद पालिटेक्निक कालेज परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में दोनों वरीय पदाधिकारियों ने परिसर में स्ट्रांग रूम, मतगणना केंद्र, नियंत्रण कक्ष, सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रवेशनिकास द्वारों की निगरानी प्रणाली को लेकर निरीक्षण किया। रंजन ने कहा की राज्य सरकार द्वारा लगातार निर्देश दिया जा रहा है कि आगामी नगर निगम चुनाव की तैयारियां शुरू करनी हैं। एहतियातन के तौर पर दो-तीन स्थानों का निरीक्षण किया जाएगा ताकि जो बेहतरीन व्यवस्थाएं हो सके वो की जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण है की मतदान कर्मियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

NEWS BOX

कल जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में मनाया जाएगा अधिवक्ता दिवस

PHOTON NEWS JAMSHEDPUR : जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय नया कोर्ट परिसर में लॉयर्स डिफेंस के प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ला से मुलाकात की। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट एवं अधिवक्ताओं की समस्याओं पर चर्चा हुई। और आगामी 3 दिसंबर को हर साल की तरह लॉयर्स डिफेंस इस दिन को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म दिवस के अवसर पर अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस कार्यक्रम में भागीदारी निभाने के लिए वाइस चेयरमैन से विनती की गई। उन्होंने आश्वस्त किया कि वे इस कार्यक्रम में रहेंगे और स्टेट बार काउंसिल की ओर से भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर मदद करेंगे। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में लॉयर डिफेंस के अध्यक्ष अधिवक्ता परमजीत कुमार श्रीवास्त, नवीन प्रकाश, रविंद्र कुमार, अक्षय कुमार झा, अमित कुमार, विनोद कुमार मिश्रा, केशव कुमार सिंह, मिथिलेश सिंह, बसंत कुमार मिश्रा के साथ कई अधिवक्ता मौजूद थे।

उपचुनाव को लेकर ग्रामीण एसपी ने किया क्रिटिकल बूथों का निरीक्षण

PHOTON NEWS JAMSHEDPUR : घाटशिला उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों का प्रचार प्रसार चल रहा है। इसी बीच प्रशासन मतदान की तैयारी में जुटा है। घाटशिला विधानसभा उप चुनाव में मतदान 11 नवंबर को है। इसके लिए प्रशासन ने क्रिटिकल बूथ बनाए हैं। इन क्रिटिकल बूथों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने शनिवार को इन क्रिटिकल बूथों का जायजा लिया। ग्रामीण एसपी ने महीषधारा, बासाडीह, सुंदरडीह, बेहड़ा, रावताड़ा आदि बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां सुविधाओं को देखा। सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया गया।

तारामणि स्मारक विद्यालय में शहीद दामु टुडू का मना शहादत दिवस

PHOTON NEWS GHATSHILA : घाटशिला प्रखंड के तारामणि स्मारक प्लस टू उच्च विद्यालय काड़ाडुबा परिसर में शनिवार को शहीद दामु टुडू का शहादत दिवस मनाया गया। सीआरपीएफ जमशेदपुर की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में हर आम व खास लोगों ने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कंपनी कमांडर मकसूद आलम ने शहीद की पत्नी रता टुडू को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। मकसूद आलम ने उपस्थित लोगों को शहीद दामु टुडू की वीर गाथा सुनाई। जिला परिषद सदस्य देवयानी मुर्मू ने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कहा कि केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल 133 बटालियन का जवान था। आज ही के दिन 1 नवंबर 1997 को मणिपुर में उग्रवादियों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त किया था। उन्होंने कहा कि दामु टुडू दामपाड़ा का गौरव है। शहीद के बलिदान से आज की युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेने की जरूरत है। इस मौके पर सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर सपन कुमार घोष, प्रधानाध्यापिका हेमलता सिंह, मुखिया माही हांसदा, शहीद के पुत्र भोगान टुडू, युगल किशोर टुडू, गुनाराम टुडू, राजा टुडू, सीता टुडू, शुरूबाली टुडू, हेमन टुडू, ईश्वर हांसदा, सुदाम मुर्मू, दुर्गा प्रसाद दंडपात समेत अनेक लोग उपस्थित थे।

जनवरी 2024 से अक्टूबर 2025 तक सड़क हादसों में 76 की मौत

PHOTON NEWS CHAIBASA : जिले में नो-एंट्री विवाद अब जनआंदोलन का रूप ले चुका है। पिछले कई दिनों से शहर का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। सड़क सुरक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे लोगों का दावा है कि बीते एक साल में सड़क दुर्घटनाओं में 155 लोगों की जान गई है। वहीं, जिला प्रशासन ने इस दावे को पूरी तरह गलत बताते हुए कहा है कि जनवरी 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच जिले में सड़क हादसों में सिर्फ 76 लोगों की मौत दर्ज की गई है। प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, हाटगम्हरिया, झींकपानी, टोंटो और मुफस्सिल थाना क्षेत्रों में वर्ष 2024 में जनवरी से दिसंबर तक 23 और जनवरी से जुलाई 2025 के बीच 15 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई। वहीं, चाईबासा–जमशेदपुर मार्ग पर कुजू से बाईपास चौक के बीच एनएच–220 पर 2024 में छह और 2025 में दो लोगों की जान गई। गितिलपी चौक से बाईपास चौक के बीच 2024 में पांच और 2025 में दो मौतें दर्ज की गईं, जबकि गितिलपी चौक से जैंतगढ़ के बीच 2024 में 12 और 2025 में 11 लोगों की मृत्यु सड़क हादसों में हुई है।

घाटशिला में प्रशासन ने जब्त की 2 लाख 41 हजार रुपये कीमत की सामग्री

PHOTON NEWS JAMSHEDPUR : जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर विधानसभा उप निर्वाचन–2025 को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से सम्पन्न कराने के लिए जिले में सघन निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। निगरानी दलों ने शनिवार को चेक नाका पर दो लाख 41 हजार रुपये कीमत की सामग्री जब्त की है। डीसी ने बताया कि अन्तर्राज्यीय व अंतरजिला सीमाओं में बने चेकपोस्ट एवं फ्लाइंग स्क्वायड टीम, घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में वाहनों की जांच एवं सतत कार्रवाई के तहत नकदी, शराब, मादक पदार्थ एवं फ्रीबीज जब्त किए जा रहे हैं। बता दें कि जिले में स्थापित फ्लाइंग स्क्वॉड टीम, स्थैतिक निगरानी दल, आबकारी विभाग, पुलिस विभाग एवं जिला स्तरीय व्यय निगरानी दल द्वारा संयुक्त रूप से सतत कार्रवाई की जा रही है।

अब धनबाद से भी निकलेंगे आईएएस व आईपीएस अधिकारी

- स्टूडेंट्स के लिए शुरू होगी मुफ्त कोचिंग सुविधा, प्रशासन ने संस्थाओं को किया आमंत्रित

PHOTON NEWS DHANBAD : अब धनबाद से भी आईएएस व आईपीएस अधिकारी निकलेंगे। जिला प्रशासन अब संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए कोचिंग शुरू करने जा रहा है। इसके लिए, जानी मानी संस्थाओं को आमंत्रित किया गया है। इसके लिए, जिला प्रशासन का योजना विभाग ने कमर कस ली है। धनबाद के छात्र-छात्राओं को लोक सेवा की नौकरियों की तैयारी करने के लिए अपने जिले से कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा। यह कोचिंग कक्षाएं आरएसपी कालेज बेलगड़ियां में संचालित की जाएंगी। इस संबंध में जिला योजना पदाधिकारी मुकेश बाउरी ने बताया कि पूरा कोर्स छह माह का होगा। दो वर्षों के लिए यह सुविधा संचालित होगी। दो बैच एक साथ संचालित किए जाएंगे। प्रत्येक बैच के लिए 50-50 छात्र-छात्राओं का चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। यानी दो वर्षों के दौरान 200 विद्यार्थियों को यह सुविधा मिलेगी। मुकेश बाउरी ने बताया कि वास्तविक आवश्यकता के आधार पर छात्रों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। यह कक्षाएं केवल आफलाइन मोड पर चलेंगी।

IAS भारत सरकार
IPS Indian Police Service

आईआरसीटीसी का दावा, नो फूड ऑप्शन हटा नहीं, विकल्प चुनने की जगह बदली

- यात्रियों की हायतौबा के बाद आईआरसीटीसी की सामने आई सफाई

PHOTON NEWS DHANBAD : वंदे भारत और शताब्दी जैसी ट्रेनों में ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर नो फूड ऑप्शन चुनने का विकल्प न मिलने से परेशान यात्रियों की लगातार शिकायत के बाद आईआरसीटीसी ने स्थिति साफ की है। आईआरसीटीसी के कंस्लटेंट पब्लिक रिलेशन प्रशांत कुमार पटनायक का कहना है कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान नो फूड ऑप्शन नहीं हटाया गया है। यात्री नो फूड ऑप्शन का चयन नीचे की ओर उस स्थान के ठीक नीचे कर सकते हैं, जहां अपना मोबाइल नंबर डालते हैं तथा अपग्रेड का विकल्प चुनते हैं। रेलवे के आरक्षण केंद्रों के साथ-साथ ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान भी यात्री अपनी मर्जी से खानपान सेवा का चयन कर सकते हैं। राजधानी, शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस के साथ वंदे भारत जैसी ट्रेनों में भी यह सहूलियत दी गई है। पहले ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान नो फूड का ऑप्शन सामने ही दिखता था। अब वेज, नॉनवेज, वेज डायबिटिक, नॉन वेज डायबिटिक और जैन मील जैसे विकल्प सामने दिख रहे हैं। नो फूड ऑप्शन को खोजने में लोगों को कठिनाई हो रही है। आईआरसीटीसी के अनुसार, अदर प्रेफरेंसेज में ऑटो अपग्रेडेशन, बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थस आर अलॉटेड और आइ डॉट वांट फूड/बेवरेज जैसे विकल्प मौजूद हैं। दरअसल, ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान नो फूड ऑप्शन न मिलने के कारण यात्री परेशान हैं। उनका कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग के लिए यात्रा शुल्क वसूला जाता है। उस पर नो फूड का ऑप्शन न मिलने से 300 से 400 तक अधिक चुकाना पड़ रहा है। जबकि रेलवे के आरक्षण काउंटर से टिकट बुक करने पर सेवा शुल्क भी चुकाना नहीं पड़ता और ना ही खान-पान सेवा लेने की बाध्यता है।

नई पहल | मकानों की फोटो डाल कर करनी होगी जियो टैगिंग

पहली बार मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए होगी ऑनलाइन जनगणना

MUJTABA RIZVI JSR : जनगणना साल 2027 में होगी। मगर, इसके पहले सांख्यिकी विभाग इसका प्री टेस्ट कराने जा रहा है। यह प्री टेस्ट मानगो में 10 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा। जनगणना का यह रिहर्सल होगा। इस बार प्रीटेस्ट और जनगणना ऑनलाइन होगी। इसके लिए सरकार ने एक साफ्टवेयर तैयार किया है। प्रगणक इस साफ्टवेयर पर किसी भी परिवार की जानकारी ऑनलाइन भरेंगे। प्रगणक इस साफ्टवेयर को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और अपना मोबाइल नंबर डाल कर खोलेंगे। प्री टेस्ट की तैयारी जोर-शोर से शुरू कर दी गई है। इसके लिए प्रगणकों और सुपरवाइजर की ट्रेनिंग कराई जाएगी। अंतिम जनगणना साल 2010 में ऑफ लाइन हुई थी। तब प्रगणकों को प्रपत्र दिया गया था। इसी प्रपत्र पर उन्होंने परिवार की सारी जानकारी भरी थी। मगर, अब जो जनगणना होने जा रही है, वह ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन जनगणना के चलते अब इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी की शिकायत की संभावना न के बराबर होने की बात कही जा रही है। प्रगणक को परिवार की जानकारी लेने घरों तक जाना होगा। मकान की तस्वीर खींच कर साफ्टवेयर पर अपलोड करनी होगी। इसके अलावा, जियो टैगिंग भी करनी होगी। अगर कोई प्रगणक घर बैठे किसी परिवार की जानकारी साफ्टवेयर में अपलोड करना चाहेगा तो वह जियो टैगिंग नहीं कर पाएगा। उसका साफ्टवेयर बता देगा कि प्रगणक ने यह जानकारी किस जगह बैठ कर भरी है। मकान के पते से इसका मिलान करने पर गड़बड़ी पकड़ में आ जाएगी। बताया जा रहा है कि प्रगणकों को एप्लीकेशन में सभी कॉलम सिलसिलेवार भरने होंगे। वह पहला कॉलम पूरा भर लेगा तभी नीचे वाले कॉलम को भरने के लिए जा सकेगा।

मानगो में सेंसस का प्री टेस्ट 10 से 30 नवंबर तक

साल 2021 में नहीं हो पाई थी जनगणना

जनगणना हर 10 साल में होती है। सरकार ने साल 2021 में जनगणना कराने का खाका तैयार किया था। इसके लिए कोल्हान में गम्हरिया में प्री टेस्ट जनगणना कराई गई थी। मगर, बाद में कोरोना के चलते वर्ष 2021 में जनगणना नहीं हो पाई थी।

पांच नवंबर तक चलेगी ट्रेनिंग

मानगो में 36 वार्ड में प्रीटेस्ट जनगणना कराने की तैयारी है। लगभग 40 प्रगणक और सात सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। इनकी ट्रेनिंग तीन नवंबर से पांच नवंबर तक होगी। ट्रेनिंग के लिए जनगणना निदेशालय से सहायक निदेशक दिलीप कुमार आए हैं। मानगो में जनगणना के प्री टेस्ट का काम जिला सांख्यिकी अधिकारी कराएंगे। जिला सांख्यिकी अधिकारी अपर जिला जनगणना अधिकारी होते हैं। इसके अलावा, जिला जनगणना अधिकारी एडीसी होते हैं। जबकि, जिले के डीसी प्रधान जिला जनगणना अधिकारी होते हैं।

जिला सांख्यिकी अधिकारी बनाए गए डीसीएलआर

जमशेदपुर में जिला सांख्यिकी अधिकारी का पद कई महीने से खाली था। अब जब जिले में जनगणना का प्री टेस्ट होना है तो सरकार ने इस पद पर तैनाती कर दी है। फिलहाल, डीसीएलआर सच्चिदानंद महतो को जिला सांख्यिकी अधिकारी का भी चार्ज दिया गया है। इस संबंध में सरकार का आदेश जारी हो गया है। सोमवार को डीसीएलआर सच्चिदानंद महतो जिला सांख्यिकी अधिकारी का भी चार्ज ले सकते हैं।

BRIEF NEWS

बेमौसम हुई बरसात से धान की फसल हो गई नष्ट

PURNIA : प्रखंड क्षेत्र में लगातार कई दिनों से हो रही बे मौसम की बरसात से धान की फसले बर्बाद हो गई।भारी बारिश से किसानों में मातम छा गया है। बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान का असर अमौर प्रखंड क्षेत्र में व्यापक रूप से देखने को मिल रहा है। लगातार कई दिनों से हो रही बारिश से धान की फैसले बर्बाद हो गई। धान की फसले बर्बाद होते देख किसान मायूस हो गए हैं । किसानों ने बताया कि कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से सैकड़ो एकड़ में लगे धान की तैयार फसलें बर्बाद हो गई है। किसानों ने प्रशासन से फसल क्षति मुआवजे की मांग की है। मांग करने वालों में मो अजमल, मौजम, समसूल हुदा, नाजिम, अजमुद्दीन, अंजर, इलियास, शेख रसूल, वीरेंद्र शाह, रवि साह, शमसुद्दीन, शे रईस आदि शामिल है।

नाथनगर में लोजपा प्रत्याशी का जनसंपर्क अभियान तेज

BHAGALPUR : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर के नाथनगर में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। क्षेत्र के एनडीए समर्थित लोजपा प्रत्याशी मिथुन कुमार लगातार जनसंपर्क में जुटे हैं। शनिवार को उन्होंने सबौर सहित दर्जनों गांवों का दौरा कर लोगों से आशीर्वाद और समर्थन मांगा। इस दौरान ग्रामीणों, महिलाओं और युवाओं ने उनका स्वागत किया। जगह-जगह फूल-मालाओं से अभिनंदन किया गया। लोगों ने कहा कि मिथुन कुमार जमीनी नेता हैं, जो जनता की समस्याओं को करीब से जानते हैं और उनके समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में मिथुन कुमार जिला परिषद अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं।

नालंदा जिले की सातों विधानसभा में पूरक रैंडमाइजेशन संपन्न

NALANDA : जिला मुख्यालय समाहरणालय सभागार में आज शनिवार को निर्वाचन पदाधिकारी - सह - जिला पदाधिकारी, नालन्दा की अध्यक्षता में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के निमित्त नालन्दा जिलान्तर्गत सातो विधानसभा यथा -171 अस्थावां, 172- बिहारशरीफ, 173- राजगीर (अ.जा), 174- इस्लामपुर, 175- हिलसा,176- नालन्दा एवं 177- हरनौत विधानसभा क्षेत्र के लिए इवीएम बीयु एणड सीयु तथा वीवीपैट के पूरक रैंडमाइजेशन सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्षों/सचिवों की उपस्थिति में सफलतापूर्वक कार्य सम्पन्न किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, नालन्दा, नोडल पदाधिकारी इवीएम कोषांग, नालन्दा, उप निर्वाचन पदाधिकारी, नालन्दा, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, आई टी प्रबंधक, नालन्दा, सहित राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, बीजेपी, लोजपा, कांग्रेस, बसपा पार्टी के अध्यक्ष/सचिव उपस्थित थे।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करने की अपील

लालू राज में नहीं थे उद्योग, आज जीडीपी में उद्योग का योगदान 23% : सम्राट चौधरी

AGENCY PATNA : बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को बनियापुर, परबत्ता और तारापुर विधानसभा क्षेत्रों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया और जनसम्पर्क अभियान चलाया। जनसभा के दौरान उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और लोगों से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करने की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस बिहार में लालू राज के दौरान उद्योग पूरी तरह समाप्त हो गए थे, आज उसी बिहार की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 23 प्रतिशत हिस्सेदारी उद्योग क्षेत्र की है। बिहार में देश का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट, सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट और सबसे ज्यादा थर्मल पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा, ₹ मैं आपसे वादा करता हूं कि हमारी सरकार फिर बनने पर बिहार में अगले पांच साल में 50 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा। हमने यह वादा अपने संकल्प पत्र के माध्यम से भी किया है। सारण जिले के बनियापुर विधानसभा क्षेत्र से राजग उम्मीदवार केदारनाथ सिंह (भाजपा) और परबत्ता विधानसभा से राजग उम्मीदवार बाबूलाल शौर्य (लोक जनशक्ति पार्टी-रामविलास) के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार की सड़कें बदहाल थीं। तब सड़क में गड्ढा था या गड्ढे में सड़क, यह कहना मुश्किल था। पटना पहुंचने में पांच घंटे लगते थे, आज डेढ़ घंटे में सफर पूरा हो जाता है। अब हर गांव तक सड़क और बिजली पहुंच चुकी है। 23 से 24 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है, वह भी 125 यूनिट मुख्त बिजली के साथ। चौधरी ने बताया कि बिहार अब बुनियादी विकास से आगे बढ़कर औद्योगिक विकास के नए युग में प्रवेश कर चुका है।

जनसभा को संबोधित करते उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

यह जनसमर्थन बता रहा है कि अबकी बार बिहार से राजग बाहर : अखिलेश यादव

PATNA : समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को बिहार के दरभंगा में बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित किया और केंद्र तथा राज्य की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पर निशाना साधा। जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये जनसमर्थन और जोश बता रहा है कि अबकी बार बिहार से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस्तमाली पार्टी है, वो इस्तेमाल करने के बाद लोगों को बर्बाद करती है। उन्होंने कहा कि लोग पलायन की बात कर रहे हैं, आप ही बताओ आज बिहार में पलायन क्यों है? वास्तव में यह भाजपा की वजह से है। बिहार की जनता इस बार भाजपा का पलायन कराने जा रही है और तेजस्वी नौकरी देने जा रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि हमे खुशी है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अवध में भजपा हराने का काम किया है, इस बार मगध में भी हार होने जा रही है। अखिलेश ने सोने के दाम को लेकर भाजपा पर निशाना साधा।

लालू और नीतीश कुमार के शासन में कोई अंतर नहीं : प्रशांत किशोर

AGENCY PATNA : बिहार में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार पर हमला बोला है। अपने रोड शो के दौरान शनिवार को उन्होंने लालू यादव और नीतीश कुमार के शासन में कोई अंतर नहीं बताया। उन्होंने दोनों ही सरकारों पर आम जनता का शोषण करने का आरोप लगाया।

विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राजगीर, हिलसा, नालंदा, बिहारशरीफ और अस्थावां विधानसभा क्षेत्रों में प्रशांत किशोर ने रोड शो किया। प्रशांत ने आज राजगीर से अपने भव्य रोड शो और जनसंपर्क अभियान की शुरूआत की। राजगीर के कलाली मोड़ से शुरू हुआ रोड शो सिलाव बाइपास, नेपुरा मोड़ होते हुए नालंदा मोड़ तक पहुंचा। इसके बाद बेन बाजार में प्रशांत किशोर ने जनसंवाद किया और हिलसा, नूरसराय होते हुए बिहारशरीफ पहुंचे। यहां देवीसराय मोड़ से क्लॉक टावर, अतवारी बाजार होते हुए सोहसराय मोड़ तक रोड शो किया और स्थानीय उम्मीदवार दिनेश कुमार के लिए लोगों से समर्थन मांगा।

इससे पहले बिहारशरीफ में प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बात करते हुए राज्य में कानून-व्यवस्था के सवाल को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू यादव के जिस जंगलराज को हटाकर नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, अब फिर से लगभग वैसा ही माहौल बन गया है। भले ही अब अपहरण-रंगदारी जैसा अपराध ज्यादा न हो रहा हो, लेकिन नीतीश सरकार में अधिकारियों का जंगलराज चल रहा है।

उन्होंने राजग के घोषणा पत्र पर कहा कि यह समय अब घोषणा करने का नहीं, 20 साल के शासन का हिसाब देने का है। नीतीश कुमार ने साल 2005 में जब बिहार की सत्ता संभाली थी, तब भी बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में था और आज उनके 20 साल के शासन के बाद भी देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल है।

मैथिली ठाकुर की सभा में उमड़ा जनसैलाब नदियामी पंचायत में भी दिखा अभूतपूर्व उत्साह

AGENCY DARBHANGA : बैका पंचायत के मदरिया गांव स्थित मथुरा नाथ महादेव मंदिर प्रांगण शनिवार को अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर के समर्थन में आयोजित जनसभा के दौरान जनसैलाब में बदल गया।

रिमझिम बारिश के बावजूद सैकड़ों ग्रामीण, विशेषकर महिलाएं और बच्चे, घंटों पहले से ही मंदिर प्रांगण में डटे रहे। भीगी धरती और छातों की कतारों के बीच वातावरण मैथिली ठाकुर ज़िंदाबाद! मोदी ज़िंदाबाद! के नारों से गूंज उठा।

महिलाओं का उत्साह और बच्चों की मासूम प्रतीक्षा दृश्य मन मोह लेने वाला था। बारिश में भी भीगते हुए सभी समर्थक मंच की ओर निहारते रहे। सभा स्थल पर भारी संख्या में मीडिया कर्मियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और जीवंत बना दिया।

कार्यक्रम में भाजपा जिला महामंत्री संजय कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह, अरूण कुमार चौधरी , शक्ति नाथ झा, पूर्व सैनिक लाल झा, रमन झा, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी लाल कान्त झा,भाजपा महिला मोर्चा प्रवक्ता सुलेखा झा, भाजपा पूर्वी मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम झा, मयंक चौधरी, सरोज भारती,

भाजपा पूर्वी जिला प्रवक्ता रौशन झा तथा भाजपा दरभंगा के स्तंभ पुरुष अंदौली गांव निवासी वैद्यनाथ यादव प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विकास योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि दरभंगा की धरती ने हमेशा संस्कृति, सत्य और संकल्प का साथ दिया है। अबकी बार यह भूमि परंपरा और प्रगति की विजय कथा लिखेगी। सभा में वक्ताओं ने जनता से भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैथिली ठाकुर केवल एक नाम नहीं, बल्कि मिथिला की अस्मिता, मातृभाषा और संगीत की सजीव पहचान हैं।

इसी क्रम में नदियामी पंचायत में भी भाजपा कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों का जोश देखने लायक था।

प्रधानमंत्री के आगमन पर तैयारी अंतिम चरण में, सैकड़ों मजदूर दिन-रात कार्यरत

AGENCY SAHARSA : देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोमवार को पटेल मैदान में चुनावी आम सभा को लेकर तैयारी अपने अंतिम चरण में है। जिसे एक दिन पूर्व मंच एवं पंडाल तैयार कर सुरक्षा के मद्देनजर एसपीजी के हवाले सौंप दिया जाएगा। प्रधानमंत्री की सभा को लेकर बड़े बड़े वाटरप्रूफ पंडाल बनाये जा रहे है। जिसके कारण सैकड़ो मजदूर दिन रात लगे हुए है।वही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये जा रहे हैं।डीआईजी मनोज कुमार स्वयं मुख्य मंच की तैयारी में दिशा निर्देश देने में जुटे हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री के सभा को लेकर पहुंचे गुजरात से राज्य सभा सांसद सह सभा कार्यक्रम संयोजक मयंक भाई नायक ने

कार्यक्रम स्थल पर मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री सोमवार को जिले में जनता दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।जहां वे स्थानीय लोगों से सीधे संवाद स्थापित कर संबोधित करेगें। इस सभा में लाखों लोगों की भीड़ जुटने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में जिले के सभी चार विधानसभा के प्रत्याशियों सहित कुल 11 एनडीए प्रत्याशी मंच पर उपस्थित रहेगें।

विधानसभा चुनाव से 3 दिन पूर्व भारत व नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा होगी पूर्णतः सील

AGENCY EAST CHAMPARAN : बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने को लेकर शनिवार को पुलिस प्रेक्षक तथा एसएसबी के एडीजीपी ने जिला पदाधिकारी सौरभ जोरवाल एवं पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में चुनाव से 3 दिन पूर्व भारत-नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पूर्णतः सील किये जाने के निर्देश दिए गए। बैठक के बाद बताया गया कि चुनाव को लेकर भारत-नेपाल सीमा के सभी रास्तों एवं 64 चेकपोस्ट पर कड़ी निगरानी के लिए आवश्यक बल की तैनाती सुनिश्चित की गई है। सीमा के माध्यम से अवैध आवागमन, शराब, नकदी एवं आपत्तिजनक सामग्री के संभावित प्रवाह को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी जा रही है। बताया गया कि सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी को लेकर जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक लगातार जिले के सभी महत्वपूर्ण मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। आदर्श आचार संहिता के सख्त अनुपालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किसी भी प्रकार के उल्लंघन की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल कार्रवाई की जा रही है। सभी संदर्भित अधिकारियो को दोषियों के विरुद्ध कठोर एवं त्वरित प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।

NEWS BOX

नालंदा जिले में बारिश में भी नहीं थमा जनसंपर्क अभियान

AGENCY NALANDA : बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान भी जोर पकड़ता जा रहा है। शनिवार को भी रिमझिम बारिश के बीच निर्दलीय प्रत्याशी शबनम लता ने अस्थावां विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में धुआंधार जनसंपर्क अभियन चलाया । उन्होंने मतदाताओं से घर-घर जाकर मुलाकात की और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की ।जनसंपर्क के दौरान सभी जाति -धर्म के महिला -पुरुष, युवक-युवतियों ने उत्साहपूर्वक उनके साथ जुड़कर समर्थन जताया। शबनमलता ने कहा कि उनका उद्देश्य अस्थावां का सर्वांगीण विकास करना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार, अपराधमुक्त समाज की स्थापना , पलायन पर रोक, महिलाओं और बेटियों की सूरक्षा तथा रोजगार सृजन उनकीशिर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि बीते छह वर्षों से वे बच्चोंऔर महिलाओं के उत्थान के लिए कई सामाजिक कार्यक्रम चला रही हैं। लड़कियों को नि :शुल्क सिलाई, कढ़ाई और बुनाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके उपरांत उन्हें सिलाई मशीनें उपहार स्वरूप दी जाती हैं।

रेडक्रॉस व ग्रामीण बैंक ने किया मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन

AGENCY EAST CHAMPARAN : भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी पूर्वी चंपारण और बिहार ग्रामीण बैंक के सौजन्य से शनिवार को मेगा रक्त दान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन शैलेन्द्र कुमार भारती,अध्यक्ष, रेड क्रॉस सोसाइटीज एवं मनीष कुमार ब्रांच मैनेजर बिहार ग्रामीण बैंक द्वारा संयुक्त रुप से किया गया। मौके पर रक्त दान महादान की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि प्रत्येक स्वस्थ्य व्यस्क मानव को तीन महीने में एक बार रक्तदान करना चाहिए। इससे शरीर में नयी स्फूर्ति आती है और कैंसर जैसी बिमारी से भी बचाव होता है।इसलिए मोतिहारी के आमजनों से अनुरोध किया कि बढचढ कर रक्त दान करें ताकि आपात स्थिति में घायलों एवं मरीजों को रक्त आसानी से उपलब्ध हो सके। शिविर में कुल 36बैंक कर्मियों ने रक्तदान किया। जिसमे मनीष कुमार, नलीनी कान्त,अभिषेक रंजन, दीपक कुमार, नूरेन निसार प्रशांत,स्वर्ण सत्यम, प्रिया कुमारी,विकरान्त ठाकुर, रितेश कुमार वर्मा, राहुल कुमार, अवनीत कुमार, कुंदन कुमार, धर्मेंद्र कुमार, सुरभि प्रिया आदि शामिल है।

डिस्लेक्सिया अभियान के तहत दरियापुर बाइट ने निकाली जागरूकता रैली

AGENCY EAST CHAMPARAN : जिले के संग्रामपुर प्रखण्ड शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान बाइट दरियापुर के द्वारा रैली निकाल डिस्लेक्सिया के प्रति लोगो को जागरुक किया गया। प्रचार्य डॉ. नीरा कुमारी के अध्यक्षता में संस्थान के कर्मचारी डीएलएड के प्रशिक्षुओ के द्वारा रैली निकाल उक्त बीमारी के प्रति आमजनों को जागरूक किया गया। प्राचार्य ने बताया कि रैली का मुख्य उद्देश्य डिस्लेक्सिया के प्रति जागरूकता बढ़ाना और प्रभावित बच्चों के प्रति सहानुभूति व सहयोग की भावना विकसित करना है। रैली में व्यख्याता सुधीर कुमार मंडल, राजेश राम, मकसूद आलम अंसारी,जय प्रकाश तिवारी, सोनू कुमार सहित अन्य शामिल रहे।

दस्त की शिकायत पर अस्पताल में इलाजरत 10 वर्षीय बच्ची की मौत

AGENCY NAVADA : नवादा जिले के सिरदला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को इलाज के दौरान एक 10 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। मृतका शेरपुर गांव निवासी उपेंद्र कुमार की पुत्री सृष्टि कुमारी है। परिजन ने इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर अजय कुमार पर लगाया है। शनिवार की शाम सृष्टि सहित उसकी दो बहनों सलोनी कुमारी और सुप्रिया कुमारी को अचानक उल्टी और दस्त की शिकायत हुई, जिसके बाद परिजन दोनों को लेकर सिरदला पीएचसी लेकर पहुंचे। मृतक के मां के अनुसार, डॉक्टर केवल एक बार देखने आए और दवा लिखकर चले गए। उसके बाद बार-बार बुलाने के बावजूद डॉक्टर दोबारा नहीं पहुंचे। शाम करीब 5 बजे तक हालत बिगड़ती रही, लेकिन डॉक्टर वार्ड में नहीं आए। अंततः सृष्टि ने तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया। बच्ची की मां ने रोते हुए कहा — ‟मैं बार-बार डॉक्टर को बुलाने गई, पर वे नहीं आए। मेरी बच्ची मेरे सामने दम तोड़ दी। जब मैं चिल्लाने लगी तब डॉक्टर आए और बोले — बच्ची मर चुकी है ‟ परिजन और ग्रामीणों ने अस्पताल में हंगामा किया। मौके पर पहुंचे पंचायत समिति सदस्य गुड्डू कुमार ने कहा कि सिरदला पीएचसी भगवान भरोसे चल रहा है। यहां डॉक्टर, नर्स और कंपाउंडर अपने निजी क्लिनिक में व्यस्त रहते हैं, जबकि अस्पताल में संविदा पर बहाल गार्ड ही सुई और पट्टी का काम करते हैं।

नालंदा जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित

AGENCY NALANDA : जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह-जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार के आदेशानुसार बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के सफल संचालन हेतु जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना हरदेव भवन,समाहरणालय परिसर में शनिवार को बिहारशरीफ में की गई। यह नियंत्रण कक्ष 1 नवंबर से 7 नवंबर 2025तक तथा मतगणना दिवस 14 नवंबर को 247 कार्य करेगा। डीएम ने बताया कि मतदान तिथि 6 नवंबर 2025 और मतगणना तिथि 14 नवंबर 2025निर्धारित की गई है। मतदान को स्वच्छ, निष्पक्ष,स्वतंत्र एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने तथा विधि -व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के उद्देश्य से यह नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी विरेंद्र कुमार को जिला नियंत्रण कक्ष का वरीय प्रभारी -सह-नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। इसके तहत नालंदा जिले के सभी सात विधानसभा क्षेत्र अस्थावां, बिहारशरीफ, राजगीर, इस्लामपुर, हिलसा , नालंदा और हरनौत- के लिए पृथक-पृथक टेलीफोन लाइनें और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

बैठक पूर्णिया में चुनावी तैयारियों की हुई व्यापक समीक्षा

भ्रामक खबर फैलाने वाले लोगों पर होगी कड़ी कार्रवाई

AGENCY PURNIA : बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के निदेर्शानुसार पूर्णिया जिला अंतर्गत सभी सातों विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभावार सामान्य प्रेक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसी क्रम में शनिवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी अंशुल कुमार और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में प्रेक्षक महोदय की अध्यक्षता में निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा बैठक महानंदा सभागार में आयोजित की गई। बैठक में सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी और निवार्ची पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक करते जिला निर्वाचन पदाधिकारी अंशुल कुमार व अन्य

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण, सामग्री, विधि व्यवस्था, स्वीप, ईवीएम, आदर्श आचार संहिता, व्यय अनुश्रवण, मीडिया, सोशल मीडिया, बज्रगृह और अर्द्धसैनिक बल कोषांग की अद्यतन स्थिति से प्रेक्षक महोदय को अवगत कराया। प्रेक्षक महोदय ने जिला प्रशासन की तैयारियों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्णिया जिले में निर्वाचन की सभी तैयारियां संतोषजनक हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों एवं आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। मतदान केंद्रों पर रोशनी, पानी, शौचालय, साफ-सफाई और दिव्यांग मतदाताओं की सुविधाएं दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए गए। विधि-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान प्रेक्षक ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि अफवाह फैलाने वाले या चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने वाले तत्वों पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाए। सीमावर्ती क्षेत्रों एवं चिन्हित चेकपोस्टों पर सघन जांच तथा उसकी वीडियोग्राफी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। मीडिया और सोशल मीडिया से जुड़ी समीक्षा में प्रेक्षक महोदय ने कहा कि यदि किसी भी प्रकार की भ्रामक या अफवाह आधारित खबर प्रकाशित या प्रसारित होती है, तो उसका त्वरित खंडन किया जाए और संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए।

तेजप्रताप के खिलाफ राबड़ी नहीं करेंगी प्रचार, लेकिन तेजस्वी पर जताया भरोसा

AGENCY PATNA : बिहार के मोकामा में जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हुई हत्या से विपक्ष का एक चुनावी मुद्दा मिल गया है। इसी मुद्दे को लेकर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने शनिवार को राज्य की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पर निशाना साधा। राबड़ी देवी ने आज अपने बड़े बेटे ताजप्रताप को लेकर भी अपनी बात रखी। पटना में शनिवार को पत्रकारों से बाचतीत में राबड़ी देवी ने कहा कि जब गरीब का राज होता है, तो लोग उसे जंगलराज कहते हैं, लेकिन जब सत्ता के संरक्षण में अपराध हो तो उसे क्या कहा जाए? इस दौरान राबड़ी देवी ने बिहार चुनाव और राजनीति पर खुलकर बात की।

पहली बार अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर सार्वजनिक रूप से उन्हों अपनी बात रखी। पत्रकारों ने सवाल कि क्या वह अपने बड़े बेटे के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगी? इस पर राबड़ी देवी ने कहा, मन से तो वो मेरा बेटा ही है, लेकिन उसे पार्टी और घर दोनों से निकाला गया है, तो मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाउंगी। उसके प्रचार के लिए नहीं जाउंगी, लेकिन दिल में है कि वह चुनाव जीते।

पटना महानगर के पूर्व अध्यक्ष अमर कुमार सिन्हा की जदयू में वापसी

PATNA : पटना महानगर के पूर्व अध्यक्ष अमर कुमार सिन्हा ने शनिवार को जनता दल यूनाइटेड (जदयू) परिवार में वापसी की। विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी ने इस अवसर पर अमर कुमार सिन्हा को ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाईयां दीं। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विकास योजनाओं एवं ऐतिहासिक उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के साथ ही मिशन-225 में जोर-शोर से जुटने की भी अपील की। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार भी मौजूद रहे।

बच्चों से भीख मंगवाना एक सामाजिक अपराध

किसी के भी जीवन की सबसे अमूल्य संपत्ति बचपन है। खेलना, पढ़ना, सीखना और सुरक्षित वातावरण में बड़े होना, हर बच्चे का अधिकार है। लेकिन, बच्चों का शोषण, भीख मंगवाने के लिए उनका इस्तेमाल और उनकी मासूमियत का लाभ उठाना आज गंभीर सामाजिक समस्या बन चुका है। भीख मंगवाना व्यक्तिगत समस्या नहीं है। यह एक व्यवस्थित व्यवसाय बन चुका है। छोटे-बड़े शहरों में यह आम दृश्य है कि मासूम बच्चे हाथ में थाली, कपड़े या किसी वस्तु के साथ चलते हैं और लोग उनके मासूम चेहरों पर दया दिखा कर पैसे डाल देते हैं। यह न केवल बच्चों के बचपन को छीनता है, बल्कि उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से भी प्रभावित करता है। समाज की जागरूकता की कमी, लोगों का दया भाव और कुछ परिवारों की आर्थिक मजबूरी मिलकर इस समस्या को बढ़ावा देते हैं। यह सिर्फ गरीबी का नतीजा नहीं, बल्कि बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन भी है। बचपन किसी भी मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील हिस्सा होता है। यह वह समय है, जब बच्चे सीखते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं। लेकिन, जब बच्चों को भीख मंगवाने या किसी अन्य शोषण के लिए मजबूर किया जाता है, तो उनका विकास बाधित होता है। भीख मंगवाना कभी-कभी आर्थिक मजबूरी का नतीजा हो सकता है, लेकिन जब यह नियमित रूप से होता है और बच्चे को मजबूर किया जाता है, तो यह शोषण बन जाता है। मासूमियत का फायदा उठाकर बच्चों से पैसे कमाना एक नैतिक अपराध है। समाज की भूमिका यहां महत्वपूर्ण बन जाती है। लोग यह सोचकर पैसा देते हैं कि वे मदद कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे बच्चों के शोषण को प्रोत्साहित कर रहे हैं। माता-पिता और परिवार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने बच्चों को इस तरह की गतिविधियों से बचाएं। भारत में बाल श्रम और बच्चों से भीख मंगवाने को रोकने के लिए कई कानून हैं। बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम बच्चों को मजदूरी और शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा, चाइल्डलाइन 1098 जैसी सेवाएं 24*7 बच्चों की मदद के लिए उपलब्ध हैं। एनजीओ और सामाजिक संगठन भी सक्रिय रूप से बच्चों को शोषण से बचाने और उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। लेकिन, वास्तविक चुनौती यह है कि कई बार बच्चे और उनके माता-पिता कानूनी संरचना से अनजान रहते हैं और शोषण नेटवर्क इतने संगठित होते हैं कि उन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। सरकार और समाज को मिलकर बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलानी होगी और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देना होगा। समाज का दया भाव और सहानुभूति अक्सर बच्चों के शोषण का कारण बन जाती है। अगर लोग बच्चों को भीख देने के बजाय सही तरीके से मदद करें, तो वे शोषण को बढ़ने से रोक सकते हैं। स्थानीय समुदाय, स्कूल, माता-पिता और पड़ोसी मिलकर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। बच्चों को सुरक्षित वातावरण, शिक्षा और खेलकूद का अवसर देना उनके विकास के लिए जरूरी है। समाज को यह समझना होगा कि केवल पैसे देना बच्चों की मदद नहीं है। सही कार्रवाई, जैसे एनजीओ, चाइल्ड लाइन और सामाजिक संस्थाओं को सूचित करना ही बच्चों को शोषण से बचा सकती है। भीख मंगवाना कई जगहों पर आर्थिक व्यवसाय बन चुका है। कुछ परिवार और नेटवर्क मासूम बच्चों को इस्तेमाल करके पूरे दिन हजारों रुपये कमाते हैं। यह सिर्फ बच्चों की मासूमियत का फायदा उठाना नहीं है, बल्कि उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित करना भी है। पैसा देने वाले लोग यह सोचते हैं कि वे दया कर रहे हैं, लेकिन असल में वे इस प्रणाली को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। यह एक चक्र बन जाता है, जिसमें बच्चों का शोषण जारी रहता है। बच्चों के भविष्य और समाज की नैतिक जिम्मेदारी के लिहाज से यह गंभीर समस्या है। इस समस्या का समाधान समाज, सरकार और नागरिकों के मिलकर काम करने में है। बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा के लिए कदम उठाना जरूरी है। पैसे देने की बजाय मदद करें। बच्चों को भीख देने के बजाय उन्हें शिक्षा, खेल और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाएं। बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड लाइन (1098) और मान्यता प्राप्त एनजीओ से संपर्क करें। समाज में बच्चों के अधिकारों और शोषण की समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाएं। स्कूल, माता-पिता और पड़ोसी मिलकर बच्चों के सुरक्षित वातावरण को सुनिश्चित करें। सिर्फ दया भाव या छोटे पैसों से बच्चों की मदद नहीं होगी। सही कार्रवाई, जागरूकता और कानूनी उपाय ही उन्हें बचा सकते हैं। समाज, सरकार और नागरिकों के मिलकर सही कदम उठाने से ही इस समस्या का समाधान संभव है। जागरूकता, शिक्षा और सहयोग से ही हम बच्चों को उनका बचपन वापस दिला सकते हैं और उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव रख सकते हैं।

बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के बीच आईएमएफ

ANALYSIS

✍ डॉ. मयंक चतुर्वेदी

संगठन ने साफ कर दिया है कि वह लोन की छठी किस्त तब तक जारी नहीं करेगा, जब तक बांग्लादेश में स्थायी, निर्वाचित और वैधानिक सरकार नहीं बन जाती। आईएमएफ ने जनवरी 2023 में बांग्लादेश के लिए 5.5 अरब डॉलर का पैकेज स्वीकृत किया था। इस राशि का उद्देश्य था विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर करना, मुद्रा की गिरावट रोकना और बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण पाना। पांच किस्तों में से 3.6 अरब डॉलर पहले ही जारी किए जा चुके हैं लेकिन करीब 800 मिलियन डॉलर की छठी किस्त रोक दी गई है। अब आईएमएफ के इस फैसले को महज आर्थिक कदम मानना भूल होगी। यह एक प्रकार का राजनीतिक और नैतिक दबाव है, जो संकेत देता है कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान बजट या बैलेंस शीट नहीं देखते, बल्कि यह भी परखते हैं कि शासन में पारदर्शिता, नागरिक सुरक्षा और धार्मिक समानता का कितना पालन हो रहा है। देश के भीतर प्रशासनिक रिश्वतखोरी की स्थिति भयावह है। पासपोर्ट सेवा में 75 प्रतिशत, वाहन पंजीकरण में 72 प्रतिशत और न्यायिक सेवाओं में 34 प्रतिशत लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है। यह स्थिति केवल आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि नागरिकों के बीच शासन के प्रति अविश्वास भी पैदा करती है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का हालिया निर्णय, जिसमें उसने बांग्लादेश की नई सरकार बनने तक अगली किस्त जारी करने से इनकार किया है, इसके माध्यम से बता दिया है कि यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय की उस गहरी चिंता का प्रतीक है, जो इस देश के शासन तंत्र की नीतिगत सड़ांध और नैतिक गिरावट को देख रही है। वस्तुतः आईएमएफ ने बांग्लादेश को बड़ा झटका दिया है। संगठन ने साफ कर दिया है कि वह लोन की छठी किस्त तब तक जारी नहीं करेगा, जब तक बांग्लादेश में स्थायी, निर्वाचित और वैधानिक सरकार नहीं बन जाती। आईएमएफ ने जनवरी 2023 में बांग्लादेश के लिए 5.5 अरब डॉलर का पैकेज स्वीकृत किया था। इस राशि का उद्देश्य था विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर करना, मुद्रा की गिरावट रोकना और बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण पाना। पांच किस्तों में से 3.6 अरब डॉलर पहले ही जारी किए जा चुके हैं लेकिन करीब 800 मिलियन डॉलर की छठी किस्त रोक दी गई है। अब आईएमएफ के इस फैसले को महज आर्थिक कदम मानना भूल होगी। यह एक प्रकार का राजनीतिक और नैतिक दबाव है, जो संकेत देता है कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान बजट या बैलेंस शीट नहीं देखते, बल्कि यह भी परखते हैं कि शासन में पारदर्शिता, नागरिक सुरक्षा और धार्मिक समानता का कितना पालन हो रहा है। देश के भीतर प्रशासनिक रिश्वतखोरी की स्थिति भयावह है। पासपोर्ट सेवा में 75 प्रतिशत, वाहन पंजीकरण में 72 प्रतिशत और न्यायिक सेवाओं में 34 प्रतिशत लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है। यह स्थिति केवल आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि नागरिकों के बीच शासन के प्रति अविश्वास भी पैदा करती है। माना जा रहा है कि

विदेशी निवेशक अब ढाका को जोखिमपूर्ण बाजार मानने लगे हैं। वर्ष 2024 के अंत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में 18 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि निर्यात वृद्धि दर 6.2 प्रतिशत से घटकर 3.1 प्रतिशत रह गई। बांग्लादेश बैंक की रिपोर्ट बताती है कि विदेशी मुद्रा भंडार भी एक वर्ष में 39 अरब डॉलर से घटकर 22.5 अरब डॉलर पर आ गया है। बांग्लादेश की मौजूदा परिस्थिति दिखाती है कि किसी भी देश की आर्थिक नीतियां धर्म और राजनीति से अलग नहीं रह सकतीं। जब शासन एक वर्ग के प्रति पक्षपाती हो, कानून व्यवस्था चरमपंथियों के नियंत्रण में आ जाए और प्रशासनिक संस्थाएं भ्रष्टाचार से ग्रस्त हों, तो अर्थव्यवस्था अपने आप ढहने लगती है। दरअसल, यहां हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार केवल एक मानवाधिकार संकट नहीं है, यह उस आर्थिक प्रणाली की विफलता है जो समान अवसर और सुरक्षा देने में असफल रही है। ऐसे में आईएमएफ का संदेश साफ नजर आता है कि वित्तीय स्थिरता, सामाजिक न्याय से अलग नहीं हो सकती। अब आईएमएफ की इस रोक ने बांग्लादेश को एक निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया है। अगर देश अब भी सुधारों की राह नहीं अपनाता, तो आने वाले महीनों में विदेशी मुद्रा संकट, महंगाई और बेरोजगारी का विकराल रूप सामने आएगा। यहां लगता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का बांग्लादेश के लिए संदेश स्पष्ट है- उसे तय करना होगा कि वह किस दिशा में जाना चाहता है। एक ऐसा देश जो भ्रष्टाचार, धार्मिक कट्टरता और राजनीतिक हठ का प्रतीक बने या वह राष्ट्र जो अपनी गलतियों से सबक लेकर स्थायी विकास, सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण की राह चुने।

आईएमएफ का भरोसा टूटने का एक कारण यह भी है, क्योंकि किसी भी आर्थिक सुधार को लागू करने के लिए सबसे पहले प्रशासनिक ईमानदारी और पारदर्शिता चाहिए, जो ढाका में दुर्लभ है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस, जिन्हें कभी गरीबों का मसीहा कहा गया, आज उसी मंच पर आलोचना का केंद्र बने हुए हैं। साल 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद यूनुस ने सेना समर्थित अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभाला लेकिन वह न तो आर्थिक स्थिरता दे पाए न राजनीतिक भरोसा। आईएमएफ, विश्व बैंक और विदेशी निवेशक, सभी ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वे केवल एक लोकतांत्रिक, जनादेश-आधारित सरकार के साथ ही दीर्घकालिक सहयोग करेंगे। बांग्लादेश की आर्थिक गिरावट केवल वित्तीय अनुशासन की कमी से नहीं, बल्कि सामाजिक असमानता और धार्मिक उत्पीड़न से भी जुड़ी है। जब किसी समाज में भय का वातावरण होता है, जब नागरिकों को सुरक्षा नहीं मिलती, तो निवेशकों का भरोसा भी डगमगाने लगता है। आईएमएफ और अन्य वैश्विक संस्थान इन संकेतों को गंभीरता से लेते हैं। हिंदू समुदाय, जो बांग्लादेश की कुल आबादी का लगभग 8 प्रतिशत है, ऐतिहासिक रूप से व्यापार, शिक्षा और पेशेवर वर्गों में प्रमुख भूमिका निभाता रहा है। जब इस समुदाय को निशाना बनाया जाता है, तो स्थानीय बाजार और उत्पादन चक्र कमजोर पड़ते हैं। उद्योग-धंधों में अस्थिरता आती है और उपभोक्ता विश्वास टूटता है। यह सीधे जीडीपी और रोजगार दर को प्रभावित करता है। बांग्लादेश का सामाजिक संकट उसकी अर्थव्यवस्था जितना ही गंभीर है। देश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय पर लगातार हमले हो रहे हैं। साल 2025 में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हिंसा अपने चरम पर रही। वर्ष के पहले छह महीनों में ही 250 से अधिक हमले, 27 हत्याएं और 60 से ज्यादा मंदिरों पर हमले हुए। साल 2023 में 302 घटनाएँ, जबकि साल 2024 में (दिसंबर तक) 2200 से अधिक मामले दर्ज हुए। अगस्त 2024 से अगस्त 2025 के बीच 1,700 से अधिक दर्ज घटनाएं, कम से कम 23 ज्ञात मौतें और 150 से अधिक मंदिरों को नुकसान की पुष्टि अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में हुई। जिनमें सैकड़ों हिंदू परिवारों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। मानवाधिकार संगठन हिंदू बौद्ध खिश्चियन यूनिटी काउंसिल के अनुसार पिछले एक वर्ष में 1,045 घटनाओं में 45 लोगों की हत्या हुई, 479 घायल हुए और 102 मंदिरों या व्यवसायों को नुकसान पहुंचाया गया। यह स्थिति केवल धार्मिक असहिष्णुता नहीं, बल्कि शासन की निष्क्रियता और सामाजिक नियंत्रण की विफलता का प्रमाण है। आईएमएफ ने कई बार स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश को वित्तीय सुधारों के साथ ही प्रशासनिक और सामाजिक सुधारों की आवश्यकता है। आगे आईएमएफ का प्रतिनिधिमंडल 29 अक्टूबर से देश की दो सप्ताह की समीक्षा करेगा। यह दल बांग्लादेश बैंक, वित्त मंत्रालय और आर्थिक सुधार बोर्ड से मुलाकात करेगा और तय करेगा कि सहायता की अगली किस्त जारी की जाए या नहीं। भ्रष्टाचार और अल्पसंख्यक विरोधी हिंसा, दोनों बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय साख को चोट पहुंचा रहे हैं।

माओवाद का खात्मा : संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गृहमंत्री अमित शाह ने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बने माओवाद को मार्च 2026 तक समाप्त करने का जो संकल्प लिया है, वह अब सिद्धि की ओर अग्रसर है। देश का एक बहुत बड़ा भू-भाग जो विकास की मुख्यधारा से अलग था, अब शेष भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तत्पर है। आज छत्तीसगढ़ के नक्सलवादी आतंकवाद के लिए कुख्यात बस्तर में तिरंगा फहरा रहा है और नक्सलवादियों के गढ़ में गृहमंत्री अमित शाह की जनसभाएं हो रही हैं। गृहमंत्री नक्सलवादियों को स्पष्ट संदेश देते हैं कि माओवादियों आपके पास अब दो ही विकल्प बचे हैं या तो समर्पण कर दें या फिर एनकाउंटर के लिए तैयार रहें। इस सख्ती का ही असर है कि 17 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ में एक साथ 210 माओवादियों ने एक साथ समर्पण किया है। उधर, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष छह करोड़ रुपये के इनामी माओवादी पोलित ब्यूरो सदस्य मल्लेजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति उर्फ सोनू उर्फ अभय ने 60 साथियों सहित बंदूक छोड़कर विकास की राह थाम ली है। इन माओवादियों ने 54 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है, जिनमें सात एके 47 और नौ इंसास राइफलें है। भूपति माओवादी संगठन में सबसे प्रभावशाली रणनीतिकारों में माना जाता था और उसने लंबे समय तक महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर अभियानों का नेतृत्व किया। भूपति वही खतरनाक माओवादी आतंकवादी है, जिसने छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के 76 जवानों का नरसंहार किया था। महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला दशकों से माओवादी गतिविधियों का केंद्र रहा है। इस क्षेत्र के शीर्ष माओवादी का समर्पण शेष बचे हुए नक्सलियों खासकर निचले स्तर के कैडर को सीधा संदेश दे रहा है कि अब जब उनका सबसे बड़ा और अनुभवी नेता हथियार डाल रहा है, तो उनके पास भागने या छिपने का कोई रास्ता नहीं बचा है। इससे वे भी समर्पण करने के लिए मन बनायेंगे। यह समर्पण छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे राज्यों के लिए शांति का बड़ा संकेत है। भूपति व उसके साथियों के समर्पण करने से माओवादियों की सबसे मजबूत दीवार ढह गई है। जनवरी 2023 में गृहमंत्री अमित शाह ने माओवाद के खिलाफ ऑपरेशन को हरी झंडी दी, उसके बाद से अब तक सुरक्षाबलों ने 312 माओवादियों को मार गिराया है। मारे गए माओवादियों में में सीपीआई माओवादी महासचिव वासव राजू समेत पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति के आठ सदस्य भी शामिल हैं। 21 जनवरी 2024 से लेकर अब तक माओवाद के खिलाफ अनेक ऑपरेशन सफलतापूर्वक चलाए जा चुके हैं, जिनमें 836 माओवादी गिरफ्तार किये गए हैं और 1639 आत्मसमर्पण कर चुके हैं। आत्मसमर्पण करने वालों में पोलित ब्यूरो और एक केंद्रीय समिति सदस्य शामिल है। वर्ष 2010 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने माओवाद को भारत की सबसे बड़ी चुनौती बताया था, किंतु उस समय राजनैतिक कारणों से माओवाद के पूर्ण सफाए का कोई ब्लूप्रिंट नहीं बन पाया था। मनमोहन सरकार के कार्यकाल में माओवादी बहुत बड़ी चुनौती थे। उस समय ये नेपाल के पशुपतिनाथ से आंध्र प्रदेश के तिरुपति तक लाल कॉरिडोर बनाने का सपना देख रहे थे । ये भारत, भारत के संविधान और भारत की सनातन संस्कृति से बैर रखते हैं। वर्ष 2013 में विभिन्न राज्यों के 126 जिलों के माओवादी हिंसा से ग्रस्त होने की रिपोर्ट केंद्र को भेजी गई थी। वर्ष 2014 में मोदी सरकार आने के बाद से मार्च 2025 तक यह संख्या 126 से घटकर केवल 18 जिलों तक सीमित रह गई है। वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 11 रह गई है। इनमें छत्तीसगढ़ के सात जिले, झारखंड का एक जिला पश्चिम सिंहभूम, मध्यप्रदेश का एक जिला बालाघाट, महाराष्ट्र का एक जिला गढ़चिरौली और ओडिशा का एक जिला कंधमाल शामिल है। इनमें भी अब छत्तीसगढ़ के तीन जिले बीजापुर, नाराणपुर और सुकमा ही अति माओवादी प्रभावित बचे हैं। वर्ष 2014 के पूर्व माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर तिरंगा फहराना अपराध माना जाता था, गरीबों के लिए सरकारी सहायता नहीं पहुच पाती थी और दूरदराज के गांवों से किसी भी माध्यम से संपर्क नहीं हो पाता था। अब समय बदल चुका है, छत्तीसगढ़ के माओवाद से मुक्त हुए क्षेत्रों में विकास की नई गंगा बह रही है। बस्तर जैसे कुख्यात जिले मे तिरंगा शान से फहरा रहा है। युवा बड़ी संख्या में खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों में भागीदारी कर रहे है। माओवादियों से मुक्त हुए क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का तीव्र विकास किया जा रहा है। कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं जिससे वहां की जनता दोबारा माओवादियों के दुष्प्रचार में न फंसे। माओवाद के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत उनकी फंडिग रोकने का काम भी किया जा है। जैसे-जैसे माओवाद के सफाए का अभियान आगे बढ़ रहा है, उसके समर्थक राजनैतिक तत्वों के पेट में दर्द भी उठ रहा है। माओवाद के समर्थन से फल फूल रहे वामपंथी दलों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को बंद करने की अपील तक कर दी। तेलंगना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तो एक कार्यक्रम में कह दिया कि माओवाद एक विचारधारा है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। सोशल मीडिया पर भी माओवादी विचारधारा के समर्थक भी यही बात कह रहे हैं कि यह विचारधारा पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकती। माओवाद एक जहरीली, खतरनाक और नरसंहार का समर्थन करने वाली विचारधारा है, जिसका अंत करने के लिए सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सुरक्षा बल आक्रामक भी हैं और समर्पण करने वालों का स्वागत भी कर रहे हैं।

Social Media Corner

सच के हक में...

आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पंजाब और पुडुचेरी के स्थापना दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई! इन सभी क्षेत्रों ने भारत की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ईश्वर करे कि ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी विकास यात्रा में निरंतर नए आयाम स्थापित करते रहें। मैं इन सभी प्रदेशवासियों की निरंतर समृद्धि और कल्याण के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देतीं हूं।

(राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का 'एक्स' पर पोस्ट)

नागरिक देवो भवः ही हमारे सुशासन का मंत्र है। इसीलिए यहां हमें ऐसे कानूनों पर बल देना है, जिससे रिफॉर्म्स को गति मिलने के साथ ही जनता-जनार्दन का जीवन भी ज्यादा से ज्यादा आसान हो। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के समय हम सभी ने देव से देश और राम से राष्ट्र का संकल्प लिया था। उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी हमें उनके आदर्शों को साकार करना है।

(प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'एक्स' पर पोस्ट)

पाकुड़ में कांग्रेस नेता बेलाल शेख और उसके साथी जियाउल पगला ने सोलागढ़िया गांव में पत्थर खदान के मुन्शी पर गोलीबारी की। सौभाग्य से मुन्शी की जान बच गई है। घायल मुन्शी ने बयान दिया है कि दो दिन पूर्व इन्हीं अपराधियों द्वारा उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी भी की लेकिन 'हाऊस' के दबाव में दोनों को छोड़ दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि गिरफ्तारी का रिकॉर्ड भी गायब कर दिया गया है।

(बाबूलाल मरांडी का 'एक्स' पर पोस्ट)

खानपान की बदलतीं प्राथमिकताएं

देशवासियों के रहन-सहन और खान-पान में तेजी से बदलाव आ रहा है। लोगों की प्राथमिकताएं चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण, सभी जगह बदलाव का दौर चल रहा है। बदलती प्राथमिकताएं सेहत पर भारी पड़ने लगी हैं तो गंभीर चिंता का कारण भी बनती जा रही हैं। बदलाव को इसी तरह से भली-भांति समझा जा सकता है कि प्राथमिकताओं में वाहन, दवा और जंक फूड प्रमुखता लेते जा रहे हैं। यूनिसेफ की पिछले दिनों जारी रिपोर्ट के अनुसार बदलाव का यह दौर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में नेक टू नेक देखा जा रहा है। अनाज का स्थान जंक फूड ले चुका है। ग्रामीण क्षेत्र में जंक फूड का उपयोग जहां 10 प्रतिशत हो गया है, वहीं अनाज उपयोग 5.4 प्रतिशत रह गया है। इसी तरह से शहरी क्षेत्र में जंक फूड की हिस्सेदारी 11 प्रतिशत हो गई है तो अनाज पर खर्च का प्रतिशत केवल केवल 4 प्रतिशत रह गया है। वाहन आदि पर व्यय ग्रामीण क्षेत्र में 7.8 फीसदी हो गया है, तो शहरी क्षेत्र में कुछ ही अधिक 8.2 प्रतिशत हो गया है। यह रहन-सहन व खान-पान के बदलाव की तस्वीर है। साइड इफेक्ट यह कि अनाज से ज्यादा खर्च स्वास्थ्य यानी की इलाज पर ग्रामीण क्षेत्र में 6.5 प्रतिशत तो शहरी क्षेत्र में इससे कुछ कम 5.9 प्रतिशत होने लगा है। शिक्षा पर खर्च में ग्रामीण क्षेत्र जहां 3.8 प्रतिशत पर अटका है, वहीं शहरी क्षेत्र 6 प्रतिशत है। निश्चित रूप से शहरी क्षेत्र में शिक्षा प्राथमिकता बनी हुई है। यूनिसेफ की चिंता यह नहीं है कि किस पर कितना व्यय हो रहा है। चिंता का कारण यह है कि जंक फूड के साइड इफेक्ट सामने आने लगे हैं। आज अधिक कैलोरी वाले जंक-फूड पेट भरने का प्रमुख साधन बन गया है। साइड इफेक्ट देखिए कि बच्चों से लेकर बड़ों तक देश में मोटापा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से मोटापा के कारण होने वाली बीमारियों के साथ आज की युवा पीढ़ी हृदय रोग की शिकार होती जा रही है। दुनिया के देशों में जहां डायबिटिज यानी मधुमेह की गिरफ्त को कम करने में जुटे हैं, वहीं हमारे देश में मधुमेह की गिरफ्त लगातार मजबूत होती जा रही है। मधुमेह से ग्रसित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही अन्य बीमारियों की पकड़ अधिक होती जा रही है। जंक फूड के चलते इम्यूनिटी प्रभावित हो रही है। अधिक कैलोरी के कारण शरीर थुलथुल होता जा रहा है। हालांकि मोटापे की समस्या से समूची दुनिया जूझ रही है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार, डिब्बाबंद खाने के चलते साल 2030 तक देश में 2.7 करोड़ से अधिक बच्चे मोटापे की चपेट में आने की आशंका व्यक्त की जा रही है। बच्चे हो या बड़े सबकी पंसद बर्गर, पिज्जा, चिप्स, कुरकुरे, मैगी, बिस्कुट और इसी तरह से डिब्बाबंद खाद्य सामग्री के साथ जूस और सॉफ्ट ड्रिंक पसंद बनते जा रहे हैं। इसका एक तो बड़ा कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में समाज रुप से बढ़ती मार्केटिंग सुविधा, चंद मिनट से लेकर कुछ मिनटों में ही सामग्री की उपलब्धता, फिर स्वाद और आक्रामक विज्ञापनों के मोहजाल के कारण पैक्ड खाद्य सामग्री के प्रति तेजी से रुझान बढ़ा है। आकर्षक नाम, आकर्षक आउटलेट, वेल अरेंज्ड डिलिवरी सिस्टम व गिग वर्कर्स की टीम द्वारा आर्डर के साथ ही चंद मिनटों में उपलब्धता और इसके साथ ही इंस्टेट खाने की आदत के कारण यह सब हो रहा है। चिंता का कारण है कि खाना जो पौष्टिकता और समयानुकूल होता था वह अब कहीं खो गया है। अब स्वाद और इंस्टेट खाने का मोह होने लगा है। एक अन्य कारण शहरों में अध्ययन के लिए जाने, पीजी और लाइब्रेरी की कल्चर ने युवाओं का जंक फूड की गिरफ्त में अधिक ले लिया है। कौन खाना बनाए, के चक्कर में एक फोन पर सहज उपलब्धता को देखते हुए भी जंक फूड को बढ़ावा मिला है। फिर यह शहरों से गांवों तक पहुंच गई है, जिससे गांवों में भी जंक फूड आम होता जा रहा है। यूनिसेफ ही नहीं समूची दुनिया की चिंता का कारण यह है कि खानपान और रहन-सहन की बदलती प्रवृत्ति स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। आज समूची दुनिया मोटापा की समस्या को लेकर गंभीर है, तो हृदय रोग की गिरफ्त में कम आयु के भी आने लगे हैं।

सिंथेटिक मीडिया

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जनित डीपफेक या कृत्रिम रूप से निर्मित चित्र एवं वीडियो सोशल मीडिया पर तब से तेजी से फैल रहे हैं, जब से जनरेटिव एआई ने फोटोरियलिस्टिक सामग्री (कंटेंट) को किसी दिए गए दृश्य का विवरण टाइप करने जितना आसान बना दिया है। जैसे-जैसे यह तकनीक 2024 तक तेजी से विकसित हुई, चुनाव की विश्वसनीयता को लेकर चिंताएं बढ़ीं और एआई द्वारा सृजित सामग्री (कंटेंट) की मदद से गलत सूचनाओं को बढ़ावा मिला। भले ही ये चिंताएं आशंका वाले नतीजों के शिखर तक नहीं पहुंचीं, लेकिन एआई स्लॉप का प्रसार कम बजट वाले विज्ञापनों से लेकर उच्च बजट वाले राजनीतिक व्यंग्यचित्रों तक में व्यापक रूप से हो गया है। इस संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा आईटी नियम, 2021 में संशोधन के साथ एआई-जनित सामग्री की अनिवार्य लेबलिंग का प्रस्ताव इस परिघटना को समझने से जुड़ी वैश्विक बातचीत को कुछ हद तक आगे बढ़ाता है। यह साफ नहीं है कि भारत में इंटरनेट उपयोगकताओं - जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एआई उपयोगकर्ता आधार भी है, के लिए एआई स्लॉप को पहचानने में असमर्थ रहना कितनी बड़ी समस्या है। दो प्रमुख कारक पलड़े को कार्रवाई के पक्ष में झुकाते हैं- एआई के आगमन से पहले की गलत एवं भ्रामक सूचनाओं की तरह ही झूठ और भ्रामक कंटेंट कभी भी वायरल हो सकती है, जिससे उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था में असंगत स्थान मिल जाता है और कई लोगों को धोखा देने वाली फोटोरियलिस्टिक कंटेंट बनाने की तकनीक हर हफ्ते बेहतर होती जा रही है। सार्वजनिक हस्तियों ने अक्सर, कभी-कभी अदालत में भी यह शिकायत की है कि बेईमान मकसदों के लिए उनकी तस्वीरों का दुरुपयोग किया जा रहा है। सिनेमाघरों में और ओटीटी स्ट्रीमिंग सेवाओं पर अनिवार्य धूम्रपान से जुड़ी चेतावनियों, एक ऐसा उपाय जिसे मनोरंजन के सृजनकताओं व उपभोक्ताओं पर थोपे जाने से पहले उद्योग जगत ने बहुत कम समर्थन दिया था और जिसका कोई विश्वसनीय प्रभाव नहीं दिखा, के ठीक उलट सिंथेटिक कंटेंट के बढ़ते प्रसार की शुरूआत में ही बड़े सोशल मीडिया और एआई फर्मों द्वारा लेबलिंग की पेशकश की गई है।

Printed and Published by Fahim Akhtar on behalf of MAA MEDIA VENTURE and Printed at SHIVA SAI PUBLICATION PVT.LTD, Ratu, Kathitand, Near Tender Bagicha, H.P. Petrol Pump P.O.+P.S.- Ratu, Dist.-Ranchi, 835222, Jharkhand And Published at Roshpa Tower, 5th Floor, Main Road, Ranchi, Jharkhand-834001. R.N.I Number - JHABIL/2022/85899, Editor- Fahim Akhtar. Mob - 9431311669, E-mail : thephotonnewsjharkhand@gmail.com

The long shadow of old battles in Tata-Mistry clash

Deep tensions within the immediate and extended family, emotions within the Parsi community, and wars between Parsis and non-Parsis have been part and parcel of the Tata Group's tumultuous history over the past 150 years. Tata Trusts, the more philanthropic end of the sprawling salt-steel-software empire, owns a majority stake in Tata Sons, the holding firm. So the former's footprints within the world of profits and boardrooms have always constituted an uneasy ingress, dogging the family for a century. British colonial rulers and post-independence regimes, all have meddled in the Tatas' affairs.

Hence, there is nothing shocking about the stink that erupted within the Tata Trusts, originating from the feud between Mehli Mistry, a trustee, and Noel Tata, the new heir and the late Ratan Tata's half-brother. Noel ejected Mehli from the trust, but that set in motion a disruptive cascade that ended up crashing into the Tata Sons' boardroom. At stake is a tangled web of aggravated relations: among Parsis (Mehli vs Noel), between Parsis and non-Parsis, and within kinfolk (Noel vs the family of the late Cyrus Mistry, his brother-in-law). The group has grappled with such shenanigans in the past, too.Mehli, who is likely to legally contest his ouster, sees himself as the holder of Ratan's legacy. He wants a say in all nodal centres across the group. He is peeved that Noel trusts non-Parsis: two are in Tata Trusts, a third is Tata Sons' chairman. Mehli is Cyrus's cousin, but supported Ratan during the Ratan-Cyrus spat. It is possible that Mehli dislikes Noel's recent moves to fix the love-hate relationship with his in-laws.

Implicit in these are three issues. Mehli's proprietary sense is one. Since the early 1900s, trustees have tussled over this right. In his biography of the group, Mircea Raianu explains how Dorabji and Ratanji, the two sons of founder Jamsetji Tata, who died in 1904, clashed with a cousin, R D Tata. The two sides "faced… momentous decisions about how best to carry on [Jamsetji's] legacy"; Dorabji's "conservative instincts" jarred with RD's "ambitious plans". It was left to a mediator, Jamsetji's trusted advisor B J Padshah, to bring the trio together.In the 2010s, Ratan sidelined Noel and anointed Cyrus as his successor. After the Ratan-Cyrus falling out, a technocrat, N Chandrasekaran, headed Tata Sons. Noel got the opportunity to own and manage the empire only after Ratan's death.Relations with 'outsiders', or non-Parsis, are another issue. Historically, they have been both welcomed and shunned by the Tatas. Raianu writes that the group "depended on Marwari intermediaries to connect them with the inland markets". Marwaris "permeated the Tata organisation as selling agents, partners, and shareholders". But when Tata & Co was liquidated in 1930, the Marwari shareholders were shaken off. The Tatas used the crisis to "enact a clean break" from them. Gone were individuals like Cheniram Jesraj, a Marwari partner since the group's old opium trading days. Earlier, when Padshah brokered peace between Dorabji and RD, the Marwari agents were excluded to "protect" the Tata name and ensure that it remained "unblemished".In the early 1990s, when Ratan took over from J R D Tata, he got rid of outsiders, or corporate overlords who managed the group's jewels—the steel, auto, and hotel businesses. But after the fight with Cyrus, Ratan again inducted non-Parsis in Tata Trusts. An outsider headed Tata Sons too. Mehli joined during the post-Cyrus period, and Ratan maintained a balance between Parsis and non-Parsis in the affairs of both Tata Sons and Tata Trusts. When Noel took over and leaned more towards non-Parsis, it rankled the Parsis.Finally, what irked Mehli was an old riddle: Tata Trusts' influence over Tata Sons and what it ought to be. The prickly and contradictory nature of ties between charities and companies, philanthropy and profits, and public and private interests surfaced as early as 1899. Jamsetji had decided to set up a property trust to settle the family estate and leave adequate money for charity.

Long road to justice in '84 riots cases

Sajjan serves a life term, Tytler faces trial — proof of victims' relentless fight against power

FORTY-ONE years after the 1984 Sikh genocide, in which 2,733 Sikhs were brutally killed in Delhi (as per official figures), justice continues to elude the victims. The cases against two key masterminds — former Union Minister Jagdish Tytler and former MP Sajjan Kumar — have drawn national attention. Bringing these political leaders to trial was a long, uphill struggle: Sajjan Kumar has been in jail for seven years, and Jagdish Tytler now faces a murder trial.On September 28, 2007, a journalist informed me that the CBI had given Jagdish Tytler a "clean chit." When she asked how to obtain the report, I advised her to request it directly from the judge's chamber. Hours later, she returned with a critical piece of information: the CBI had filed a charge sheet against one Suresh Paniwala but had inserted an exoneration of Tytler within it.By filing a charge sheet instead of a closure report, the CBI avoided the legal requirement of notifying the complainant before exonerating an accused. This was a clear attempt to surreptitiously clear Tytler without scrutiny. The report also claimed the agency could not trace Jasbir Singh, a key eyewitness.

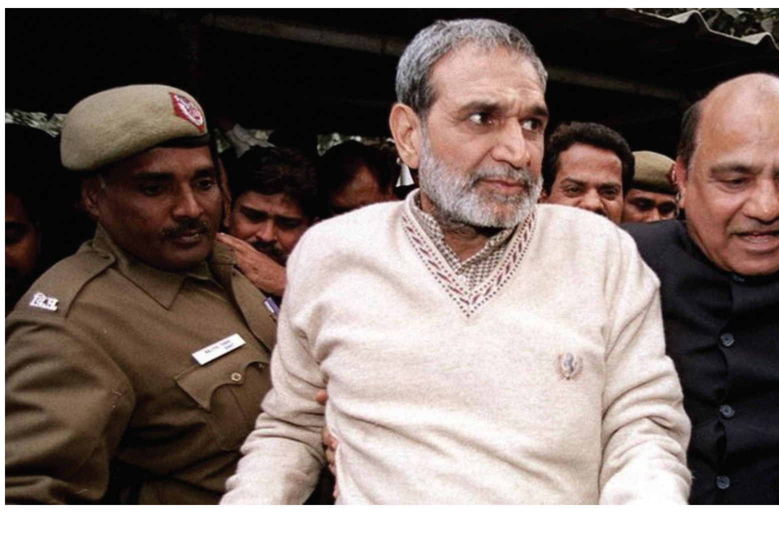

The case against Tytler — accused of leading a mob that killed three Sikhs at Gurdwara Pul Bangash in 1984 — was registered in 2005 on the Nanavati Commission's recommendation and assigned to the CBI. When the case came up the next day, I appeared for the victims and argued that the court must treat it as a closure report, not a charge sheet, and give us time to locate Jasbir Singh. The court agreed and issued notice to the complainant. In December 2007, we filed a protest petition, and advocate Navkiran Singh submitted Jasbir Singh's affidavit offering to testify. The court rejected the CBI's report and ordered further investigation. In March 2010, the CBI again gave Tytler a clean chit. Simultaneously, the Congress announced his candidature for the Lok Sabha. The same day, I filed a new protest petition. Tytler's supporters attacked me in the Karkardooma court complex. Two days later, journalist Jarnail Singh threw a shoe at Home Minister P Chidambaram in protest. Under massive public pressure, the Congress withdrew Tytler's ticket.In April 2013, the court again rejected the second closure report, ordering fresh investigation. Yet, in December 2014, the CBI filed a third closure report, again clearing Tytler. On December 4, 2015, the court not only rejected this report but also ordered court-monitored investigation. In 2023, the CBI finally filed a charge sheet for murder against Tytler for leading the mob that killed three Sikhs at Gurdwara Pul Bangash. The trial is now underway.In January 2010, the CBI filed two charge sheets against Sajjan Kumar — one for the murder of five Sikhs in Delhi Cantt and another for one Sikh in Sultanpuri. Both were registered in 2005 after the Nanavati Commission's findings. Co-accused included ex-MLA Mahinder Yadav and ex-councillor Balwan Khokhar.

On February 2, 2010, when the cases came up in court, I appeared for the victims and requested warrants against the accused, but the public prosecutor sided with Sajjan Kumar's lawyer in seeking summons instead. Concerned about the prosecutor's bias, we approached the Delhi HC for a special public prosecutor. The then Chief Justice AP Shah ordered that the CBI and I agree on a name. We nominated Senior Advocate RS Cheema and DP Singh as special public prosecutors. Their appointment was a turning point.When Sajjan applied for anticipatory bail, Sessions Judge PS Teji rejected it, after which Sajjan went underground and approached the HC. Several judges recused from hearing the matter. When one judge hinted at granting interim protection, I objected, reminding the court that "when 3,000 Sikhs were killed, heavens had already fallen." Ultimately, no relief was granted that day, though another judge later granted bail.

The case was transferred to Karkardooma Court. Putting aside my other court work for three years, I focussed on this trial. Charges were framed in April 2010 and evidence began soon. Sajjan's men tried to influence witnesses, especially Nirpreet Kaur, who had lost her father in the massacre. Working with Punjab CM Parkash S Badal and ADGP Suresh Arora, we arranged a house in Mohali guarded by Punjab Police Commandos, ensuring witness safety.We even attempted a sting operation on Sajjan Kumar through Nirpreet, but his men grew suspicious and she narrowly escaped. The witnesses later testified from secure accommodations arranged through a CBI request to Punjab.The main witness, Jagdish Kaur, whose husband and two sons were killed, testified first. Her harrowing account shook everyone in court. The defence cross-examined her for 17 days, until suddenly the SC stayed the trial. I argued that such a stay would destroy the witnesses' morale. The court relented, listing the case again within two weeks — a rare move. Later, the stay was vacated, and the trial resumed.

In April 2013, the trial court acquitted Sajjan Kumar but convicted Mahinder Yadav, Balwan Khokhar and three others. The verdict provoked public outrage. Nirpreet Kaur launched a fast-unto-death at Jantar Mantar, demanding an appeal. Supported alternately by AAP, BJP and Akali Dal, her protest forced the government to file an appeal in the Delhi HC after seven days.

While the appeal was pending, I entered politics and became Leader of Opposition in Punjab, which barred me from practising law. Torn between public office and my commitment to the 1984 victims, I resigned in July 2017 to continue pursuing these cases. My resignation drew judicial attention to the victims' continued pain.Soon after, the SC, led by Justice Dipak Misra, appointed a supervisory committee to re-examine 199 closed cases. In January 2018, it formed a new SIT, headed by Justice SN Dhingra, to reopen investigations. This revived hope for justice after three decades of impunity. The renewed momentum produced tangible results. In September 2018, a Delhi court awarded death penalty to one accused and life imprisonment to another. Then, on December 17, 2018, the Delhi HC convicted Sajjan Kumar and sentenced him to life imprisonment. He has been in jail since, with repeated bail pleas rejected. His final appeal is scheduled in the SC on November 12.

In another case, on February 25, 2025, ASJ Kaveri Baweja sentenced Sajjan Kumar to two life terms for the murder of a Sikh father and son. A third case against him is in its final argument stage.The pursuit of justice for the 1984 genocide victims has been a decades-long struggle marked by political interference, threats and institutional apathy. Yet, persistent legal battles, courageous witnesses and judicial oversight have finally begun to deliver accountability. While many wounds remain unhealed, the conviction of powerful figures like Sajjan Kumar and the ongoing trial of Jagdish Tytler stand as milestones in India's fight for justice.

Negligence darkens the festival of light

The carbide-gun crisis forces India to confront a larger question: why must celebration depend on combustion?

Joy turned to tragedy in Madhya Pradesh, Bihar, and Delhi this Diwali. Across the states, at least 300 people— many of them children—suffered burns and eye injuries from carbide guns, crude explosive devices sold as festive novelties. Hospitals in MP confirmed that at least 14 children lost their eyesight, while other reports suggest up to 30 people may face permanent blindness.

These contraptions, once used to scare animals from fields, became a fad after social media videos glamourised their loud blasts and flashes, labelling them as 'PVC monkey repeller guns'. Made by mixing calcium carbide with water, they are far more dangerous than conventional firecrackers. Ophthalmologists have called them 'chemical bombs' and the All India Ophthalmological Society has demanded a national ban.

Scrambling to control the fallout, the authorities now admit that these weapons were being freely sold online and in local markets as a festive innovation. Despite multiple advisories against conventional crackers issued in previous years, enforcement remained weak. The police seized hundreds of such devices and arrested sellers only after the deaths made headlines—a familiar case of action after tragedy.Three failures stand out. First, the absence of any oversight allowed a toxic mix of chemical explosives to be marketed as trendy fireworks. Second, government or civic public awareness campaigns around fireworks safety failed to detect the new, deadlier trend. Third, a digital failure: viral social-media videos glamourising carbide blasts spread unchecked, driving demand among impressionable teenagers.The authorities must act decisively now. Enforcing the ban and prosecuting offenders is only the first step. Public awareness of the dangers must spread to all states through campaigns involving schools, civic bodies, and medical associations. Online platforms must be directed to discourage content that promotes such trends. And for the victims—especially children facing permanent blindness—the government must ensure lifelong medical and financial support.The crisis also forces India to confront a larger question: why must celebration depend on combustion? Every year, firecrackers and now chemical contraptions leave behind burns, pollution, and grief. No ritual or festival requires sacrificing safety. If Diwali truly honours light, it must begin with enlightenment—the courage to celebrate without harm, and the wisdom to keep our children safe from our own excess.

Debate and dissent, the Indian way

Critical thinking has been a part of Indian philosophy for centuries. However, Indian textbooks celebrate Socrates, Aristotle, and Descartes, while rarely mentioning Gautama, Nagarjuna, or Shankaracharya as logicians. The new education policy aims to reclaim the richness of Indian epistemology

India is often praised for its spirituality, poetry, and devotion. What is less known, and usually deliberately forgotten, is that it also built one of the world's strongest cultures of reasoning. Generations of Indian students have been taught that critical thinking began in ancient Greece, evolved in Enlightenment Europe, and entered India through English education. This version of history is incomplete and biased. India has always been a civilisation of questioning minds and debating scholars. Our schools, however, have not told this story.For decades, Indian textbooks have associated rationality with Europe and tradition with India. They celebrate Socrates, Aristotle and Descartes, but rarely mention Gautama, Kanada, Nagarjuna, or Shankaracharya as logical thinkers. As a result, young minds grow up believing that logic is foreign to our soil. Worse, they begin to assume that questioning authority is un-Indian.

Indian civilisation did not rely on unquestioning belief. It argued, debated, and demanded evidence. The country that produced yoga and ayurveda also developed powerful logic, epistemology, and debate systems. Centuries ago, Indian thinkers asked the same questions modern philosophy asks. What is truth? How do we know what we know? Can knowledge be verified? What is the difference between perception and reality? Far from being passive acceptors of tradition, Indian scholars built competing schools of thought that openly challenged one another. Disagreement was a respected intellectual practice. A short journey through India's intellectual heritage makes this clear.

The Nyaya school developed a formal system of logic that teaches how to examine claims, test evidence, and avoid errors in reasoning. It offered a five-step method to reach logical conclusions, more detailed than the three-part syllogism taught in Western philosophy. Modern students learn about Aristotle's logic, but almost none are exposed to Nyaya, which explains the same skill with greater clarity and practicality.Buddhist philosophers taught rigorous inquiry based on scepticism. Gautama warned against accepting any scriptural, social, or religious claim without testing it through experience and reflection. The Buddhist method of argumentation exposed contradictions by systematic questioning. That is the essence of critical thinking.Jain philosophy argued that truth is many-sided and cannot be captured fully from one viewpoint alone. Its method encourages students to compare interpretations before forming a conclusion. In today's world of social media polarisation, this approach teaches intellectual humility and reduces bias.

Vedanta promoted rational reflection as a path to clarity. It used disciplined questioning to remove confusion and sharpen understanding. It insisted on inquiry. Knowledge, it taught, must withstand reasoning before being accepted.

India even developed a structured tradition of debate called vada. Scholars engaged in public reasoning contests with rules for evidence, logic, and fairness. Debate was used as a method to uncover the truth. An education system that once honoured debate now silences it in the name of rote learning.When Indian students are disconnected from their own traditions of inquiry, they lose confidence in their intellectual heritage. They begin to memorise rather than think. They struggle to analyse arguments, detect false claims, or evaluate evidence. They become passive receivers of information rather than active thinkers.

In a world flooded with misinformation, fake news, and agenda-driven propaganda, reasoning skills are no longer academic luxuries. They are survival tools. India cannot become a global knowledge leader if its students cannot think independently and question intelligently..The problem is not that we teach Western logic. The problem is that we teach it alone. Indian students are given a single intellectual lens to view reason, while their civilisation's contributions are removed from sight. This creates a false hierarchy of knowledge. It breeds silent inferiority. This is not an argument against Western knowledge—the call is for fairness. Students must be trained to compare ideas, not absorb them uncritically. The National Education Policy, 2020 acknowledges that India's knowledge traditions must be restored. It states that students must develop critical thinking rooted in Indian and global perspectives. The policy encourages universities and schools to introduce Indian knowledge systems. To think freely, students must stand on intellectual ground they recognise as their own.Serious about producing independent thinkers and reclaiming Indian reasoning traditions must move from policy pages to classrooms. Teachers should be trained in Indian argumentation frameworks to use reasoning tasks in daily classes. Simple reasoning modules drawn from Nyaya, Buddhist logic, the Jain idea of many viewpoints, and Vedanta's reflective method should be introduced from Classes 6 to 12.

Nifty, Sensex End 4-Week Winning Streak Amid Profit Booking

New Delhi.(Agency)

New Delhi: Indian equity benchmarks ended their four-week winning streak, closing marginally lower this week amid profit-booking and mixed global cues. Benchmark indices Nifty and Sensex dipped 0.65 and 0.55 per cent during the week to close at 25,722 and 83,938, respectively.

Market optimism was bolstered during the first three sessions by positive domestic economic data and China's approval for few Indian companies to import rare earth magnets. However, sentiment turned cautious after the US Federal Reserve cut its benchmark interest rate by 25 basis points to the 3.75 per cent–4 per cent range."India's industrial output rose 4 per cent YoY in September 2025, supported by strong manufacturing activity. The US Federal Reserve hinted that the 25-bps cut might be the final one in 2025, which dampened hopes of further near-term easing," said Ajit Mishra- SVP, Research, Religare Broking Ltd.Further, steady corporate earnings and continued FII inflows through October helped cushion the downside, he added. Metals, energy and realty stocks were the major contributors to the rally, while auto, pharma and IT stocks experienced profit-taking."While PSU banks surged on reports of a potential hike in foreign investment limits, metal counters gleamed on renewed optimism after China's pledge to rein in steel overcapacity and signs of progress in US-China trade talks," added Vinod Nair, Head of Research, Geojit Investments Limited.Analysts said that capital market stocks lost momentum as SEBI's proposed overhaul of TER structures weighed on sentiment. Support for the Nifty is currently located close to the 25,600 zone and the 25,400 zone, while resistance is seen around 26,100, analysts said.

M&M records 26% growth in overall auto sales to over 120K units in October

CHENNAI.(Agency)

Mahindra & Mahindra Ltd on Saturday reported a 26 per cent growth in its overall auto sales at 1,20,142 units in October this year.Domestic passenger vehicle sales grew by 31 per cent to 71,624 units in October as compared to 54,504 units in the same month last year, Mahindra & Mahindra Ltd (M&M) said in a regulatory filing.Commercial vehicle sales in the domestic market stood at 31,741 units, registering a growth of 14 per cent, it added.

"In October, we achieved SUV sales of 71,624 units, a growth of 31 per cent, which is the highest SUV sales we have clocked ever in a month," M&M CEO, Automotive Division, Nalinikanth Gollagunta said.On the farm equipment business front, M&M said total tractor sales in October were at 73,660 units, as against 65,453 units for the same period last year, up 13 per cent.Domestic tractor sales were at 72,071 units, as against 64,326 units in October 2024, up 12 per cent, it added.Exports for the month stood at 1,589 units, logging a growth of 41 per cent from October last year.

"A good monsoon, combined with the benefit of the GST rate cut announced in September have supported the strong performance in September and October 2025," M&M President, Farm Equipment Business, Veejay Nakra said.

Going forward, he said factors like timely onset of Rabi sowing and good progress in Kharif harvesting augur well for tractor sales.

Amazon cloud growth boosts investor confidence amid AI spending boom

New Delhi.(Agency)

Amazon.com Inc. posted robust cloud growth that reassured investors that the tens of billions of dollars the company and its peers are pouring into artificial intelligence will pay off. In the third quarter, Amazon Web Services generated $33 billion in revenue, a 20 per cent increase from a year earlier, the company said in a statement on Thursday. The gain exceeded the 18 per cent growth that analysts had expected and marked the biggest year-over-year rise since OpenAI's ChatGPT came on the scene in late 2022.

Subscribe to the Bloomberg Daybreak Podcast on Apple, Spotify and other Podcast Platforms.

The results reinforce the logic that major technology companies such as Microsoft Corp. and Alphabet Inc.'s Google have been using to justify record spending levels on data center construction — that demand for AI is outstripping the supply of global computing capacity. Amazon's results came a day after investors punished Meta Platforms Inc. for projecting even greater spending in 2026. Unlike Microsoft and Google, Meta isn't a major cloud-computing provider to outside customers. That means its spending spree could be riskier.Amazon's shares jumped 12 per cent to $249.42 as the markets opened in New York on Friday, the biggest intraday jump since April. The stock's performance had lagged behind that of its industry peers this year, with investors worrying that the company has yet to demonstrate enough benefit from its artificial intelligence products. In its most recent quarter, Microsoft's Azure cloud business grew at almost twice the rate of AWS, while Google Cloud posted 33.5 per cent growth.Clearly AWS continues to drive the bus here, with acceleration in growth and better-than-expected operating margin," analysts with William Blair said in a research note after earnings.

The 'missing' Indian-origin CEO behind Rs 4,200 crore BlackRock loan fraud

Bankim Brahmbhatt, the Indian-origin CEO of a US-based telecom company, is facing a lawsuit in the US filed by HPS, the private credit investment arm of BlackRock.

New Delhi.(Agency)

It was just two years ago that Bankim Brahmbhatt, the Indian-origin CEO of a US-based telecom company, shot into the limelight after featuring in Capacity's Power 100 List, which recognises the top 100 leaders in the telecoms industry. The Gujarat-born Brahmbhatt now finds himself embroiled in a massive financial scandal worth a whopping $500 million (Rs 4,200 crore) involving American multinational investment company BlackRock.Brahmbhatt, who seems to have pulled off a Houdini, is now facing a lawsuit in the US filed by HPS, the private credit investment arm of BlackRock. Brahmbhatt is the owner of the little-known companies Broadband Telecom and Bridgevoice. These belong to the Bankai Group, which previously identified him on X as its president and CEO.

THE MAKING OF A $500 MILLION FRAUD

Terming it a "breathtaking" fraud, the lenders, including HPS, alleged that Brahmbhatt fabricated invoices and accounts receivable that were pledged as collateral to secure massive loans, according to a report in The Wall Street Journal.According to the report, Brahmbhatt set up a web of financing vehicles — Carriox Capital and BB Capital SPV — to raise millions of dollars from private-credit investors.

HPS, a private-credit giant recently acquired by BlackRock, started lending to

Brahmbhatt's firms in 2020. It gradually raised its exposure to $385 million in 2021, and later to around $430 million in 2024. BNP Paribas, a European banking and financial services giant, helped finance the loans issued by HPS.However, HPS had no inkling of the alleged massive fraud that was happening until July 2025. During a routine check, an HPS employee stumbled upon irregularities in customer email addresses provided by Brahmbhatt-owned companies to verify invoices.

HPS found that the email addresses were from fake domains mimicking real telecom companies. On being questioned, Brahmbhatt assured HPS that there was nothing to worry about. He later went incommunicado. A month later, on August 12, Brahmbhatt filed for bankruptcy - the same month HPS sued him.In its lawsuit, HPS also alleged that assets meant as loan collateral were transferred to offshore accounts in India and Mauritius by Brahmbhatt.

WHO IS BANKIM BRAHMBHATT?

Very little is known about Brahmbhatt. His LinkedIn profile also appears to have been deleted.Bankai Group, which claimed Brahmbhatt to be its CEO, claims to have around three decades of experience in the telecommunications industry. It sells services and infrastructure to other telecom companies.Brahmbhatt featured in Capacity's Power 100 List of 2023 for his work in the industry.

CBI links Anil Ambani, Rana Kapoor in Rs 2,796-crore Yes Bank loss case

The CBI has accused industrialist Anil Ambani of approving favours to Yes Bank founder Rana Kapoor's family, causing huge financial losses to the bank. This development highlights alleged corruption and risky investments linked to Ambani's companies.

New Delhi. (Agency)

In a major development in the Yes Bank corruption case, the Central Bureau of Investigation (CBI) has accused industrialist Anil Ambani of approving favours extended to the family of the bank's founder Rana Kapoor, allegedly in violation of established credit policy. The agency, in its detailed chargesheet filed before a special CBI court in Mumbai, claims that Yes Bank suffered losses of Rs 2,796.77 crore due to risky investments in Non-Convertible Debentures (NCDs) and Commercial Papers (CPs) of Ambani's companies.

According to investigators, Kapoor was aware that these investments carried no viable secondary market and would damage the bank's long-term interests, but went ahead with them after Ambani's approval.

TWIN FIRs AND A Rs 5,000-CRORE INVESTMENT GONE BAD

Two FIRs were registered following complaints from the Chief Vigilance Officer (CVO) of Yes Bank in November 2020. They accused Kapoor, Ambani, and several senior executives of criminal conspiracy, cheating, and corruption.Between 2017 and 2019, Yes Bank invested Rs 2,965 crore in Reliance Home Finance

Ltd (RHFL) and Rs 2,045 crore in Reliance Commercial Finance Ltd (RCFL), both part of the Anil Dhirubhai Ambani Group (ADAG). By late 2019, both turned into non-performing investments, leaving the bank with unpaid dues of over Rs 3,300 crore.

LOANS TO KAPOOR'S FAMILY FIRMS

The CBI alleges a quid pro quo arrangement between the two sides. Around the same period, RHFL and RCFL disbursed multiple loans to companies owned by Kapoor's wife Bindu Kapoor and their daughters.

Rs 60 crore each was sanctioned to RAB Enterprises (India) Pvt Ltd and Bliss House Pvt Ltd, both owned by Bindu Kapoor.Rs 225 crore each went to RAB Enterprises and Imagine Estate Pvt Ltd, also controlled by her.

The loans, given at 9.25% annual interest, were allegedly cleared without field verification or due diligence.

PRIVATE MEETINGS, MUTUAL BENEFITS

The chargesheet paints a picture of close coordination between Kapoor and Ambani. CBI claims that Kapoor frequently held private business meetings with Ambani, often without any Yes Bank officials present. After these meetings, Kapoor would allegedly instruct his officers to approve proposals for ADAG companies as "agreed upon."

In turn, Ambani allegedly directed his own key executives to relax loan conditions for companies owned by the Kapoor family.

Man Got Income Tax Notice After Depositing Rs 8 Lakh – Here's How He Fought Back And Won

New Delhi. (Agency)

If you're planning to deposit a large amount of cash into your bank account, you might want to think twice before doing so without proper documentation. In one recent case, a hefty cash deposit caught the attention of the Income Tax Department. This led the assessing officer to classify it as presumptive business income. Here's what happened and why such deposits can raise red flags with tax authorities.It all started when a Delhi resident, Kumar, deposited Rs 8.68 lakh in his bank account — a move that soon drew the attention of the Income Tax Department. Shortly after, he received a notice, as the department classified the amount as business income and initiated proceedings under Section 44AD of the Income Tax Act — a provision meant for presumptive taxation of small businesses. What seemed like a routine deposit soon escalated into a lengthy legal dispute.After losing his first appeal before the Commissioner of Income Tax (Appeals), Kumar decided to take his fight to the Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) in Delhi. His persistence paid off on September 22, 2025, the tribunal ruled in his favour, as reported by News18.

The ITAT observed that the original enquiry under

Section 143(2) of the Income Tax Act was meant only to verify the source of the cash deposits. However, the assessing officer exceeded his authority by treating the entire amount as undisclosed business income without seeking prior approval from the Commissioner of Income Tax (CIT).

Tribunal Cites Legal Precedent

Drawing on a ruling by the Calcutta High Court, the ITAT concluded that expanding the scope of enquiry beyond its original purpose was not legally justified. The tribunal noted that both the assessing officer and the appellate authority had gone beyond their jurisdiction by treating the bank deposits as taxable income. Declaring the entire investigation invalid, the ITAT set aside all related assessments and tax demands — freeing Kumar from any tax or penalty on the disputed amount.

Studds Accessories IPO: Subscribed 5 times on Day 2; GMP steady | Should you bid

Kolkata . (Agency)

A formidable player in the two-wheeler helmet market in India and abroad, Studds Accessories IPO has received applications amounting to 5.08 times overall on the second day of the bidding process. It has garnered subscription of 6.03 times in the retail category, 0.04 times in QIB (ex anchor) category and 9.62 times in the NII category by the end of October 31. The bidding window will close on November 3.Studds Accessories IPO is a book built issue of Rs 455.49 crore, which will be mobilised through an offer for sale of 0.78 crore shares. The point to note is that the proceeds of sale of any OFS share go to the seller and not to the company. The helmet maker mopped up about Rs 137 crore from anchor investors, a few of which were

HDFC Mutual Fund (MF), Nippon India MF, ICICI Prudential MF, Edelweiss MF, ITI MF, Kedaraa Capital Public Markets Fund I, Carnelian India Amritkaal Fund, Pinebridge India Equity Fund, and Edelweiss Life Insurance Company.Kolkata: A formidable player in the two-wheeler helmet market in India and abroad, Studds Accessories IPO has received applications amounting to 5.08 times overall on the second day of the bidding process. It has garnered subscription of 6.03 times in the retail category, 0.04 times in QIB (ex anchor) category and 9.62 times in the NII category by the end of October 31. The bidding window will close on November 3.Studds Accessories IPO is a book built issue of Rs 455.49 crore, which will be mobilised through an offer for sale of 0.78 crore shares. The point to note is that the proceeds of sale of any OFS share go to the seller and not to the company. The helmet maker mopped up about Rs 137 crore from anchor investors.

Weekly review: Gold prices ease during the week amid firm dollar and profit booking

In the Indian market, gold mirrored the global trend and traded lower through the week.

New Delhi.(Agency)

CHENNAI: Gold prices declined through the week ended October 31, tracking weakness in international markets as the US dollar strengthened and investors booked profits after recent record highs.

In the global market, spot gold slipped below the psychological level of $4,000 per ounce during the week, marking its first significant correction in several weeks. Prices fell to around $3,960–$4,010 per ounce between October 27 and 31, pressured by a stronger dollar and rising expectations that the US Federal Reserve may delay interest rate cuts. Analysts described the pullback as a "healthy correction" following the sharp rally earlier in

October, when gold had briefly touched an all-time high above $4,380 per ounce. The US Commerce Department data and firm Treasury yields also weighed on sentiment, as investors shifted focus from safe-haven assets to higher-yielding investments. However, analysts said the long-term outlook for gold remains positive, supported by sustained central bank buying and lingering geopolitical uncertainties.In the Indian market, gold mirrored the global trend and traded lower through the week. On October 27, 24-carat gold was quoted around Rs 1,24,000 per 10 grams, before easing to about Rs 1,22,000 by the end of the week. Prices fell by roughly Rs 1,500–Rs 2,000 per 10 grams across major cities including Delhi, Mumbai, and Chennai. Silver also moved in tandem, shedding more than half a percent over the week.

Traders attributed the decline to a combination of international cues and a stronger rupee, which reduced import costs. Retail demand remained steady ahead of the wedding season, though investors adopted a cautious stance amid volatility in global prices.Analysts believe the current correction may offer short-term buying opportunities for consumers, particularly if gold stabilizes above Rs ?1,20,000 per 10 grams. However, they expect near-term movements to remain range-bound, influenced by US economic data, currency fluctuations, and global risk sentiment.

Overall, gold ended the week on a softer note but retained a broadly positive medium-term outlook, with investors watching for fresh triggers from global monetary policy signals and geopolitical developments.

41 years on, justice still eludes 1984 anti-Sikh riot victims: Only 13 murder convictions, 253 cases ended in acquittals

Agency New Delhi.

More than 2,700 members of the Sikh community were murdered in four days of violence in the capital in the aftermath of the assassination of then Prime Minister Indira Gandhi by her Sikh bodyguards on October 31, 1984. Forty-one years on, the wait for justice continues for most victims of the carnage.

Just 28 cases have ended in convictions to date. Thirteen of these convictions are in murder cases – this number is less than the number of committees and commissions that were set up over the years to investigate cases relating to the anti-Sikh riots.

The Justice G T Nanavati Commission set up by Atal Bihari Vajpayee's NDA government in 2000, one of the 14 panels that investigated the violence, found that 587 FIRs were registered in Delhi, 241 of which could not be traced. Another 253 cases had ended in acquittals.Story continues below this ad

Of the remaining FIRs, 40 were pending trial, and one was pending investigation at the time. Eleven FIRs had been quashed; in another 11, the accused had been discharged. Three cases had been withdrawn.On February 12, 2015, in the first term of the Narendra Modi government, the Union Home Ministry constituted a special investigation team (SIT) to "re-investigate appropriately" the "serious" criminal cases that had been filed in Delhi but had been closed subsequently.

A total 293 cases that had been closed and for which untraced reports had been filed, were scrutinised. After going through case records for months, the SIT closed 199 of these cases, primarily because of "incomplete, illegible" records or the absence of witnesses.In 60 of the remaining cases, the SIT launched a preliminary enquiry, but in the absence of evidence or witnesses, 52 of them ended in closures. Police filed chargesheets in five of the remaining eight cases. One of these ended in an acquittal, another is pending in Delhi's Karkardooma Court.

Two men detained for chasing woman journalist on Delhi flyover

New Delhi. (Agency)

Two men were detained on Friday for allegedly chasing a 35-year-old woman journalist while she was returning home from her office. On Friday at 1:27 am, a PCR call was received at Lajpat Nagar police station reporting that two persons on a scooter were allegedly following a woman on the Lajpat Nagar flyover and had damaged her vehicle. Police reached the location within minutes to ensure her safety, a senior police officer said.

The woman, a producer with a private news channel, was returning home after work from Noida. At around 12.45 am on Mahamaya Flyover, two men intercepted her and asked her to stop, but she overtook the scooter, following which its riders began to follow her, the officer said. She did not stop and drove towards a safer location, police said. A case was registered, and both accused, identified as Shubham and Deepak, were detained. They have been previously involved in many criminal cases.

Cloud seeding can't be a reliable fix for Delhi's winter pollution: IIT-Delhi study

New Delhi. (Agency)

Cloud seeding cannot be a "primary or reliable strategy" to manage winter air pollution in Delhi as the capital is climatologically unsuitable for it, a study carried out at the Indian Institute of Technology Delhi (IIT Delhi) has concluded.

Cloud seeding, the study says, "should be viewed, at best, as a potential high-cost, emergency short-term measure, contingent on stringent forecasting criteria". It underscores that "sustained emission reduction remains the most viable and necessary long-term solution" to the problem of air pollution.

The report, prepared this month at the Centre for Atmospheric Sciences (CAS) IIT Delhi, is the outcome of a "comprehensive analysis integrating climatological data (2011-2021), aerosol-cloud interaction assessments, and pollutant washout/recovery"The Delhi government conducted two back-to-back cloud seeding trials on October 28, in which a team from IIT-Kanpur flew a small aircraft over parts of Delhi and released silver iodide and salt particles in flares.

The idea was to induce artificial rain, and thus reduce air pollution above the capital. Rain is believed to reduce air pollution because it acts as a natural cleansing mechanism, washing soluble gases out of the atmosphere and depositing particulate matter on the ground.

CM Rekha Gupta hits back at AAP over pollution row, says AQI data cannot be tampered with

Agency New Delhi.

Chief Minister Rekha Gupta on Friday lambasted AAP and said that pollution data cannot be tampered with and advising the "unemployed" opposition to stick to singing songs.

Her response came after AAP leaders criticised the Rekha Gupta government on failed cloud seeding through a parody song of 'Barsaat bhi aakar chali gayi, baadal bhi garaj kar baras gaye'. They went on to sing, 'Rekha ka jhut sun-sunkar, sacchi baarish ko taras gaye' (Hearing Rekha's lies again and again, we're yearning for real rain).AAP had also raised accusations that the BJP government in Delhi shut down pollution monitoring stations and manipulated Air Quality Index data on Diwali night to conceal the situation."There is something wrong with the Aam Aadmi Party's (AAP) thinking. The problem with the AAP is that if AQI goes down, they will say the data is fudged. If the AQI increases, how is it increasing? It is not our job to answer their nuisance. We are working honestly to address the pollution problem in Delhi," she said.

Asserting that AQI data can neither be tampered with nor manipulated, she said, "Anyone can get the AQI of a particular location." AAP is unemployed. They were singing a song that day, so they should stop bothering people and continue that.

From Vivaldi to Frank Sinatra: Symphony Orchestra of India to bring a rare Western classical musical treat to Delhi

Agency New Delhi.

When the Symphony Orchestra of India (SOI), the country's only professional orchestra housed at Mumbai's National Centre for the Performing Arts (NCPA), takes centre stage at Delhi's Travancore Palace this Sunday as part of 'NCPA@The Park', it will mark the continuation of a cultural initiative born during the pandemic. When concert halls stood empty and live music fell silent, the NCPA decided to take music out of auditoriums and into the city's parks.

Three years ago, the multi-venue cultural organisation — founded in 1969 by JRD Tata and Dr Jamshed Bhabha — launched 'NCPA@The Park' in collaboration with the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC), staging free concerts at Cooperage Fort, Narali Baug in Shivaji Park, and Powai's Hiranandani Gardens, as well as one in a Bengaluru park. "These were a way for us to bring new audiences for Western classical music. We were quite successful. This year, we've decided to bring the concept to the Capital," says Bianca Mendonca, General Manager, SOI and Western Classical Music, NCPA.

Delhi will be treated to a range of Western classical compositions, including works by Baroque-era legend Antonio Vivaldi and Austrian composer Haydn, who influenced Mozart and Beethoven. Russian composer and creator of some of the greatest ballets, Tchaikovsky's well-known Christmas classic — the famed waltz from The Nutcracker — will also be performed, alongside short pieces from the oeuvres of Schumann, Brahms and Strauss. The concert will culminate in an ode to American icon Frank Sinatra — one of the 20th century's most influential musicians. This will be followed by a performance from Delhi's jazz-funk ensemble, The Revisit Project, which will improvise on Hindi film melodies by RD Burman, AR Rahman and Shankar-Ehsaan-Loy.Mendonca says the aim is to spark interest in Western classical music among Delhi audiences. She believes that programming lighter pieces by avoiding full symphonies and instead opting for shorter four- to five-minute works helps.

Delhi government to grant recognition to private schools in non-conforming areas under RTE Act

Agency New Delhi.

The Delhi government has decided to grant recognition of private unaided schools in non-conforming areas. The initiative will ensure full compliance with Article 21A of the Constitution and the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (RTE Act). Delhi education minister Ashish Sood said that this was a long-pending reform that restores the constitutional right to education for thousands of children across the city.

According to this decision, all private unaided schools that have been functioning in non-conforming areas for a long time but have not yet obtained recognition from the directorate of education, either due to procedural reasons or due to the discriminatory approach of previous governments, can now apply for recognition from the DoE.

The DoE's online portal for submission

of applications will open on November 1, 2025. All schools willing to seek recognition may apply till November 30, 2025. After the completion of the application process, the applications will be scrutinised, and a list of such schools that meet all the prescribed criteria for recognition will be issued.

The education minister said that for over a decade this issue remained buried in files while children were denied their constitutional right to education. Previous governments played favouritism, recognising a few while neglecting many. This is not just administrative reform; it is justice for our children, fairness for our institutions and a genuine step towards democratising education in Delhi."By turning a decade-old challenge into a people-first reform, the Delhi government has set a new standard in equitable education governance, a milestone that will be remembered as a defining chapter in the city's education journey," Sood said. He further said that the last recognition drive was conducted in 2013, benefiting only a few schools through selective approvals. For more than ten years, many schools in non-conforming areas operated without recognition due to bureaucratic apathy and policy paralysis of past regimes.

Delhi govt to recognise schools in non conforming areas, adds 20,000 new seats for underprivileged students

Agency New Delhi.

The Delhi government has decided to grant recognition to private unaided schools operating in non-conforming areas, clearing the way for the generation of around 20,000 new seats for students from Economically Weaker Sections (EWS), Disadvantaged Groups (DG), and Children with Special Needs (CWSN), officials said.The development will bring nearly 500 schools under the purview of Directorate of Education (DoE), officials added. The DoE's online portal will open for applications from November 1 to 30, 2025, after which eligible schools meeting prescribed norms will be granted recognition.

Education Minister Ashish Sood said the decision resolves a decade-old issue that had left many schools functioning without formal recognition.

"For over a decade this issue remained buried in files while children were denied their constitutional right to education. Previous governments played favouritism, recognising a few while neglecting many…This is not just administrative reform, it is justice for our children, fairness for our institutions, and a genuine step towards democratising education in Delhi," said Sood.

According to officials, the move marks the first such recognition drive since 2013. The decision, officials noted, ensures compliance with Article 21-A of the Constitution and the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (RTE Act).

Sood said the policy "sets a new standard in equitable education governance – a milestone that will be remembered as a defining chapter in the city's education journey."

The government said recognition will bring these schools under DoE's purview, ensuring compliance with norms on infrastructure, safety, teacher qualifications, and fee transparency. It also enables them to upgrade to higher levels, ensuring continuity for students, said officials.

Jamia Millia Islamia students protest 'saffron narrative' in events at Foundation Day

Agency New Delhi.

The 105th Foundation Day celebrations of Jamia Millia Islamia have sparked controversy after several students' organisations issued a joint statement opposing events, which they say "contradict the university's secular and inclusive values". The six-day celebration, which began on October 29 and runs through November 3, features a music and dance performance titled 'Akhand Bharat', scheduled for November 1 at the Safdar Hashmi Amphitheatre, along with a singing performance by the Delhi Police on November 2.

In their statement, the student groups, including AISA, AIRSO, AISF, DISSC, CRJD, Fraternity Movement, MSF, SFI and the Common Students of Jamia Millia Islamia, said the programme "foresees a series of events that seem less about celebrating Jamia's century-long commitment to inclusive nation-building and more

about signalling a shift towards a saffronised narrative of nation and campus".The statement further said, "A singing performance by the Delhi Police, a music and dance programme on the theme of 'Akhand Bharat', and a Kavi Sammelan featuring invited state-sponsored Sangh-Parivar functionaries are centrally featured."

The student groups also condemned what they called the "silent imposition" of the National Education Policy (NEP) 2020, saying it "has structurally attacked the higher education access of Muslim and oppressed communities" and accused the university administration of "sacrificing minority rights at the altar of political obedience".

"Jamia Millia Islamia has the dual task of simultaneously critiquing and serving the nation. Any attempt to convert this university purely into a service-unit or a mouthpiece for Hindutva ideology is a betrayal of its founding mission," the statement read.

Delhi's fifth season of pollution turns into battle for the right to breathe

Studies reveal how vehicular emissions, industrial discharge, construction dust, and crop residue burning combine each winter to choke the capital.

Agency New Delhi.

The Constitution of India guarantees every citizen the right to life under Article 21, a phrase our courts have rightly expanded to mean not mere existence, but a life lived with dignity, health, and ecological balance. Clean air, therefore, is not a privilege, but a constitutional entitlement.

Yet, each winter, Delhi seems to enter what may be called a fifth season, the season of pollution, where the very air that sustains life becomes its greatest adversary. Ancient India regarded air as sacred: the Manusmriti declares, "Pawan shudhi sarvabhutanaam" (air is the purifier of all beings). Today, the purifier itself cries out for purification. This inversion of nature's order is not merely an environmental failure; it is a civilisational breach, demanding that environmental law be asserted as the modern embodiment of the moral and natural order that sustains creation.

India's classical poets saw rhythm in the succession of seasons, six in harmony, each completing the other. Kalidasa, in the Ritusamhara, sang of this balance: "At the meeting of winter and spring, the groves shine forth with blossoms." But Delhi today knows a new rhythm, the Pollution Season, which descends between autumn and winter, not with blossoms but with smog. The Vedic declaration "The seasons unfolded with the very act of creation" once symbolised harmony between man and nature; today it stands shattered by human excess.

The city's carrying capacity, its ability to absorb pollutants, has long been breached. Studies reveal how vehicular emissions, industrial discharge,

construction dust, and crop residue burning combine each winter to choke the capital. Nestled within the Indo-Gangetic plain, hemmed in by the Himalayas and the Aravallis, Delhi becomes a bowl of stagnating air, a trap for its own breath.

This is not an atmospheric inconvenience, but a constitutional crisis. The High Court of Delhi once likened the capital to a "gas chamber", capturing the desperation of a city where governance has failed to deliver on its most basic duty to protect life of its citizens. According to the IQAir 2024 World Air Quality Report, Delhi's particulate matter levels are nearly 15 times higher than WHO limits, a grim measure of collective negligence. Citizens now prepare for this "fifth season" not with celebration, but with survival kits, air purifiers, N95 masks, sealed windows, and antioxidant diets, all in an attempt to endure what should have been a simple, natural transition of weather.

NEWS BOX

Trump Unveils Another Makeover To White House: Renovated Lincoln Bathroom

United States . (Agency)

Knocking down the East Wing of the White House apparently wasn't enough for Donald Trump.

The US president unveiled yet another makeover to the storied residence on Friday, showing off a marble-and-gold renovation of the Lincoln Bathroom.

The old version dating back some 80 years had pale green tiles and strip lights, according to a picture posted by Trump on his Truth Social network.

But now, it has gold taps and mirrors, along with lavish white and gray marble walls, Trump revealed in more than two dozen photos in a string of posts.

"I renovated the Lincoln Bathroom in the White House. It was renovated in the 1940s in an art deco green tile style, which was totally inappropriate for the Lincoln Era," Trump wrote on Truth Social."I did it in black and white polished Statuary marble. This was very appropriate for the time of Abraham Lincoln and, in fact, could be the marble that was originally there!"

It comes just days after Trump sparked controversy by demolishing the entire East Wing of the White House in October to build a giant new $300 million ballroom.But the bathroom renovation is the first major work done on the executive mansion of the White House itself. The Lincoln Bathroom is near the Lincoln Bedroom, an ornate room on the second floor of the mansion where the US president lives.The Lincoln Bedroom used to be the late president's office and cabinet room, and was renamed in 1945 when President Harry Truman ordered furnishings from the Lincoln era to be placed there, according to the White House Historical Association.

K-Beauty, K-Pop, Fried Chicken: What Happens When APEC Meets Korean Culture

South Korea.(Agency)

World leaders and business titans gathered in South Korea this week to hash out issues from tariffs and AI to disputed history and regional security.

But beyond the staid statecraft, the summit and sideline events featured plenty of nods to the host country's vibrant pop culture and history.

Trump's Golden Crown

US President Donald Trump may be facing "No Kings" protests back home, but in South Korea, officials had the perfect gift for the gold-loving magnate -- a replica of an ancient royal crown.At a lavish ceremony in the historic capital of Gyeongju, Trump was presented with a replica of the "largest and most extravagant" gold crown from the Silla dynasty, which ruled from 57 BC to 935 AD.Catering to the US leader's fondness for the precious metal, President Lee Jae Myung wore a gold tie and Trump was also served a gold-themed dessert.

Meanwhile, across the United States, protesters have decried Trump's "king-like" presidency. After news of the gift broke, memes mocking a crowned Trump flooded social media.

K-Beauty Haul

Karoline Leavitt, the often-combative White House press secretary, drew social media attention after posting her K-beauty haul on Instagram while accompanying Trump in Gyeongju."South Korea skincare finds," the 28-year-old captioned an Instagram story -- complete with a heart-eyes emoji -- showcasing a cleansing oil, face masks, "zero pore" pads, moisturiser and other K-beauty staples.

South Korea, well known for its beauty products and advanced skincare and dermatological treatments, has been working to strengthen its foothold in the global market.

White House Restricts Reporters' Access To Part Of Press Office

Washington .(Agency) :

US President Donald Trump's administration on Friday barred reporters from accessing part of the White House press office without an appointment, citing the need to protect "sensitive material."

Journalists are now barred if they do not have prior approval to access the area known as Upper Press -- which is where Press Secretary Karoline Leavitt's office is located and is near the Oval Office.

Reporters have until now been able to freely visit the area, often wandering up to try to speak to Leavitt or senior press officers to seek information or confirm stories.Media are still allowed to access the area known as "Lower Press," next to the famed White House briefing room, where more junior press officers have their desks, the memo said.The policy comes amid wider restrictions on journalists by the Trump administration, including new rules at the Pentagon that major outlets including AFP refused to sign earlier this month. The change at the White House was announced by the National Security Council in a memorandum titled "protecting sensitive material from unauthorized disclosure in Upper Press.""This memorandum directs the prohibition of press passholders from accessing... 'Upper Press,' which is situated adjacent to the Oval Office, without an appointment," said the memo, addressed to Leavitt and White house Communications Director Steven Cheung.This policy will ensure adherence to best practices pertaining to access to sensitive material."

It said the change was necessary because White House press officers were now routinely dealing with sensitive materials following "recent structural changes to the National Security Council."Trump has gutted the once powerful NSC, putting it under the control of Secretary of State Marco Rubio, after former National Security Advisor Mike Waltz was reassigned in May following a scandal over the use of the Signal app to plan strikes on Yemen.Trump's administration has made a major shake-up to access rules for journalists since his return to power in January.

China's Xi to meet South Korean leader, capping APEC summit

On the final day of his first trip to South Korea in over a decade, Xi will meet with Lee on the sidelines of the Asia-Pacific Cooperation Organisation summit, held this year in the city of Gyeongju.

GYEONGJU . (Agency)

Chinese President Xi Jinping will sit down with South Korean counterpart Lee Jae Myung on Saturday, capping an Asian summit at which Beijing and Washington agreed to a truce in their trade war.On the final day of his first trip to South Korea in over a decade, Xi will meet with Lee on the sidelines of the APEC (Asia-Pacific Cooperation Organisation) summit, held this year in the city of Gyeongju.On Thursday, Xi met with Trump in the nearby city of Busan, with the two agreeing to dial down a trade dispute that roiled markets and disrupted global supply chains.Trump chse to return to the United States following those talks, leaving the Chinese leader to take centre stage at a summit in which he has framed Beijing as the defender of the multilateral order against "hegemonism".Speaking at the summit's closing ceremony on Saturday, Xi said next year's APEC meeting would take place in the southern Chinese city of Shenzhen.Xi met on Friday with Canadian Prime Minister Mark Carney on the sidelines of the meet -- the first formal talks between the two countries' leaders since 2017.He told the Liberal leader he was determined to work together to get relations back on the "right track" and invited Carney to visit China.Xi also sat down with Japan's premier Sanae Takaichi for the first time since she was appointed last month.She said she told Xi that she wants a "strategic and mutually beneficial relationship between Japan and China".

But she told reporters that she also raised a number of thorny issues with the Chinese leader, saying that it was "important for us to engage in direct, candid dialogue".

The Chinese leader now turns his attention to the South Korean President in what will be their first sit-down meeting since Lee's election in June.Lee to 'reassure' Beijing

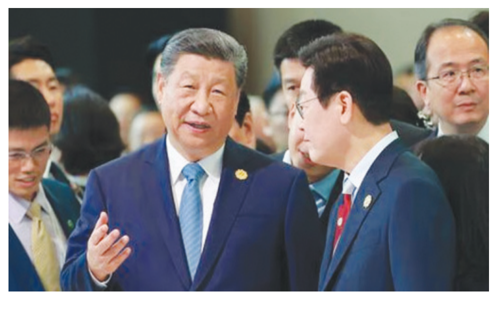

Seoul has long trodden a fine line between top trading partner China and defence guarantor the United States.Relations with China soured in 2016 after Seoul agreed to deploy the US-made THAAD missile defense system.Beijing hit back with sweeping economic retaliation, restricting South Korean businesses and banning group tours.Cultural spats -- including China's claims over the origins of the Korean staple dish Kimchi -- have also soured public opinion against Beijing.

"Public opinion matters in foreign policy," Gi-Wook Shin, a Korea expert and sociology professor at Stanford University, told AFP."Public perception of China in South Korea is highly negative. I suppose the Chinese view of South Korea is not favourable either," he said.South Korea -- which this week also agreed a multibillion dollar economic deal with the United States -- remains heavily dependent on trade with its vast Asian neighbour.Lee will likely try to "reassure Beijing that South Korea's alignment with the United States does not preclude pragmatic economic engagement with China," Seong-Hyon Lee, a scholar at the Harvard University Asia Center.

The South Korean leader is keen to "seek a measure of economic stability and a more predictable floor in bilateral relations," he told AFP.

Indian-origin man at the centre of USD 500 million loan fraud in US

World. (Agency)

BlackRock's private credit arm, alongside other lenders including BNP Paribas's HPS Investment Partners, is fighting to recoup over USD 500 million in an alleged fraud involving telecom-services companies owned by an Indian-origin man Bankim Brahmbhatt, according to a report from The Wall Street Journal. The lenders filed a lawsuit in August, alleging Brahmbhatt's companies, including Broadband Telecom and Bridgevoice, used fake accounts receivable as collateral for loans.The Journal's reporting highlights that the firms now owe the lenders more than USD 500 million. The dispute centres on a kind of debt deal known as asset-based finance, where the borrower puts up collateral in the form of revenue generated by specified businesses, equipment, or customer receivables. This type of debt, once seen as having grown significantly, now rests with a small group of private-credit investors, which includes BlackRock's mammoth global credit arm, GIP HPS.According to the WSJ, the lenders allege that they discovered discrepancies when performing an internal check that led to their suspicion of fraud. The lawsuit claims Brahmbhatt created an elaborate scheme of fake email domains and customer lists dating back to 2018. Brahmbhatt's companies allegedly sold off-chain finance assets in India and Mauritius, according to the lawsuit.Brahmbhatt's telecom companies had filed for bankruptcy in August, shortly after the lenders' lawsuit. The WSJ notes that earlier this year, an employee received strange, un-solicited emails, which are now believed to have been an attempt to fabricate records. While Brahmbhatt has, through his attorney, denied the fraud allegations, the lenders are determined to recover the massive sum. The paper states that "The investment represents a fraction of HPS's USD 179 billion in assets under management," yet underscores the growing scrutiny on private-credit deals.Meanwhile, a Bloomberg report quoted BNP as saying that its trading unit took a USD 190 million (USD 220 million) hit in the third quarter to account for "a specific credit situation." Executives at the firm declined to name the clients in question, but they also insisted the hit was a one-off and not emblematic of a worsening credit environment.

"We had one specific file in global markets, but we don't give any colour or names," BNP Paribas Chief Financial Officer Lars Machenil said in an interview on Bloomberg Television. "But it is not a usual suspect, it is in the sphere of payment."

Explosion at New Mexico oil refinery sends thick smoke across Artesia

ARTESIA. (Agency)

Emergency crews responded Friday to an explosion at an oil refinery in New Mexico as thick smoke emerged from the plant and drifted across parts of the city of Artesia before crews were able to extinguish the flames.Navajo Refinery operator HF Sinclair said that the fire had been extinguished and that three people were transported off-site for medical attention. No other injuries were reported.Air monitoring on the perimeter of the refinery and in a nearby community showed no risk to public safety, said Corinn Smith, a spokesperson of HF Sinclair. It was unclear whether refinery production was affected.

Artesia Police Commander Pete Quiñones said that police and other first responders scrambled to the site before the fire was contained.

Authorities said the smoke had dissipated by Friday afternoon and roads were reopened. The New Mexico Environment Department said it was sending a team to Artesia to assess conditions and monitor air quality.

The refinery sits adjacent to Artesia's main intersection, which serves as an artery from the Permian Basin in the southeastern corner of the state to the rest of New Mexico. The company's website notes that the facility has a crude oil capacity of 100,000 barrels per day, making it the largest in New Mexico, but it wasn't immediately clear how full the plant was at the time of the incident.The plant serves markets in the southwestern United States by processing oil acquired from the basin, which is one of the busiest in the world. It operates alongside a refining facility in Lovington, about 65 miles (105 km) away.

HF Sinclair, headquartered in Dallas, Texas, also owns and operates refineries in Kansas, Oklahoma, Wyoming, Washington state and Utah.

Indians Key To Tech Leadership: Lawmakers Urge Trump To Ease H-1B Visa Curbs

GYEONGJU.(Agency)

US lawmakers have urged President Donald Trump to reconsider his proclamation on H1-B visas, including the USD 100,000 fee, asserting that Indian nationals are central to American leadership in IT and AI, and the restrictions will negatively impact US-India ties.US Representative Jimmy Panetta along with Members of Congress Ami Bera, Salud Carbajal and Julie Johnson wrote to Trump on Thursday.The lawmakers expressed concern over Trump's 'Restriction on Entry of Certain Nonimmigrant Workers' proclamation on the H1-B visa programme that imposes a USD 100,000 fee on new petitions amid other restrictions.They urged him to reconsider his September 19 proclamation in light of the decision's potentially negative impacts on the US-India relationship."As members of a recent delegation to India, we recognise the importance of the H-1B programme not just to the United States economy, national security, and competitive advantage, but also to our relationship with India, and to the Indian-American communities that we represent. We respectfully request that you suspend the September 19 proclamation and reconsider any

policy that would decrease appropriate access to the H-1B programme," the lawmakers said in the letter.They added that at a time when China is "investing aggressively" in artificial intelligence and advanced technologies, the US must continue to attract the world's best talent to maintain its "innovation ecosystem, strengthen the defence industrial base, and preserve its long-term competitive edge"."In the case of India, the country of origin for 71 per cent of H-1B holders last year, attracting this talent also reinforces our strategic partnership with a key democratic partner in the Indo-Pacific," they said.The lawmakers described the H-1B programme as a "cornerstone" of US competitiveness in science, technology, engineering, and mathematics (STEM). They added that research consistently shows that H-1B professionals boost US innovation, patent production, and business formation, complementing rather than displacing American workers. "Indian nationals, who make up the largest share of H-1B recipients, are central to US leadership in information technology and artificial intelligence."

They stressed that many of America's most successful companies were founded or led by former H-1B holders, who "drive new businesses, job creation, and keep the United States at the forefront of technological progress"."Indian-Americans and other H-1B holders also comprise a thriving constituency in each of our districts.

Argentina's chief of staff resigns, heralding change for President Milei after election win

BUENOS AIRES . (Agency) \

The chief of staff to President Javier Milei of Argentina resigned on Friday, less than a week after the governing party won a new mandate to accelerate his program of radical reform in pivotal midterm elections.Guillermo Francos, a 75-year-old career politician with decades of experience at the heart of government, said in a statement that he was stepping down so that Milei "may face without constraints the stage of government that begins after the national elections."Francos' departure after weeks of speculation was expected to herald a wider Cabinet shake-up, as is common in Argentina following elections. Interior Minister Guillermo Catalán followed suit on Friday.Riding high off his party's surprise landslide win in Sunday's legislative elections and $40 billion in pledged funds from a friendly Trump administration, Milei announced that his main spokesperson, Manuel Adorni — an ideological defender of the president's agenda known for his combative press conferences littered with sarcastic one-liners — would replace the even-tempered Francos as Cabinet chief.Many far-right supporters of Milei's anti-establishment platform viewed Francos, who hails from Argentina's traditional political elite, with suspicion. But political rivals and lawmakers hostile to Milei's agenda considered him a confidant.Francos was appointed chief of staff last year as the irascible political outsider sought help from the seasoned negotiator in persuading Congress to pass wide-ranging economic overhaul measures to trim the fiscal budget and spur foreign investment. Before his promotion, Francos served as interior minister, charged with managing Milei's tense relations with provinces opposed to the government's budget cuts.

Milei thanked Francos in a statement for "his service to the nation during these last two years of profound reforms that required continuous dialogue with various political forces."He said that, starting on Monday, Adorni would assume the role of chief of staff in response to their party's resounding victory that surpassed pollsters' expectations, injected energy into faltering

reforms and gave their scrappy libertarian party the numbers it needed in Congress to defend presidential vetoes."This change responds to the election results, the need to renew political dialogue and the beginning of this second phase," Milei said.Although Milei's La Libertad Avanza bloc has boosted its numbers in Congress enough to prevent the left-leaning opposition from passing spending measures that undermine fiscal austerity, the party still lacks a majority.

To see through his free-market overhaul of Argentina's economy, Milei has acknowledged the need to build alliances with centrist parties and win over influential provincial governors.Top of the agenda will be liberalizing Argentina's labor market and simplifying its byzantine tax system — big goals that have vexed right-wing governments before. To show his openness to dialogue, Milei welcomed 20 of Argentina's 24 governors to the presidential headquarters on Thursday.

The four governors excluded from the meeting represented Peronism, the populist opposition movement widely blamed for delivering the economic shambles that Milei inherited in 2023.

NEWS BOX

India's Melbourne blunder: Should Abhishek Sharma have shown better game awareness

New Delhi. (Agency)

IAbhishek Sharma may have been the lone bright spot for India in the second T20I against Australia, but former cricketer Irfan Pathan believes that the young batter still has plenty to learn about game awareness. Despite Abhishek's fighting 68 off India's total of 125 runs in Melbourne, he was unable to prevent India from collapsing to a heavy defeat on Friday, October 31.While Abhishek's innings stood out as his maiden international fifty on Australian soil, Pathan said that the left-hander must focus on developing his tactical understanding, particularly when batting with lower-order partners. Speaking on his YouTube channel, Pathan pointed out that Abhishek needed to take greater responsibility during his partnership with fast bowler Harshit Rana, which briefly steadied the innings after a disastrous start.Pathan observed that Abhishek's innings could be divided into two distinct phases: the explosive start during the powerplay, when he took on the Australian pacers with confidence, and the later phase, when he lost control of the tempo and failed to farm the strike effectively.Abhishek Sharma once again showed that while everyone else seemed to be batting on one pitch, he was batting on another. It was a brilliant half-century, a superb innings, but if

you look closely, you'll notice it had two parts. During the powerplay, he batted beautifully, but after it ended, he should have continued with the same intent and awareness, which he didn't," Pathan said on his channel.The numbers support Pathan's assessment. Abhishek faced 37 deliveries in an innings that stretched till the 19th over, while Harshit Rana, who came in outside the powerplay, played nearly as many — 33 balls.This meant that during their 47-ball partnership, Abhishek faced just 14 deliveries. He scored 18 runs off those, while Harshit contributed 35 from 33 balls after a slow start to his innings.

Into the final, but flaws remain: India must find their best in World Cup showdown

Team India is just one step away from attaining the glory that has evaded them in their entire cricketing history. As they prepare to take on South Africa in the final, India need to ensure that they fix the chinks in the armour to turn the World Cup dream into a reality on home soil.

New Delhi. (Agency)

India stand on the cusp of history as they prepare to take on South Africa in the final of the ICC Women's Cricket World Cup 2025. Just a fortnight ago, few would have believed they could come this close to realising their World Cup dream. Yet, the Women in Blue have silenced their critics with a jaw-dropping victory over defending champions Australia, chasing down the highest target in the history of women's ODI cricket.As India march into their third ODI World Cup final, there remain certain areas that need fine-tuning to ensure the dream is fulfilled.

The Harmanpreet Kaur-led side began their campaign with back-to-back wins over Sri Lanka and Pakistan. However, both victories were far from perfect, as the top order struggled against spin and suffered early collapses. On both occasions, it was the lower order that came to the rescue, guiding the team to competitive totals. Against Sri Lanka, a massive partnership between Deepti Sharma and Amanjot Kaur steadied the innings, while a similar effort from the lower order salvaged the situation against Pakistan.As the tournament progressed, India's batting prowess finally came to the fore, with Smriti Mandhana rediscovering her golden touch and plundering runs at the top of the order. She was ably supported by Pratika Rawal, whose promising campaign ended prematurely due to an unfortunate ankle injury.Stay updated for complete coverage of Women's World Cup 2025 with India Today! Get full schedule, team squads, live score, and the updated ICC women's world cup points table.The Indian batting line-up unleashed its full potential on the grand stage of the semi-final, making light work of the mammoth target set by Australia and chasing it down with nine balls to spare. Despite the clinical victory, a few areas of concern still linger for the Harmanpreet Kaur-led side.

Fielding Frailties

India's fielding was below par throughout the first innings, as they conceded several easy

boundaries and even dropped a catch offered by Australia's captain, Alyssa Healy. Although Healy was dismissed soon after for 5 (15), such lapses could prove costly on another day.The fielding effort lacked the intensity befitting a semi-final. The Australians capitalised on India's sluggishness, frequently turning singles into doubles. The lack of urgency in the field arguably gifted Australia an extra 20–30 runs. Come the grand final, the Women in Blue cannot afford similar lapses as one dropped catch could shatter their World Cup dream.

Proactive Running

During their time at the crease, Indian batters were occasionally guilty of poor communication, creating unnecessary run-out opportunities for the opposition. In the midst of a game-changing partnership, a run out is the last thing a team needs, as it can alter the course of the match entirely.During the century stand between Jemimah Rodrigues and Harmanpreet Kaur against Australia, there were several moments of hesitation and miscommunication that left the batters vulnerable. India cannot afford such mistakes in the final, especially given the haunting memory of Harmanpreet Kaur's run out that led to India's exit from the 2023 T20 World Cup.

Holding Nerves on the Big Stage

In the past, India have often come agonisingly close to winning major titles, only to falter under pressure. The 2017 World Cup final remains a painful reminder: requiring just 38 runs from 44 balls with seven wickets in hand, India succumbed to nerves and suffered a heartbreaking nine-run defeat.

Max Verstappen fan Saishiva Sankaran hoping to race alongside idol in F1

New Delhi. (Agency)

When you dream of reaching the pinnacle in motorsports, it's always about being behind the wheel of a Formula One car. India has had the privilege of seeing Narain Karthikeyan and Karun Chandok represent the nation on the grid in the past, but since then, we've been waiting for the next big talent to emerge. Interest in motorsports has seen its highs and lows over the years, but every now and then, a special talent catches everyone's attention with determination and a passion for speed. One such racer is Saishiva Sankaran.

The 17-year-old is currently working his way up the ranks, competing in the Indian F4 Championship and participating in the India Racing League with the Speed Demons Delhi. He has already caught the attention of many with his accomplishments so far. Saishiva began his racing journey in karting, capturing the Pro Cadet Indikarting Championship in 2018 and following it with a podium finish at the JK Tyre Cadet Karting Championship the next year. He went on to finish as Vice Champion in the MECO FMSCI National Karting Championship, showcasing his consistency and growth.

In 2022, he continued his impressive form by earning two podiums in the Rotax National Championship (Junior category).

Transitioning into single-seaters, Saishiva made waves in the MRF 1600 National Championship, where he claimed three podium finishes and became the youngest race winner in the series.His talent has also shone on the international stage — he took first place in the X30 Cadet Novice class at the IAME Series and finished P2 in the National FLGB (1300 cc) endurance race in 2024.Further solidifying his reputation, Saishiva became the youngest pole-sitter at the 2024 Indian F4 Championship and also recorded two podiums in two races at the JK Tyre Novice Cup. In 2025, he added four podium finishes in the Indian F4 Championship and three more in the MRF National Championship, including a memorable first-place finish.

While these achievements make him a talent to watch, the 17-year-old remains grounded, saying he is just a normal kid who enjoys the simple things in life.

"I'm basically 17 years old and I'm residing in Pune. Outside the racing track, I'm just a normal kid who goes to school, comes back, and hangs out with friends, and you'll see me on my simulator most of the time of the day. Besides that, my family is not much into sports. Unlike me, my dad was the only guy who was into sports. He used to play cricket, and now I'm also taking up sports," said Saishiva to India Today in an exclusive interaction.

Shreyas Iyer discharged from Sydney hospital. Here's when he can fly home

New Delhi. (Agency)

Shreyas Iyer is recovering steadily from his spleen injury and has been discharged from a hospital in Sydney, the Indian Cricket Board confirmed on Saturday, November 1. The middle-order batter, who was undergoing treatment for a laceration on his spleen, will remain in Sydney for follow-up consultations before returning to India once he is declared fit to fly.The BCCI expressed gratitude to Dr. Kourosh Haghigi and his team in Sydney, along with Dr. Dinshaw Pardiwala in India, for ensuring that Iyer received the best possible medical care. The board also confirmed that the cricketer had undergone a minor surgical procedure to repair the laceration on his spleen.BCCI's Official Statement on Shreyas Iyer

"Shreyas Iyer sustained a blunt injury to his abdomen while fielding during the third ODI against Australia on October 25, 2025, resulting in a laceration of his spleen with internal

bleeding. The injury was promptly identified, and the bleeding was immediately arrested following a minor procedure. He has undergone appropriate medical management for the same," the BCCI said in an official statement."He is now stable and recovering well. The BCCI Medical Team, along with specialists in Sydney and India, are pleased with his progress, and he has been discharged from the hospital today," the statement added.The board further noted its appreciation for the medical professionals involved in Iyer's treatment, saying, "The BCCI extends its heartfelt appreciation to Dr. Kourosh Haghighi and his team in Sydney, along with Dr. Dinshaw Pardiwala in India, for ensuring Shreyas received the best possible care for his injury."India captain Suryakumar Yadav had earlier updated on Shreyas' condition. He has said that the batter had been doing well and was replying to the texts sent by his teammates.hreyas Iyer Injury: How it HappenedIyer suffered the injury during the third ODI against Australia while attempting a challenging catch to dismiss

Rishabh Pant ready for Test return after frustrating foot fracture

New Delhi. (Agency)

Rishabh Pant is set to make his long-awaited comeback to international cricket. The dynamic wicketkeeper-batter, who has been out of action since suffering a foot fracture in England, has confirmed that he has now fully recovered from the injury that kept him sidelined for months.

Pant sustained the injury during the Manchester Test match in England. While attempting a reverse sweep against Chris Woakes, he accidentally edged the ball onto his right foot, fracturing it in the process. True to his resilient nature, Pant returned to the crease to continue his innings after

initially retiring hurt, demonstrating once again the determination and courage that define his game.Since that Test match, which took place between July 23 and 27, Pant had been unavailable for selection until this week, when he finally returned to competitive cricket. He featured in the unofficial Test match against South Africa A at the BCCI Centre of Excellence in Bengaluru, marking his first outing after months of rehabilitation.Speaking on the sidelines of the match, Pant opened up about his recovery journey and expressed relief over how smoothly his healing process went."The first part of the process was healing. For the first six weeks, you have to let the fracture heal properly and then report to the CoE. Thankfully, the healing went well," Pant said in a BCCI video."I started my rehab gradually. In the early days, there was a lot of physiotherapy and careful monitoring. Once I regained some mobility, I began focusing on building strength, which marked the start of the second phase. Right now, I'm happy to say that I'm fully recovered, and I owe a big thanks to the CoE staff for helping me through it," he added.

Turning trolls into believers: Indian women's team makes people dream again

New Delhi. (Agency)

When the Women's World Cup began, I wasn't sure what to expect. I hadn't followed women's cricket as closely as I had the men's game – it had always lingered at the edges of my attention, But as the tournament unfolded, it became impossible to ignore.India, as hosts, carried both expectation and promise. They were among the favourites, and rightly so. Still, everyone knew Australia stood a class apart - a team with batting depth, all-round strength, and a champion's aura.Watching them took me back to the first Women's World Cup I had seen, when India had made a surprising run to the final. Back then, there was buzz about a young Harmanpreet Kaur, Mithali Raj's calm leadership, and Jhulan Goswami's brilliance with the ball. Yet, somehow, it hadn't fully registered how special that era was. Perhaps men's cricket simply occupied too much of the spotlight for me to truly notice.Then came the moment that changed everything - the one that turned many of us

into believers. India stunned Australia, powered by Harmanpreet Kaur's unforgettable 171, a knock that would go down as one of the greatest in World Cup history. The team marched into the final, and for a brief, electric stretch, the entire nation was behind them. But the dream ended in heartbreak - agonisingly short of glory.I was in my first job then, and I remember the sting of that defeat lingering for a day or two before life, and the news cycle, moved on. The women's team, though, kept pushing forward - growing in stature, earning respect, and chipping away at the barriers that once kept them in the shadows. But that one defining, crowning moment still eluded them.

Eight years later, I found myself covering a Women's World Cup for the first time. The rhythm of the game felt different - a little slower than the men's version, perhaps - but it had its own kind of charm. There was skill, competitiveness, and above all, a sense of purpose that was impossible to miss.India's campaign began on an uncertain footing. Even in their wins against Sri Lanka and Pakistan, cracks were visible. The team's balance seemed off – the sixth bowling option sacrificed for batting depth, and the core batters, Smriti Mandhana, Harmanpreet Kaur, and Pratika Rawal, struggled to find rhythm.

Women's World Cup final ticket fiasco: Frustrated fans hit out at BCCI

Women's World Cup: The India vs South Africa final is on Sunday, November 2. However, the tickets for the match are yet to go live. Frustrated fans have hit out at the BCCI over logistical issues.

New Delhi. (Agency)

The Indian women's cricket team may be gearing up to play the final of the Women's World Cup within the next 24 hours, but fans are still waiting for tickets to go on sale. The continued delay has sparked widespread frustration and anger among supporters, who have taken to social media to express their disappointment over what they describe as poor planning and mismanagement.

BookMyShow, the official ticketing partner for the ICC Women's ODI World Cup, has

yet to release tickets for the much-anticipated final match. Prices for the tickets have started from Rs. 100 throughout the tournament, making them accessible to a wide audience. However, with the clock ticking down to the championship clash, fans remain in the dark about when they will be able to secure their seats.Social media platforms have been flooded with complaints directed at both the Indian Cricket Board and the International Cricket Council (ICC), with fans questioning how such a major event could face logistical issues so close to the final.This is not the first time cricket enthusiasts have encountered such confusion. A similar situation unfolded during the Men's ODI World Cup in 2023, when tickets for several matches were released at the last minute, leaving fans scrambling to make arrangements.As demand for the final's ticket is expected to be historic after India's incredible victory in the semi-final of the tournament. The Indian women's team chased down a record target of 339 runs against defending champions Australia to reach the summit clash of the tournament. India are going to play South Africa in the final of the competition, a clash that is expected to be a very close on.

South Africa had beaten India in the group-stage of the tournament, in a nervy clash in Vizag. But with the Indian team playing their best match in the semi-final, the momentum definitely seems to be with the co-hosts of the tournament.Aanticipation builds for the Women's World Cup final, the delay in ticket availability has once again raised concerns about event management and fan engagement in cricket, especially in major international tournaments.

Yami Gautam

Confirms Haq Faces No Censorship Cuts In UAE: 'Agar Waha Koi Problem Nahi Hai...'

Actor Yami Gautam has clarified that her upcoming courtroom drama Haq — inspired by the historic Shah Bano Begum case — has not faced any censorship cuts in the United Arab Emirates. In a recent interview, Yami revealed that the film has received a 15-plus age classification, ensuring that a wider audience in the region will be able to watch it without restrictions.Slated for theatrical release on November 7, Haq features an ensemble cast that includes Emraan Hashmi, Sheeba Chaddha, and Vartika Singh, alongside Yami in the lead role. The film, directed by Suparn Varma, is produced by Junglee Pictures in association with Insomnia Films and Baweja Studios.

"The Film Isn't Here To Offend Anyone"

Speaking to Times Now, Yami Gautam explained that Haq presents its subject matter with sensitivity, aiming to highlight a social and legal landmark rather than provoke religious sentiment. "This is the first time I'm sharing that in terms of censorship in the UAE, there are no cuts — it is 15 plus, meaning it's watchable for all. Toh agar waha koi problem nahi hai (If there's no problem there), that means this film is not here to antagonise anyone from any faith," she said.The uncut release in the UAE indicates that local authorities deemed the film's content appropriate for public viewing, a significant indicator given its potentially sensitive themes.

Yami further emphasized that Haq was never intended to target any religion or community. "You are not making a film about one community," she stated, adding, "It is difficult to give bigger evidence than this, without even watching the film."

Based On The Shah Bano Case

Haq draws inspiration from the 1985 Supreme Court verdict in the Mohd. Ahmed Khan vs Shah Bano Begum case — a ruling that upheld a Muslim woman's right to maintenance under Indian law. The film adapts journalist Jigna Vora's book Bano: Bharat Ki Beti and dramatizes the legal, emotional, and societal turmoil that surrounded the case.

Yami essays the role of Shazia Bano, a woman who takes on the legal system to fight for justice, while Emraan Hashmi portrays her husband, Lawyer Abbas Khan. Director Suparn Varma has described Haq as a powerful story about faith, equality, and courage — themes that remain as relevant today as they were four decades ago.

A Film That Sparks Conversation

The film's advance publicity has spotlighted its historical grounding and its smooth international certification process. The absence of censorship cuts, especially in the UAE, has generated optimism about its balanced treatment of a controversial subject.With Haq, Yami Gautam appears ready to add yet another compelling performance to her filmography — one that not only explores gender and justice but also encourages meaningful dialogue around India's socio-legal evolution.

Bhoomi Shetty To Star In Prasanth Varma's Mahakali, Details Inside

Mahakali, the upcoming fantasy mythological drama, is making all the right noises. It is one of the next instalments in the Prasanth Varma Cinematic Universe (PVCU) after the Teja Sajja starrer HanuMan. Recently, the makers announced Kannada actress Bhoomi Shetty as the female lead of the film.As fans await to see Bhoomi in this new avatar, let's take a look at the actress's filmography and her personal life.

Who Is Bhoomi Shetty?

Born in Karnataka, Bhoomi began her acting career with dailysoap Ninne Belladatta. She also finished fourth on Bigg Boss Kannada 7.The actress made her big screen debut with the 2021 film Ikkat, alongside Nagabhushana. Following her debut, she appeared in Telugu films like Chaitanya Rao Madadi's Sharathulu Varthisthai and Vijay Deverakonda's action drama, Kingdom.

Bhoomi Shetty In Mahakali

On Thursday, the makers of Mahakali dropped Bhoomi's first-look poster from the film, sending her fans into a frenzy.

It features the actess in the Goddess Kali avatar; her face is painted black and her eyes show a serious expression.Sharing the post, filmmaker Prasanth Varma wrote on X, "From the cosmic womb of creation awakens the most FEROCIOUS SUPERHERO of the universe! Introducing #BhoomiShetty as MAHA #Mahakali."

The shooting for Mahakali is currently going on in full swing. It is expected to hit the big screens next year.Apart from this, another project under Prasanth Varma's Cinematic Universe (PVCU) includes Jai Hanuman, a sequel to Teja Sajja's HanuMan, which will feature Rishab Shetty playing the Hindu deity.

Rakhi Sawant Schools Paparazzi On Camera Angles: 'Do These Angles Look Good?'

Rakhi Sawant asked the paparazzi to adjust their camera angle, but the way she said it left everyone in splits.

Rakhi Sawant is back in town and once again making headlines with her hilarious public antics. Known for her unfiltered opinions and quirky gestures, Rakhi recently returned to India from Dubai, and since then, several videos of her have been circulating online.Now, another clip of Rakhi has caught fans' attention, in which she delivers a hilarious line during a media interaction. She asked the paparazzi to adjust their camera angle, but the way she said it left everyone, including the attendees and her fans, in splits.

Rakhi Sawant's Reaction To Paparazzi's Camera Angle

In the video, Rakhi Sawant is seen sporting a bold and glamorous look. She wore a deep emerald green satin outfit, featuring plunging neckline and lacy details. Her look was completed with tan heeled boots and stockings. Her voluminous curly red hair and gorgeous makeup added to her signature over-the-top charm.But what caught everyone's attention is not a dramatic look but the way she prompted photographers to try a different angle. While posing for the pictures, she said, "Camera taango ke niche kyu hai? Upar karo." Listening to this paprazzi burst into laughter before Rakhi asked, "Nhi matlab ye angle acche lag rage hain?" To which they responded with a laugh, "Nahi nahi, bilkul nahi."

("Why is the camera under my legs? Raise it up. No, I mean, do these angles look good?" To which they replied, laughing, "No, no, not at all!")

Rakhi Reacts to Comparisons With Urvashi Rautela

A few days ago, during a media interaction to promote her new song Zaroorat, Rakhi made a grand appearance in a dazzling lehenga choli paired with heavy jewellery, which she claimed was worth a whopping Rs 70 crore.

Taking a sharp jab at Bollywood actress Urvashi Rautela, she quipped, "Main jhooth nahi bolti Urvashi Rautela ki tarah."When reporters asked if she considered Urvashi Rautela her competition, Rakhi appeared visibly annoyed and sharply responded to the question, saying, "Aapka kya dimaag ghutne mein hai kya? Aap meri tulna Britney Spears, Jennifer Lopez, Shakira, Paris Hilton aur Kim Kardashian se karen. Aapko ghisapita bas ek hi naam mil jaata hai. Please, I know her song was Abidi Dabidi, but it became Dabidi Dabidi."

Isha Malviya

Brings High Energy To New Music Video Nazraan Utaar

Isha Malviya shared a lively and glamorous dance reel on Instagram to announce the release of her latest song, Nazraan Utaar, on October 31. With her signature confidence, she teased fans in the caption: "WARNING: This glam might break your feed. 'Nazraan Utaar' is OUT NOW. Hit play if you can handle the heat."The video shows Isha grooving alongside Simran Choudhary and Anmol Daniel, all three showing off some impressive moves and stunning outfits. Their chemistry and stylish energy stood out right away, making the reel a big hit. Within hours, it crossed thousands of views, with fans flooding the comments section to praise Isha's charm, confidence, and effortless stage presence.

Fans React With Excitement

The response to Isha's post was full of excitement and love from her followers. One fan commented, "Instagram kholte hi Isha ka song aa jata h," while another added, "You are looking fab." Many described her performance as "Superb" and "Amazing." Some couldn't get enough of her style, calling her reel "full of glamour and confidence."

These short, heartfelt comments showed how much people enjoyed watching her perform. Fans also praised her ability to mix fashion and dance so naturally, saying that she always brings a spark of freshness to everything she does. The buzz around the reel proved just how popular Isha remains among her online audience.

Rising Star: Isha Malviya's TV and Social Media Journey

Before becoming a social media favourite, Isha Malviya began her career as a model and then stepped into television. She played Jasmine Kaur Sandhu in Udaariyaan (2021). Her strong acting, bold personality and expressive screen presence made her a standout in

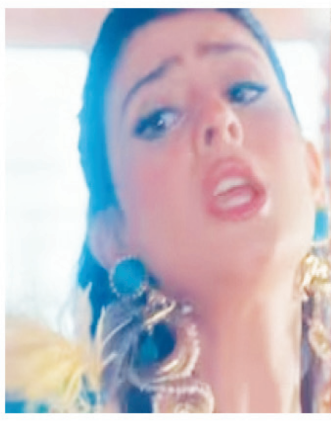

the show.

Outside TV, Isha has built a strong following online with over 3.5 million Instagram followers. She regularly posts dance reels, fashion looks, and fun glimpses from her shoots, many of which go viral. She has also appeared in several music videos and collaborated with top brands. With her blend of talent, style, and confidence, Isha continues to grow as one of the most promising young stars in entertainment, admired not just for her looks but for her energy and authenticity.